छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025

(फाल्गुन 13, शक सम्वत् 1946)

[अंक 06]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025

(फाल्गुन 13, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपकी फिटनेश कैसी है?

नेता प्रपितक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- बढ़िया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि आजकल कांग्रेस वाले राजनीति में कम ध्यान दे रहे हैं, क्रिकेट टीम की फिटनेश में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- क्या आपको कुश्ती लड़नी है?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी फिटनेश तो ठीक है न ?

डॉ. चरणदास मंहत :- ठीक है। अभी नेताम जी मेरे को कुछ बोल रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आजकल क्रिकेट टीम की फिटनेश में कांग्रेस पार्टी चिन्तित है तो हम आपकी फिटनेश में चिंतित हैं। ठीक है न।

डॉ. चरणदास महंत :- आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-1 श्री सुशांत शुक्ला जी।

बेलतरा विधान सभा क्षेत्र में राशनकार्डों में परिवर्तन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (*क्र. 1018) श्री सुशांत शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी, 2025 तक कितने APL राशन कार्डधारियों को BPL राशनकार्ड जारी किया गया तथा क्यों ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के BPL राशन कार्ड में परिवर्तन हेतु हितग्राही के किस पहचान पत्र का उपयोग किया गया तथा इस हेतु संबंधित हितग्राही से सहमति/आवेदन प्राप्त किया गया? यदि नहीं तो

क्यों? **(ग)** प्रश्नांश "क" के परिवर्तित BPL राशनकार्ड बनाने में किन-किन अधिकारियों की जवाबदेही थी ? क्या इस कार्य में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी 2025 तक एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः इस कार्य हेतु जवाबदेही संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता। एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल में परिवर्तित करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अपितु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में जिला प्रशासन एवं राज्य स्तरीय जांच दल द्वारा जांच में एपीएल कार्ड को बीपीएल में परिवर्तित किया जाना नहीं पाया गया।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज का प्रश्न खाद्य विभाग के प्रश्न क्रमांक 1018 से उत्तरित होता है, माननीय मंत्री के विभाग का उत्तर सदन के माध्यम से मिला है। बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी, 2025 तक कितने A.P.L. राशन कार्ड B.P.L. राशन कार्ड में परिवर्तित हुए ? जिसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी 2025 तक A.P.L. राशन कार्ड को B.P.L. राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है। जबकि मेरे पास जो तथ्य हैं, 57 राशन कार्ड ऐसे हैं जो बगैर दस्तावेजी प्रमाणीकरण के A.P.L. से B.P.L. राशन कार्ड में परिवर्तित किये गये। हद तो तब हो जाती है कि बंगलाधारी और डॉक्टर्स के राशन कार्ड पिछली सरकारों में A.P.L. से B.P.L. राशन कार्ड में परिवर्तित किये गये। मेरा विषय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधा-सीधा है कि वर्तमान समय में जिनके आई.डी. नंबर से यह जो कार्ड परिवर्तित किये गये, उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है, अगर कार्रवाई की गई है तो क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, A.P.L. से B.P.L. राशन कार्ड में परिवर्तित नहीं किया गया है। यह जो माननीय विधायक जी बता रहे हैं, यह पहले A.P.L. राशन कार्ड को निरस्त करने के लिए आवेदन किये हैं, उसके बाद फिर पात्रतानुसार उन लोगों को B.P.L. राशन कार्ड बनाया गया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित विभाग ने माननीय मंत्री जी के माध्यम से सदन को गुमराह करने की व्यवस्था बनाई है। मेरे पास 57 कार्ड ऐसे हैं, जो सक्षम और आर्थिक तौर पर संपन्न लोग हैं और उन लोगों के द्वारा कोई आवेदन कभी नहीं दिया गया है। जो A.P.L. से B.P.L. राशन कार्ड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसमें श्रमिक कार्ड लगता है जो श्रमिक कार्ड कभी बना ही नहीं और उनके राशन कार्ड बनाये गये। मैं आपके

माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि पूर्ववर्ती सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अन्य योजना थी उसमें 5 किलो अतिरिक्त चावल का जो आवंटन होना था, उस पूरी प्रक्रिया में बिलासपुर की 170 राशन दुकानों में प्रति दुकान लगभग 50 राशन कार्ड अतिरिक्त A.P.L. से B.P.L. राशन कार्ड बनाये गये और व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। मैं आज आपके माध्यम से आई.डी. नंबर भी उल्लेखित करना चाहता हूं जिस आई.डी. नंबर से ये राशन कार्ड बने। स्पष्ट रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से भी उल्लेखित है कि मध्यप्रदेश के सागर में ये आई.डी. नंबर खोले गये और वहां से 1300 राशन कार्ड डिलीट किये गये, जब ये विषय उठा। राशन कार्ड वर्ष 2022 में बने और वर्ष 2024 में इसकी शिकायत हुई। शिकायत करने के बाद वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 1300 राशन कार्ड डिलीट किये गये। बेलतरा विधान सभा की दृष्टि से आज जो जवाब दिया जा रहा है, बेलतरा विधान सभा बिल्हा विकासखंड और नगर निगम बिलासपुर के अधीन आती है। दोनों लोकल बाडी की कोई भी दस्तावेजी प्रमाणीकरण इन राशन कार्डों के साथ संलग्न नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि क्या संबंधित दोषी अधिकारियों को कार्य से पृथक करके मेरे समक्ष जांच करायेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, A.P.L. से B.P.L. राशन कार्ड में परिवर्तित किये जाने की बात कह रहे हैं, एक भी राशन कार्ड बता दें जिसमें A.P.L. और B.P.L. राशन कार्ड के नंबर समान हों, अगर ऐसे कार्ड मिलते हैं तो मैं उसके ऊपर जांच कराकर के कठोर कार्रवाई कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप कुछ बता दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उद्धृत हुआ है, उसका जवाब नहीं आया है। मैंने कहा कि संबंधित अधिकारी, जिस अधिकारी ने पूरा कांड किया, अगर उसी के माध्यम से जांच होगी तो जांच नहीं हो पायेगी। मैं चाहता हूं कि क्या उसको कार्य से पृथक करके संबंधित विषय पर जांच देंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्ड निरस्त किया गया है या उसकी आई.डी. की बात बता रहे हैं, ऐसा अगर कुछ भी साक्ष्य है, अगर उनके पास कुछ भी कागज है।

अध्यक्ष महोदय :- किसी दूसरे अधिकारी से करा लीजिये ।

श्री दयालदास बघेल :- हां, दूसरे अधिकारी से मैं जांच करा लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक जी के समक्ष जांच करा दूंगा ।

श्री सुशांत शुक्ला :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप बैठ जाईये । और कोई प्रश्न हो ? प्रश्न क्रमांक-02, इंद्र कुमार साहू जी ।

प्रश्न क्रमांक - 02 XX XX

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में किसानों से धान खरीदी में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 798) श्री इंद्र साव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में धान खरीदी हेतु कुल कितने पंजीकृत कृषक हैं? पंजीकृत कृषकों में से कितने कृषकों का कुल कितना धान 14 नवंबर, 2024 से लेकर जनवरी, 2025 तक खरीदी की गई है ? धान खरीदी के एवज में उक्त कृषकों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश ''क'' अवधि में जिले के धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी में अनियमितता एवं बारदाना की कमी, अमानक बारदाना, सूखत के नाम पर ज्यादा मात्रा में धान तौलने एवं रकबा शून्य संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई एवं कितनी लंबित हैं ? **(ग)** क्या सरकार की घोषणा अनुसार प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों से 3100 रू. कि दर से धान की खरीदी एवं राशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं तो अंतर की कितनी राशि का भुगतान किसानों को कब तक किया जायेगा ? समय सीमा बताएं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में धान खरीदी हेतु कुल 1.67 लाख कृषक पंजीकृत हैं। पंजीकृत कृषकों में से 1.60 लाख कृषकों से कुल 8.55 लाख मे.टन धान 14 नवंबर, 2024 से लेकर 31 जनवरी, 2025 तक खरीदी किया गया है। धान खरीदी के एवज में उक्त कृषकों को भुगतान हेतु 1966.94 करोड़ रुपये की राशि अपेक्स बैंक को अंतरित किया गया है। विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[1] अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अवधि में जिले के धान खरीदी केन्द्रों में 13 शिकायतें प्राप्त हुई थी, प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की प्रकरणवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** जी हां, प्रदेश में उपार्जित धान का दिनांक 20.02.2025 की स्थिति में 25.46 लाख किसानों को समर्थन मूल्य की राशि 34,317 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। कृषक उन्नति योजना अंतर्गत रूपये 3,100 प्रति क्विंटल से समर्थन मूल्य की अंतर की राशि रूपये 16,800 प्रति एकड़ के मान से 25.47 लाख किसानों को 11,920 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।

श्री इंद्र साव: - माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के संबंध में मेरा माननीय खाद्य मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार ने धान खरीदी के नाम पर बहुत सारे वायदे किए और अपनी पीठ भी थपथपा ली । यह तो हमारे लिये गौरव की बात है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत की

[1] परिशिष्ट "दो"

थी और किसान खुशहाल थे लेकिन आज वर्तमान में किसानों के साथ जो दुर्दशा हुई है, खरीदी में जो अनियमितता की गयी, जो अव्यवस्था देखी गई वह किसी से छिपी नहीं है और मेरा प्रश्न यह है कि हमारे बलौदाबाज़ार-भाटापारा जिला में कितने पंजीकृत कृषक हैं और पंजीकृत कृषक से कितनी धान की खरीदी की गई और कितनी उनको राशि दी गई ? इस प्रश्न का जवाब तो आ चुका है, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष महंत जी हमारे भाटापारा विधानसभा के ग्राम तरेंगा के संग्रहण केंद्र में स्वयं गए थे और वहां उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि आमानक बारदाना जो वहां उपयोग में लाया गया और आज माननीय मंत्री जी के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वह सभी जो बारदाना उपयोग किया गया वह मानक पाया गया करके तो मेरा प्रश्न यही है कि इसमें जूट उद्योग को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के वहां जाकर के जो उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया था और उनकी जो बातें जो वहां के प्रभारी को अर्थात् जो तथ्य सामने लाया गया था, उन्होंने स्वीकार भी किया था कि बारदाने अमानक हैं और हमारे यहां सदन में भी मीडिया के साथियों के सामने में नाप-तौल करके भी देखा गया था कि 470 ग्राम-480 ग्राम बारदाना पाया गया उसके बाद भी ऐसी कौन सी जांच रिपोर्ट किस अधिकारी के द्वारा किया गया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उस जांच का विवरण उपलब्ध कराएंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न ध्यानाकर्षण में आ चुका है और इसमें पूरी चर्चा की जा चुकी है फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि धान खरीदी केंद्र तरेंगा विपणन संघ द्वारा प्रदाय नया जूट बारदाना अमानक बारदाना होने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच की गयी है । माननीय महोदय द्वारा बिना नमी के जांच कर बारदाने का वज़न किया गया जिसमें 480 ग्राम होना बताया गया है जबकि नमी ज्ञात कर निर्धारित गणना सूत्र अनुसार वज़न किए जाने पर बारदाने का औसत वज़न 578 से 590 ग्राम तक पाया गया । जूट बारदानों का मानक वज़न नमी प्रतिशत की गणना के आधार पर 545 ग्राम से 626 ग्राम तक होता है इस प्रकार बारदाना निर्धारित गुणवत्ता का होना पाया गया है, इस प्रकार शिकायत निराधार पाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, निराधार है । बोलिए और कोई प्रश्न ?

श्री इंद्र साव: - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा ऐसा जवाब प्रस्तुत करना यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और जब सामने हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वहां जाकर के प्रभारी से मिले, प्रभारी द्वारा स्वीकार भी किया गया कि यह अमानक बारदाना था उसके बाद मंत्री जी द्वारा ऐसा जवाब प्रस्तुत करना बहुत ही [xx][2] बात है इस सदन के लिए और मैं चाहता हूं कि ऐसी पुनरावृति भविष्य में नहीं होनी चाहिए ।

[2] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भाषा जो है बहुत आपत्तिजनक है। [xx] [3] बात है, मंत्री जी के उत्तर को यह कहना घोर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और इसको डिलीट करवाएं और मैं तो यह कहता हूं कि वह खेद व्यक्त करें । जो उत्तर दिया गया है उससे असहमत हैं तो दूसरी प्रक्रिया में आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, विलोपित कर देंगे । आप छोटा सा प्रश्न कर लीजिए ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नये सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है। कोई बात नहीं। विलोपित हो गया। एकाध प्रश्न और करना है तो कर लीजिये।

श्री इंद्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उस बारदाना के मानक होने का जिस अधिकारी ने भी जांच की है, उसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करवा दीजिए।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तरेंगा सोसाइटी में माननीय नेता जी के द्वारा बारदाना का जो वजन किया गया था, उसमें नमी नहीं जोड़ा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने नमी सहित जांच कराया तो जो बारदाना है, वह सही पाया गया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सर, इसी बात से संबंधित मेरा प्रश्न है। मैं स्वयं वहां उपस्थित था। मैंने उस बारदाने का नाप-तौल कराया। वहां की समिति के जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि सर, ये थोड़ा कम है। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी कंपनी का, कौन सा बरदाना है और सरेआम इस तरह से या तो मैं कहूं कि मुझे झूठा साबित किया जा रहा है या सदन को गुमराह करने की बात जैसे श्री सुशांत शुक्ला ने किया, उसी तरीके से बार-बार इनके विभाग में सदन को गुमराह करने की बात आती है। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता। मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आप विधायकों की समिति बनाकर इसकी जांच कराना पसंद करेंगे? इस तरह से कितनी बार विधायक, नेता प्रतिपक्ष या मंत्री लोग आपकी सदन में झूठे कहलाये, सर, ये तो आपको देखना है । मैं आपसे चाहता हूं कि आप सदस्यों की एक समिति बना दें, जांच कर लें। हमें कोई यह बात दिखाना नहीं है कि मंत्री ने गलत जवाब दिया या आपके अधिकारियों ने गलत जवाब दिया। इस तरह से बात इन्हीं के विभाग में ज्यादा आ रहा है। तो सदन को गुमराह करने की इनकी जो मंशा है, इनके अधिकारियों की मंशा है, उसको ठीक से एक बार सदन के जो अधिकार हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए, विधायकों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक सदन की समिति बना दें। अभी वहां बोरा रखा हुआ है, वहां फिर जाकर जांच कर लेंगे। कोई नई बात तो है ही नहीं। जैसे वे खुद ही कह रहे हैं कि 545 से

[3] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

626 ग्राम तक का उसका वजन होता है और मैंने उस दिन नापा तो 480 ग्राम था। कितनी नमी जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, क्या करेंगे, ये तो अलग बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जो जांच प्रतिवेदन है, वह प्रस्तुत कर दें न। माननीय नेता प्रतिपक्ष की मांग है कि आपने जो जांच करायी थी और विभाग से एक बार और जांच करा लें, मान लें इनको शंका है तो विभाग से जांच करा लें। क्या दिक्कत है?

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां सदन को गुमराह किया जा रहा है। जो अधिकारी लोग गए होंगे तो प्रतिवेदन तो उन्हीं लोगों ने दिया है । विधायकों की उपस्थिति में हो जाये। उन्हीं के क्षेत्रों के दो तीन विधेयकों को ले जाएं। उनसे भी जांच करा लें, उसमें क्या दिक्कत है?

श्री दयालदास बघेल :- नहीं, हमने जांच कराया है, उसका प्रतिवेदन भी है। प्रतिवेदन यही आया है। उसकी जो नमी है, उसके सहित तौलोगे तो बराबर है।

अध्यक्ष महोदय :- तो प्रस्तुत करवा दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- ठीक है ।

धान खरीदी के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहित करने व परिवहन में जब्ती की कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (*क्र. 1005) श्री बघेल लखेश्वर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में धान खरीदी वर्ष 2024-25 के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहित कर रखने व परिवहन करते समय कहां-कहां व कितने क्विंटल धान की जब्ती की गई ? कृपया बतावें? **(ख)** इन जब्ती प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में धान खरीदी वर्ष 2024-25 के दौरान अवैध रुप से धान संग्रहण एवं परिवहन के निर्मित प्रकरणों में 7117.67 क्विंटल धान जब्ती की गई। स्थानवार जब्ती की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** †[4]अनुसार है।**(ख)** जब्ती के प्रकरणों पर कि गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

श्री बघेल लखेश्वर :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न धान खरीदी के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहण एवं परिवहन से जब्त की गई कार्रवाई से संबंधित था। माननीय मंत्री जी से जब्त की गई सभी जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन धान खरीदी के संबंध में मेरा ये कहना है कि धान खरीदी में भारी घोटाला हो रहा है। उसको सरकार नहीं समझ रही है, न कोई समझ रहा है। हमारे खासकर बस्तर में इस

[4] †परिशिष्ट "तीन"

साल वर्षा कम हुई। लेकिन उत्पादन ज्यादा हुआ। कैसा हुआ, उसके संबंध में चिंता करने के लिए जरूरत है। अवैध रूप से परिवहन करते जो इतना धान पकड़ा गया। तो एक तो ये चिंता का विषय है कि क्यों ऐसा क्यों अवैध रूप से धान आ रहा है? हमारे यहां प्रति एकड़ 21 क्विंटल उत्पादन हो रहा है तो बाहर से आने की क्या जरूरत है? जब्त करने की क्या जरूरत है? किसान के मामले में ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। 21 क्विंटल खरीदी के संबंध में हमारी पूर्ववर्ती सरकार के संबंध में माननीय हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री जी ने उस समय कमेंट्स किया था। चैलेंज भी किया था कि 21 क्विंटल उत्पादन होता ही नहीं है तो खरीदी कैसे हो रही है ? (श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की ओर इशारा करते हुए) आपकी ओर इशारा है मेरा । फिर भी इतनी धान खरीदी कैसे हो रही है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- लखेश्वर जी, मैंने जो मांग की थी उसको सुधार देता हूं। जितना उत्पादन आपने दिखाया है उससे ज्यादा खरीद रहे हैं या तो आप गलत खरीद रहे हैं या उत्पादन की मात्रा को सुधरवा लीजिए कहा था, आपने नहीं सुधरवाया।

श्री लखेश्वर बघेल :- अभी सुधारने की जरूरत है । हम लोग नहीं सुधार पाए, सुधारने के लिए आप आए हैं ना । मंत्री जी, इसमें चिंता करने की जरूरत है कि ऐसा कैसे हो रहा है ? अध्यक्ष महोदय, मैं धान की जप्ती के संबंध में कुछ पूरक प्रश्न करना चाहूंगा । क्या धान परिवहन करते हुए जप्त किया गया या घरों से किया गया?

अध्यक्ष महोदय :- कहां से जप्त किया गया, घर से या परिवहन करते समय?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, 7117.67 क्विंटल धान जप्त हुआ है। यह धान कोचिया के पास जप्त किया गया, जैसे कि उसके पास ज्यादा मात्रा में पाया गया, अवैध परिवहन करते हुए पाया गया, जिनसे जप्त किया गया है, उन पर कार्यवाही की गई है । ये हमारे जांच दल के द्वारा पकड़ा गया है । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पकड़ा गया है । जितने का लायसेंस है यदि तौल में उससे ज्यादा मिलता है तो जप्त किया जाता है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- यह जो कार्यवाही है, इसकी कोई समय सीमा है कि कब तक कार्यवाही हो जाएगी ? आपने जो राशि वसूल की है उसके लिए भी कोई मापदंड है क्या, कि कितने क्विंटल में कितनी राशि वसूल की जानी चाहिए । आपने 15 क्विंटल में 2660 रूपया वसूल किया । फिर 8 क्विंटल के लिए 3312 रूपए और 36 क्विंटल के लिए 16790 रूपए वसूले । इसका कोई मापदंड है क्या कि इतने क्विंटल जप्ती पर इतनी राशि का अर्थदंड लगाया जाएगा ? कोई मापदंड बताइए ।

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह जो धान जप्त हुआ है, उस पर राजीनामा करके राशि वसूल की गई है । इसमें मंडी अधिनियम के तहत् कार्यवाई की गई है, इसमें राजीनामा करके राशि वसूल की जाती है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- समय सीमा बता दीजिए, कब तक जांच हो जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय :- समय सीमा बता दीजिए, जांच कब तक पूरी करेंगे ?

श्री लखेश्वर बघेल :- उसका निराकरण कब तक कराएंगे, यह बता दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- कार्यवाही और निराकरण कब तक कर लेंगे?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, 156 प्रकरण थे, जिनमें से 61 प्रकरणों का निराकरण हो गया है । 95 निराकृत नहीं हुए हैं, बहुत जल्द इनका निराकरण करवा लेंगे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इसी संबंध में और कहना था । मेरा विधान सभा क्षेत्र ओडिशा सीमा से लगा हुआ है । बहुत भारी मात्रा में ओडिशा से धान आया, जिस तरह से प्रशासन से कार्यवाही होनी थी, वह भी नहीं हो पाई, आप इसको भी नोट करियेगा ताकि आने वाले समय में ऐसा न हो । मंडी का 50 परसेंट धान लैम्पस में गया है । उत्पादन हुआ ही नहीं तो धान कहां से आएगा ? मंडी से लेकर ही तो किसान देगा । इसमें शासन को चिंता करने की जरूरत है और हमारे किसानों ने शिकायत की थी कि छोटेगिराकाल का मामला है, उस किसान के पास पांच एकड़ जमीन है लेकिन उसके पास कम से कम 1200 क्विंटल धान था । प्रशासन की ओर से एसडीएम गए, खाद्य विभाग के लोग गए, जप्ती की गई, सब कुछ किया लेकिन जिसमे पास धान था उसने सारा धान लैम्पस में किसानों को दे दिया । लेकिन उसमें भी आप लोग कहते हैं कि मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । उसके पास धान है ही नहीं तो आप लोग क्या प्रक्रिया करेंगे, उसने तो सारा धान दे दिया । उस समय संबंधित एस.डी.एम. को भी बताया गया कि किसानों को ऐसी-ऐसी परेशानी है लेकिन छोड़िए न, यह हमारा विषय है, हम कार्रवाई करे या न करें, इस तरह से प्रशासन का जवाब आता है तो प्रशासन से कुछ व्यवस्था सुधारने की क्या आशा करोगे ? इस तरह से खुलेआम बात हुई है। मैं तो आरोप लगाऊंगा कि इस समय शासन के संरक्षण में धान खरीदी हुई है और अवैध रूप से हुई है। इतनी मात्रा में हुआ। (शेम-शेम की आवाज) आपको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, वाहवाही करने की जरूरत नहीं है। शासन के संरक्षण में अवैध धान खरीदी हुई है।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल हमारी सरकार ने बम्फर धान खरीदी की है।, उसका भुगतान भी कर दिया गया है। चेकपोस्ट के माध्यम से 7117 क्विंटल धान भी जब्त की गई है और इसमें कार्रवाई भी की है।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई हुई है लेकिन जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उतना नहीं हो पाया, मेरे कहने का मतलब यह है। हम लोग शिकायत करते हैं लेकिन अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोगों को प्रश्न नहीं करना पड़ेगा ? आपको कितनी जगह बताएं। उधर सुनवाई नहीं होती है, कलेक्टर सुनते नहीं हैं, न प्रशासन सुनते हैं। लेकिन हम इस सदन में कम से कम आवाज बुलंद करें, कम से कम छत्तीसगढ़ के लोग जाने। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप व्यवस्था सुधारियेगा। अगर पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है तो धान खरीदी में घोटाला हो रहा है। आप अनावरी

रिपोर्ट को देख लीजिएगा, शुरू में 12, 7, 10 क्विंटल की खरीदी हुई, अचानक आपकी अनावरी रिपोर्ट कैसे बढ़ गया, 12 क्विंटल से 21 क्विंटल आ गया। शुरू में 12 क्विंटल धान खरीदी हुई। उसके बाद 12 क्विंटल से 21 क्विंटल कैसे हुआ ? यह चिंता करने का विषय है, मेरी और कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए आप चिंता कर लीजिए। आपका सुझाव ठीक है।

श्री दयालदास बघेल :- जी, ठीक है।

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी, आप इसको दिखवाईएगा, आने वाले समय में ऐसा न हो। लेकिन मैंने आज जो बताया कि एस.डी.एम. का जिस प्रकार का कार्य है, क्या आप उस एस.डी.एम. के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? एम.डी.एम. ने जिस प्रकार से व्यवहार किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, उन्होंने धान भी जब्त नहीं की है।

श्री दयालदास बघेल :- अगर आप बता दे, लिखकर दे देंगे ...।

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी, बताना नहीं है, बकावंड का एस.डी.एम. है। यह मेरा विधान सभा क्षेत्र है। अगर सही में कार्रवाई करना है तो करिएगा। इस मामले में बहुत घोटाला हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री उमेश पटेल जी।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- जी, धान खरीदी में है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत सुंदर जवाब आ गया है, आप संतुष्ट नहीं हैं। चलिए नहीं हैं तो पूछ लीजिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- नहीं सर, संतुष्ट नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का टोकन कटता है, प्रबंधक टोकन कांटता है, तहसीलदार, एस.डी.एम. की जांच कमेटी बनती है, जांच कमेटी किसान के घर से जांच करके जाता है, फिर धान लाने की अनुमति मिलती है, उसके बाद जब किसान धान केन्द्र पर धान लेकर आता है तो वहां पर किसानों की धान जब्त क्यों की जाती है ? जब एस.डी.एम. घर में गया, सबकुछ जांच हुआ, उसके बाद उसके धान को जब्त कर ली जाती है। आपका धान पाखड़ है करके जब्त कर लेते हैं। वही प्रबंधक किसान के धान को सेटलमेंट करके कम कीमत में 20 रूपये किलो में धान खरीदता है। ऐसा क्यों हुआ ? मेरे यहां रायगढ़ जिले की समिति केन्द्रों से बहुत सारी शिकायतें आई है। मंत्री जी इसका जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रकरण है, बस्तर जिला का है।

अध्यक्ष महोदय :- रायगढ़ पहुंच गये।

श्री दयालदास बघेल :- आपका प्रकरण रायगढ़ का है लेकिन जो भी है, बता दीजिए, मैं उसको दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- पाखड़ में मिले धान को बेच दिए, आप इनकी शिकायत को दिखवा लीजिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, भविष्य में इस तरह से अनियमितता न हो, किसान कड़ी मेहनत करके धान की फसल करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दीजिए, मंत्री जी उसकी जांच करा लेंगे।

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं जांच करवा लूंगा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- उमेश जी।

प्रदेश में महतारी वंदन योजना अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

5. (*क्र. 411) श्री उमेश पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- प्रदेश में महतारी वंदन योजना में प्रथम पंजीयन के समय कितने हितग्राही थे तथा प्रश्नांकित अवधि तक कितने हितग्राही पंजीकृत हैं, जिलेवार, ब्लॉकवार जानकारी देवें। क्या वर्तमान समय में हितग्राहियों की संख्या में कमी आई है ? यदि हां तो क्यों ? यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या महतारी वंदन योजना में फर्जी नाम से लाभ लेने का मामला प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो कहां-कहां फर्जी नाम से लाभ लेने के प्रकरण संज्ञान में आये है? क्या पात्रता हेतु विभागीय सत्यापन का कोई नियम है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : प्रदेश में महतारी वंदन योजना में प्रथम पंजीयन (20.02.2024 तक) कुल 7027154 हितग्राही द्वारा आवेदन किया गया था। अद्यतन स्थिति में कुल पंजीकृत आवेदको में से 6963621 हितग्राही पात्र है। विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ[5] एवं प्रपत्र-ब अनुसारहै।** जी हाँ, कमी आई है, यह कमी हितग्राहियों की मृत्यु होने, लाभ त्याग करने, दो आवेदन के प्रकरण तथा अपात्र होने आदि कारणों से आई है। जी हाँ, अद्यतन स्थिति में फर्जी नाम से लाभ प्राप्त करने का 01 मामला बस्तर जिले से प्राप्त हुआ है। जी हाँ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि शुरू में हितग्राहियों के जो आवेदन प्राप्त हुए थे, आज की स्थिति में उससे कम लोग हैं। उन्होंने इसमें कारण भी

[5] परिशिष्ट "चार"

बताएं हैं। आपने जांच कराया होगा, उसके बाद नाम कटते गये होंगे। आपने कितनी बार जांच कराई है, कब-कब कराए हैं और हर बार जांच कराने पर कितने लोग कटे हैं ? उसकी जानकारी दे दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने महतारी वंदन योजना के संबंध में जो जानकारी चाही है, उसमें हमने इनको जानकारी दी है कि प्रदेश में कुल 7027154 हितग्राहियों ने आवेदन भरे हैं। इसमें जो कमी आई है, उसका कारण यह है कि इस बीच में काफी लोगों की मृत्यु हो गई है व कुछ लोगों ने लाभ त्याग कर दिया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर तो आपने मुझे लिखकर दे दिया है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने इस संबंध में कब-कब जांच कराई है ? आप मुझे इसकी जानकारी दे दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि जांच समय-समय पर होती रहती है। हर महीने, हर दिन जांच होती रहती है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हर दिन जांच होती है। आपने विभाग से इसकी जांच कराई होगी तो आपने जब भी इसकी जांच कराई है, उसकी डेट व हितग्राहियों की संख्या में कितनी कमी हुई है, उसकी आप मुझे जानकारी दे दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जांच की डेट उपलब्ध करा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को जांच की डेट उपलब्ध करा दूंगी।

श्री उमेश पटेल :- चलिये, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों ने लाभ त्याग कर दिया व कुछ लोग अपात्र निकलें। एक मामला बस्तर जिले से प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी और का नाम था। जब यह मामला आपके संज्ञान में आया तो क्या आपने इसकी जांच कराई कि कहीं पूरे प्रदेश में इस तरह के और प्रकरण तो नहीं हैं ? यदि आपने इसकी जांच कराई है तो कम से कम आप मुझे उसकी जानकारी दे दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह सत्य है। बस्तर जिले के एक गांव में यह समस्या आई है। फर्जी नाम से किसी व्यक्ति के माध्यम से पैसे लिये जा रहे थे तो इस संबंध में कार्यकर्ता के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई है और अधिकारियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहा हूं। यह मामला आपके संज्ञान में आ गया।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इसी बात को बता रही हूं कि जब वह विषय हमारे सामने आया तो हमने विभाग में निर्देशित किया और विभाग में निर्देशित करने के बाद हमें यह पता चला कि अभी ऐसा एक भी विषय नहीं है, जिसमें इस तरह से फर्जी नाम से किसी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसकी जांच कब कराई ? यदि आप इसकी जांच कराएंगे तो कैसे कराएंगे ? आप तो सारे डेटा को वेरिफाई करेंगे। यदि आपने विभाग में निर्देश दिया होगा तो उसकी कोई तारीख होगी, जिसमें विभाग ने एक-एक हितग्राहियों के नाम की जांच की होगी। आप मुझे इसकी जानकारी दे दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यही बात तो मैं बार-बार कह रही हूं कि समय-समय पर जांच होती रहती है।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अध्यक्ष महोदय, विभाग ने इसकी जांच नहीं की है। यह मामला इनके संज्ञान में आने के बाद भी कि कोई हीरो-हीरोइन के नाम से भी पैसे निकाले जा रहे हैं और यह घटना घटित होने के भी इसमें जांच नहीं हुई है। (शेम-शेम की आवाज) मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही को क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महतारी वंदन योजना के हितग्राही के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले वह आयकरदाता न हो, वह वर्ग-एक, दो, तीन न हो, इसमें पात्रता श्रेणी के लिए वह हितग्राही 21 वर्ष से अधिक की हो अर्थात् उससे कम की न हो और विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्तता महिला भी इसके लिए पात्र होती है तथा उनको भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो पात्रता की सीमा यही है, जो मैं समझा हूं कि वह 21 वर्ष से ऊपर आयु की हो, शादीशुदा हो, परित्यक्ता और विधवा हो सकती है, साथ ही आयकर दाता न हो। ठीक है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने घोषणा-पत्र में सिर्फ आयकर दाता की बात कही थी, उसमें और किसी तरह के क्रायटेरिया की बात नहीं थी। तो आपने अपने घोषणा-पत्र के बाहर जाकर यह criteria क्यों रखा ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगी, कृपया आप प्रश्न को दोबारा कर दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा-पत्र में जो वादा किया था आपने तो उसको पढ़ लिया होगा ? तो यह योजना बनाते समय क्या जो घोषणा थी, उसे लेकर यह योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो इसमें अलग से criteriaको क्यों define किया गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 2023 के चुनाव में यह वादा किया था कि हम महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे और हमने 10 मार्च से प्रारंभ भी किया है। प्रथम किश्त में लगभग 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया है। (मेजों की थपथ्पाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक बात से अवगत कराना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार में इन्होंने भी वादा किया था कि हम माताओं को 5 सौ रूपये देंगे और विधवा महिलाओं को 1 हजार रूपये देंगे। लेकिन वह तो मिला ही नहीं, हमने तो इतने कम समय में महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह प्रश्न पिछले कार्यकाल का किया होता तो समझ में आता। मेरा यह प्रश्न तो इस कार्यकाल का है, छठवीं विधान सभा का है। अगर यहां का उत्तर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री लखेश्वर बघेल :- इनकी मानसिकता है कि पिछले कार्यकाल का ही बताते हैं। इनकी आदत हो गई है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग अभी भी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में चल रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- वह अभी भी 70 साल में ही अटके हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आखिरी प्रश्न कर लीजिये, बहुत हो गया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये मैं यह बात पूछता हूं, चलिये मैं इससे भी आगे बढ़ जाता हूं। इसको भी आगे नहीं बढ़ाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं। यदि आप आदेश कर रहे हैं तो आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महिलाएं 60 साल से ऊपर आयु की हैं, शादीशुदा हैं या परित्यक्ता हैं, और अगर वह महतारी वंदन योजना के हितग्राही हैं तो उनको जो पेंशन मिल रहा था, उससे वह राशि काट रहे हैं या यहां से 5 सौ रूपया कम कर रहे हैं ? दोनों में क्या सही है, यह बता दीजिये ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, उनको मिलने वाला पेंशन नहीं काटा जा रहा है, उनको अंतर की राशि दी जा रही है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतर की राशि, मतलब आप महतारी वंदन योजना में उनको 1 हजार रूपये नहीं दे रहे हैं ? उनको 1 हजार रूपया नहीं दे रहे हैं न ? 5 सौ रूपया दे रहे हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि अंतर की राशि दी जा रही है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां। वहीं अंतर की राशि कितनी है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच ..।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच सौ, वही तो बोल रहा हूं। आप उनको 1 हजार रूपया नहीं दे रहे हैं, उनको 5 सौ रूपया दे रहे हैं। सरकार का यह सरासर [xx] है। आपने घोषणा-पत्र में कहा था, घोषणा-पत्र में सभी महिलाओं की बात आती है। आज जो महिलाएं सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जिनको सबसे ज्यादा राशि की आवश्यकता है, अगर पूरे छत्तीसगढ़ में किसी के सेवा करने की जरूरत है तो बुजुर्ग महिलाओं की है। आप उन बुजुर्ग महिलाओं को 5 सौ रूपया काटकर दे रहे हैं, अंतर की राशि दे रहे हैं। यह तो सीधा-सीधा [xx] है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अब दे दीजिये, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। सभी महिलाओं को देने की बात कही गई थी और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है तो आप घोषणा कर दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- महिलाओं के साथ [xx] है, महिलाओं का अपमान है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने माताओं-बहनों को [xx], एक हजार रूपया तक नहीं दिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्रू :- जवाब दीजिये, मंत्री जी जवाब दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आने दीजिये।

श्री सुनील सोनी :- अपने कार्यकाल में 5 सौ रूपया तो दे नहीं सके, 1 हजार की बात करते हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पांच सौ रूपया काट रहे हैं, इसकी घोषणा करिये। आपसे यह निवेदन है कि जो आप पांच सौ रूपया काट रहे हैं, लोगों को कम राशि दे रहे हैं। यह सदन है, आज आप यहां घोषणा कर दीजिये कि 5 सौ रूपया अंतर की राशि नहीं काटी जायेगी। हम आपके लिए ताली बजायेंगे। आप बहुत सक्षम मंत्री हैं।

श्री सुनील सोनी :- 5 सौ रूपया नहीं काट रहे हैं, 1 हजार पूरा दे रहे हैं। 1 हजार रूपया देने के लिए कहा था, 1 हजार रूपया दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप उनको 15 सौ रूपया दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- आप घोषणा करिये, हम ताली बजायेंगे। आप घोषणा कर दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 5 सौ रूपया पेंशन का मिल रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2500 रूपये की बात किए थे।

श्री रामकुमार यादव :- कर देवा।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा जो बात कही जा रही है कि पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- पूर्ववर्ती सरकार में?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- आप मेरी बात सुन लीजिये। अब आप लोगों को अवगत कराना जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने पांच साल कुछ किया ही नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि आप लोग 500 रूपये नहीं दे पाये, विधवा महिलाओं को 1000 रूपये नहीं दे पाये। हम तो कम समय में बारहवीं किस्त दे चुके हैं।

श्री उमेश पटेल :- क्या आप अभी घोषणा करेंगी कि जो अंतर की राशि है उसको 500 रूपये करेंगी?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य घोषणा करने के लिए कह रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम 1000 हजार रूपये देंगे।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- आप घोषणा कीजिये न। आपने 1500 रूपये देने की बात की थी। आप सदन में घोषणा कर दीजिये। आप असत्य वादा क्यों करते हैं?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस छत्तीसगढ़ में किसी महिला को सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वह बुजुर्ग महिला को है। मंत्री जी, आपको घोषणा कर देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी 1000 रूपये कर दीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, 1000 रूपये देने की बात हुई है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- जो पेंशन मिलता है उसको आप 1500 रूपये दीजिये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
11:36 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री उमेश पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 6 के लिए श्री धरमलाल कौशिक जी के स्थान पर श्री राजेश मूणत जी को अधिकृत किया गया है। वह प्रश्न करेंगे।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

बांट माप तथा तौल उपकरणों के निर्माताओं/विक्रेताओं को प्रदत्त अनुज्ञप्तियां

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (*क्र. 777) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024 से जनवरी, 2025 तक बांट माप तथा तौल उपकरणों के किन-किन निर्माताओं, विक्रेताओं एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदाय की गई है? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** जिला रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में व्यापारिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध कब-कब, किन-किन के द्वारा क्या-क्या शिकायतें विभाग/शासन स्तर पर की गई हैं तथा इन शिकायतों पर नियमों के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जिलावार, शिकायतवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) वर्ष 2024 से जनवरी, 2025 तक बांट माप तथा तौल उपकरणों के विक्रेताओं एवं सुधारकों को कुल 20 अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई है, जिलेवार **जानकारी [6]संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है । प्रश्नांकित अवधि में बांट-माप और तौल उपकरणों हेतु निर्माताओं को अनुज्ञप्ति नहीं जारी की गई है। **(ख)** जिला रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में व्यापारिक संस्थानों एवं त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध क्रमशः 33, 19 तथा 14 कुल 66 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिलावार, शिकायतवार **जानकारी संलगन प्रपत्र 'ब'** अनुसार है।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय धरमलाल कौशिक जी के प्रश्न क्रमांक 6 पर सम्माननीय मंत्री जी के जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उस पर प्रश्न पूछना चाहूंगा। सम्माननीय मंत्री जी के पास किन-किन जिलों के कितनी शिकायतें आई हैं, जिसके अंदर जो पेकिंग किया गया सामान है, उस सामान के अंदर जो उसकी वजन दी गई है, उससे वजन कम है? ऐसी कितनी कंपनियों की शिकायतें कितनी संस्थाओं की प्राप्त हुई हैं? मैंने पूरे उत्तर में पढ़ा है कि जिन-जिन की संस्थाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों में सिर्फ एक ही प्रकरण का निराकरण किया गया और 5000 रूपये सबके ऊपर जुर्माना लगा दिया। क्या इसके Norms में सिर्फ 5000 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है? यदि उस सामान की तारीख खत्म हो गई या वह व्यक्ति उस पेकिंग के अंदर कम सामान बेच रहा है तो क्या उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का कोई नियम है, कृपया नियम स्पष्ट कर दीजिये?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिकायतें मिली हैं, उसमें 5000 रूपये जुर्माना का ही प्रावधान है। इसीलिए अधिकतर प्रकरण में सभी को 5000 रूपये तक फाईन लगाये गये हैं।

---

[6] परिशिष्ट "पाँच"

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप और कोई प्रश्न करेंगे। 5000 हजार रूपये तक ही जुर्माना का प्रावधान है। इसलिए 5000 रूपये फाईन लगाया गया है।

श्री राजेश मूणत :- धन्यवाद।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (*क्र. 1080) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 31-01-2025 तक की समर्थन मूल्य पर कुल कितने मूल्य की कितनी मात्रा में धान खरीदी की गई? जिलावार बतायें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' धान खरीदी में अनियमित (बोगस) खरीदी तथा अवैध धान की पकड़ (जब्ती) जिलावार बतायें? जब्ती धान की भौतिक स्थिति 05.02.2025 की स्थिति बतायें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 31.01.2025 तक समर्थन मूल्य पर कुल 149.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जिसका समर्थन मूल्य के मान से राशि 34348.33 करोड़ रूपये होता है। जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' धान खरीदी में अनियमित (बोगस) खरीदी तथा अवैध धान की पकड़ (जब्ती) की जिलावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** एवं **प्रपत्र-स** अनुसार है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं और कुछ सवाल भी करना चाहता हूं। चूंकि धान खरीदी का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार किसानों को धान बेचने में असुविधा हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बहुत लंबे समय बाद किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था सही हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले किसान का धान ही ऐसा था जिसका दाम व्यापारी तय करता था और अन्य वस्तुओं का दाम भी व्यापारी तय करता था। एक लंबे समय से संघर्ष करने के बाद किसानों को ऐसा अवसर मिला की सरकार की धान खरीदी की बात उनकी दाम मिलने लगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब धान खरीदी की शुरूआत हुई तो पूर्व की जो पंजीकृत किसान थे, उसके बाद ऐसे कितनी शिकायतें आई हैं, जिसमें रकबा कम कर दिया गया?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न में आपने रकबा का उल्लेख कहीं नहीं किया है, आपके पूरे प्रश्न का निष्कर्ष यही है कि खरीदी कितनी हुई, जब्ती कितना हुआ, भौतिक स्थिति क्या है ? आपके तीन प्रश्न है, मंत्री जी सही जवाब दे रहे हैं, इससे संदर्भित पूछिये ना ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :-अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूँ, जिसका उल्लेख है, मैं उसी का प्रश्न कर लेता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं माननीय मंत्री जी से धान खरीदी में अनियमितता, अवैध धान की जब्ती और उसकी भौतिक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, जहां पर जब्त किया गया है, वास्तव में वहां पर धान नहीं है, यदि है तो आप बतायेंगे और नहीं तो उसकी जांच करवायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जब्त किये धान की भौतिक स्थिति बतायें ? यदि जानकारी है तो जिले स्तर पर बता दीजिए ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में अनियमितता संबंधी जो भी शिकायत है, उसमें समिति के माध्यम से 10 जिलों में 25 प्रकरण दर्ज हुये थे । इसके तहत 6 प्रकरण में एफ.आई.आर. हुआ है, 1 सेवा से पृथक किया गया है, 3 निलंबित है, 10 कार्य से पृथक है, 5 को नोटिस जारी किया गया है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ अलग सवाल कर रहा हूँ । जो जब्त किये गये धान है, आप उसकी भौतिक स्थिति बताईये ? अध्यक्ष महोदय, वास्तव में वहां जब्तशुदा धान नहीं है, आप उसकी जांच करवायेंगे क्या ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब्त धान की भौतिक स्थिति के बारे में मात्रा सहित प्रपत्र (स) में दिया गया है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, आपके रिकार्ड में है । अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग अलग है कि आप इसकी जांच करवाईये ? रिकार्ड में जब्ती धान बताया जा रहा है, लेकिन स्थल में वह धान नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जिस मंडी में आप जब्त करके रखे हैं, वह फिर से कोचिये को वापस हो गया है । अध्यक्ष महोदय, इसमें दूसरा एक प्रश्न और है कि जब्त धान कितने को वापस किया गया है, उसमें कितना मंडी शुल्क मिला, मंडी शुल्क का मापदण्ड क्या है ? कितना शुल्क लेकर धान को वापस दिया गया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मंडी शुल्क दिया जा रहा है, मंडी शुल्क1 क्विंटल में 158 रूपया लेते हैं, जब नहीं पकड़ाता तो संबंधित कोचिया 1000 रूपया का इंकम करता है । (शेम-शेम की आवाज) मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अवैध परिवहन को रोकने के लिये कड़े से कड़े कानून बनना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, सरकार की इतनी महत्वपूर्ण धनराशि 1 क्विंटल में 31 रूपया और व्यापारी 1000 रूपये कमा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास इसके लिये कोई ठोस कानून नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशासन तीन महीने केवल यही काम में लगी है, दीवाली में कुछ लोग जुआ खेलते हैं, जुआरी भाग जाता है और देखने वाला बैठे रहता है कि मैं नहीं

खेल रहा हूँ । इसमें सेटिंग वाले कोचिया का धान नहीं पकड़ा रहा है, ये छोटे-छोटे व्यापारी आंकड़े बताने के लिये हैं ।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, यह कैसे पता है कि जुआरी भाग जाते हैं और देखने वाले वहां ...। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- हकीकत है ना ? हकीकत है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- कई बार बचे हैं । (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह हकीकत इसलिये है, वह यह सोचता है कि मैं निर्दोष हूँ । जो अवैध काम करते हैं, वह प्रशासन के सेटिंग में है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है । यहां शासन की बहुत अधिक धनराशि बिचौलियों के पास जा रही है, यह किसानों के पास जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या आप भौतिक सत्यापन की जांच करायेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- आपके पास कोई जानकारी है तो दे दीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं आंकड़े सहित दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप दे दीजिए, भौतिक सत्यापन करा लेंगे । । श्री विक्रम मंडावी जी, क्रमांक 8 ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में सिस्टम अच्छा है, जो प्रश्न आये लिखकर दीजिए, जॉच करवाईये और आगे-पीछे की जरूरत नहीं है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- इससे ज्यादा पारदर्शिता और क्या होगी ? आप मांग कर रहे हैं । मंडावी जी । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- सिस्टम अच्छा है, जो आये लिखकर दो, जॉच कराओ और आगे बढ़ो । (हंसी)

बीजापुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

8. (*क्र. 816) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बीजापुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी एवं स्वीकृत आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या विकासखण्डवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार कितने केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका पदस्थ हैं? कितने में नहीं ? संख्या बतावें? कितने भवनविहीन, कितने जर्जर भवन, कितने किराये के भवन या कितने किसी शासकीय भवन में संचालित हैं? विकासखण्डवार संख्या बतावें? **(ग)** बीजापुर जिले में नियद नेल्लानार योजना सहित किसी अन्य योजना मद से वर्ष

2024-2025 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों की संख्या कितनी है? राशि क्या है? निर्माण की भौतिक स्थिति क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :(क) बीजापुर जिले में स्वीकृत एवं संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत आ.बा.केन्द्रों की संख्या	संचालित आ.बा. केन्द्रों की संख्या
बीजापुर	234	234
उसूर	342	342
भोपालपटनम	238	237
भैरमगढ़	374	374
योग	1188	1187

(ख) बीजापुर जिले में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पद एवं भवन संबंधी विकासखण्डवार संख्यात्मक **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ** र्मित प्रकरणों में 7117.67 क्विंटल धान जब्ती की गई। स्थानवार जब्ती की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** †[7] **अनुसार है**। **(ग)** बीजापुर जिले में नियद-नेल्लानार योजना सहित किसी अन्य योजना मद में वर्ष 2024-2025 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों की संख्या 255 है। प्रति भवन 11.69 लाख रूपये स्वीकृत है। निर्माण की भौतिक स्थिति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बीजापुर जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है और कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन है और कितने आंगनबाड़ी केन्द्र किराये पर संचालित है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है, यह उत्तर में दिया हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहूँगी कि कुल 1188 आंगनबाड़ी स्वीकृत है और 1187 संचालित हैं ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 495 है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 495 बता रही हैं तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो 495 भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, वह कब तक पूर्ण हो जाएंगे ?

[7] †परिशिष्ट "छ:"

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या है, उस पर कार्यवाही चल रही है तो आने वाले समय में आंगनबाड़ी केन्द्र बनेंगे और संचालित होंगे ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने 2024-25 कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति दी है और उसमें से अभी तक कितने आंगनबाड़ी अप्रारंभ हुए हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आंगनबाड़ियों केन्द्रों की संख्या 255 हैं, इसमें 84 आंगनबाड़ी केन्द्र अप्रारंभ हैं और 171 निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, कितने आंगनबाड़ी केन्द्र अप्रारंभ हैं, वह बताईए ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- 84 आंगनबाड़ी केन्द्र अप्रारंभ हैं ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है । पिछले एक साल से स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से माननीय मंत्री जी 84 आंगनबाड़ी केन्द्र अप्रारंभ बता रही हैं । मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह आंगनबाड़ी केन्द्र कब तक पूर्ण हो जाएंगे ? वह आंगनबाड़ी केन्द्र अभी तक प्रारंभ नहीं हो रहे हैं तो उसकी क्या वजह है कि वह शुरू नहीं हो पा रहे हैं, अप्रारंभ हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- अप्रारंभ आंगनबाड़ी केन्द्र को कब तक पूर्ण करा देंगे, इसके लिए कोई कार्य योजना है क्या ?

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, वह प्रारंभ क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपूर्ण आंगनबाड़ी भवन जो निर्माणाधीन हैं, उसकी संख्या 171 है और 84 आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति अंत में मिली है । अभी चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी, उसके बाद शुरू हो जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- शीघ्र करा दीजिए ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने पूरे प्रश्न का उत्तर साफ-साफ बता दिया है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता के 10 पद और सहायिका के 20 पद रिक्त हैं तो इनकी भर्ती कब तक कर लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- शीघ्र करा लीजिए ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जी ।

महतारी वंदन योजना के हितग्राहयों को किया गया भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

9. (*क्र. 1078) डॉ. चरण दास महंत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महतारी वंदन योजना के पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की संख्या माह मार्च, 2024 से जनवरी, 2025 तक बतावें? जनवरी, 2025 तक कितनी किश्तों का भुगतान हो चुका है? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु मार्च, 2024 से जनवरी, 2025 तक ऐसे पात्र हितग्राहियों की संख्या बतावें जिन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हो सका है? **(ग)** मार्च, 2024 से जनवरी, 2025 तक कितने मृतक हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की गई ? **(घ)** महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को कितनी किश्तों के भुगतान में कितनी बार मद परिवर्तन के माध्यम से राशि की व्यवस्था की गई? कौन से मद की कितनी राशि मद परिवर्तन कर हितग्राहियों की किस्तों का भुगतान किया गया?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) महतारी वंदन योजना के पात्र, अपात्र एवं मृत हुए हितग्राहियों की प्रश्नाधीन अवधि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र[8] अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि जनवरी 2025 तक कुल 11 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। **(ख)** प्रतिमाह समस्त पात्र हितग्राहियों को भुगतान अनुमोदित किया जाकर भुगतान की कार्यवाही की जाती है, किंतु आधार संबंधी एवं बैंक खाते संबंधी तकनीकी कारणों से कतिपय हितग्राहियों के भुगतान असफल हो जाते है। मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक ऐसे पात्र हितग्राही, जिनका भुगतान असफल हुआ है, की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 6 पर उल्लेखित है। **(ग)** माह मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 24194 हितग्राहियों के मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है, जिन्हें भुगतान सूची से हटाया गया है। मृत हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित नहीं की जा रही है। **(घ)** महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को निर्धारित बजट प्रावधान योजना शीर्ष 7048 से ही राशि आहरित कर भुगतान किया गया है, मद परिवर्तन नहीं किया गया है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि उमेश जी ने माननीय मंत्री जी से ज्यादा प्रश्न पूछकर परेशान कर दिया है । मैं बहुत सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं और मंत्री जी से अपेक्षा है कि इसका जवाब देंगी ।

श्री राजेश मूणत :- नेता जी, क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं कि आप भी यहां बैठते थे, वे मंत्री थे । अगर उस समय यह सब कर दिए होते तो वहां बैठने की स्थिति तो नहीं बनती ।

डॉ. चरण दास महंत :- मगर आप इधर से उधर कैसे पहुंए गए ?

श्री विक्रम मण्डावी :- राजेश भैया, आप कब तक मंत्री बन रहे हैं, वह बता दीजिए ।

[8] परिशिष्ट "सात"

श्री राजेश मूणत :- 2047 तक । (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि मार्च, 2024 से जनवरी, 2025 तक कुल 24194 हितग्राहियों के मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे भुगतान की सूची से हटाया है । आप ज्यादा परेशान मत होईए । आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि किसी हितग्राही की मृत्यु हो गई, यह जानकारी शासन को कैसे प्राप्त होती है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जानना चाहा है कि हितग्राहियों की मृत्यु होने पर शासन को कैसे जानकारी प्राप्त होती है ? मैं बताना चाहती हूं कि इसके दो, तीन विषय हैं । पहला-उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी जानकारी ली जाती है । एक पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं । दूसरा, ऑनलाईन पोर्टल है, उसमें मृत हितग्राही के घर के व्यक्ति आवेदन करते हैं कि हमारे घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है। इस तरह से शासन को जानकारी होती है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, जब तक कागज न आ जाये । हितग्राही जो मर गया, वह अपनी जानकारी तो दे नहीं सकता कि मैं मर गया और न तो उसके घर वाले जानकारी देंगे, क्योंकि आप एक हजार रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं। तो क्या आपके पटवारी का प्रतिवेदन आता है या तहसीलदार के पास आता है, फिर कलेक्टर के पास आता है? शासन को कैसे पहुंचता है और शासन तक पहुंचने में कितने महीने का समय लग जाता है और उतने महीने तक आप हितग्राही को जो पैसा देते हैं, वह कहां जाता है या उसे आप वापस लेते हैं?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकर्ता के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम हितग्राहियों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से पैसा देने वाले होते हैं, उससे पहले जांच होती है कि कितनी मृत्यु दर आई हुई है, कितने लोगों का खाता लॉक हो गया है। मतलब कई प्रकार की समस्यायें होती हैं, तो ऐसे जानकारी प्राप्त होती है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सरल प्रश्न है, मैं परेशान नहीं कर रहा हूं। मृत्यु होने के कितने महीने बाद तक उसकी मृत्यु की सूचना शासन तक पहुंचती है? आप इतना बता दें।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि एक महीने का समय रहता है, आंकड़े में तो नहीं बता पाऊंगी लेकिन अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में हर दिन काफी सारी मृत्यु होती हैं। प्रतिदिन कोई न कोई आवेदन आते हैं और खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे ही किसी हितग्राही की मृत्यु होती है, तो तत्काल अवगत कराएं, ताकि विभाग से जो पैसा जाता है, वहॉ से उनका खाता लॉक करके पैसा न जाए, इसके लिए यही प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। चलिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न है। बस, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, हो गया। समय कम है, दिलीप जी को पूछने दीजिए। आप बैठिए।

धान के उपार्जन एवं उसके निराकरण में शासन को हुई क्षति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

10. (*क्र. 1073) श्री दिलीप लहरिया: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- धान के उपार्जन एवं उसके निराकरण में कृषि विपणन सीजन 2021-22 से 2023-24 तक शासन को हुई वर्षवार क्षति (वास्तविक अथवा अनुमानित) की जानकारी दी जाये? क्या इस क्षति के नियंत्रण की कोई कार्ययोजना है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : धान के उपार्जन एवं उसके निराकरण में कृषि विपणन सीजन 2021-22 के अंतिम दर निर्धारण हेतु दावा पत्रक भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। कृषि विपणन सीजन 2022-23 के अंतिम दर निर्धारण हेतु दावा पत्रक तैयार किया जा रहा है। कृषि विपणन सीजन 2023-24 में उपार्जित धान के सी.एम.आर. जमा किये जाने की कार्यवाही जारी है, अतः कृषि विपणन सीजन 2021-22 से 2023-24 तक भारत सरकार से अंतिम दर निर्धारण उपरांत हानि की जानकारी ज्ञात हो सकेगी।

श्री दिलीप लहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय।

(माइक चालू नहीं होने पर)

श्री अजय चन्द्राकर:- तोर माइक ह त गाना च नई गावथे। (हंसी) बिना माइक के गाना गा तें।

श्री दिलीप लहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, होली आ रही है। (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धान के उपार्जन एवं उसके निराकरण में कृषि विपणन सीजन 2021-22 से 2023-24 तक शासन को हुई वर्षवार क्षति (वास्तविक अथवा अनुमानित) की जानकारी कब तक आनी है और क्या इसके लिए कोई ठोस नियंत्रण एवं नियम हैं?

श्री दयालदास बघेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य वर्ष 2021-22 के वास्तविक क्षति के संबंध में पूछ रहे हैं, तो ये केन्द्र सरकार से वास्तविक व्यय होता है। हम लोग यहां से वास्तविक व्यय का लागत पत्रक भेजते हैं, तो वहां से निर्णय होता है। अभी वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 का भी नहीं आया है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यही ज्ञान और गति है? पिछला वर्ष जो बीत चुका, उसका नहीं आया है और वर्ष 2021-22 का भी नहीं आया है, तो क्या यह गति है या दुर्गति

है? मेरे हिसाब से यह दुर्गति है। ये जल्द आना चाहिए, किसानों के हित में होना चाहिए। इनका उत्तर आने के बाद कम से कम एक समय निर्धारित हो कि चार महीने, छ: महीने में आए, क्योंकि वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं आया और वर्ष 2021-22 बीत जाने के बाद उसके तीसरे वर्ष भी नहीं आ रहा है, तो क्या इसके लिए आप समय निर्धारित करने, पत्र-व्यवहार करेंगे या ठोस पहल करेंगे?

श्री दयालदास बघेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक क्षति का आंकलन नहीं किया जा सकता, फाईनल भारत सरकार से होता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेरा इसी में एक और प्रश्न है। मेरे मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में अभी-अभी एक घटना हुई है। वहां मलहार सहकारी सेवा समिति में जो पूर्व में प्रबंधक थे, वह इसी तरह के 2 करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे और वह जेल के अंदर भी थे। आपकी सरकार आने के बाद उसी प्रबंधक को पुन: प्रबंधक बना दिया गया (शेम-शेम की आवाज) और जब वहां जांच समिति बैठी तो पता चला कि इसमें 7 हजार क्विंटल धान की अफरा-तफरी हुई और जब आपके ही अधिकारी जांच में गये तो वहां जांच में यह पाया गया कि बोरी में रेत और भूंसी डाल दिया गया था। (शेम-शेम की आवाज) यह खबर मीडिया और पेपर में आयी थी। क्या आपके द्वारा उसे जानबूझकर फिर से प्रबंधक के पद पर बैठाया गया ताकि वह फिर से भ्रष्टाचार करें ? उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज भी हो चुकी है, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग इस तरह के मुद्दों को थोड़ा-सा देख लिया कीजिए। वह एक माननीय मंत्री जी का नाम भी ले रहा था कि मैं इनके संपर्क में हूं और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और 7 हजार क्विंटल में रेत और भूंसी को डालकर अफता-तफरी कर रहा था। आपके ही अधिकारियों की जांच में यह प्रत्यक्ष रूप से पाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह तो घोर आपत्तिजनक है।

प्रश्न संख्या 11 :- XX XX

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, उनका उत्तर तो आने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- यह उनका प्रश्न नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह कौन से मंत्री जी का नाम ले रहे थे ?

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा। वह प्रबंधक एक ही मंत्री का नाम ले रहे थे।

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में प्रशासनिक व्यय मद की राशि तथा उसका उपयोग

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

12. (*क्र. 1084) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कास्टशीट में प्रशासनिक व्यय मद में किन-किन दरों से राशि का प्रावधान है? **(ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में प्रशासनिक मद में विहित दर से पात्र राशि कितनी-कितनी होती है? इसमें से कितनी-कितनी राशि का व्यय हुआ तथा शेष राशि का क्या किया गया? **(ग)** प्रशासनिक व्यय की राशि का उपयोग किन-किन प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है? क्या इस मद की राशि का वितरण धान उपार्जन करने वाली सहकारी सोसाइटियों को किया जाता है? यदि हां तो कितना और किस लिए?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष **2024-25** के लिए जारी कास्ट शीट में प्रशासनिक मद में विहित दर धान (कॉमन) के लिए रू. **23.00** प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए के लिए रू. **23.20** प्रति क्विंटल है। **(ख)** खरीफ विपणन वर्ष **2018-19** से **2023-24** की अवधि में प्रशासनिक मद में विहित दर से पात्र राशि, व्यय तथा शेष राशि की जानकारी निम्नानुसार है-

(राशि करोड़ में)

खरीफ वर्ष	**प्रशासकीय व्यय अंतर्गत विहित दर अनुसार अधिकतम प्राप्ति योग्य राशि**	**व्यय राशि**	**रिमार्क**
2018-19	87.77	180.34	-
2019-20	110.57	199.25	-
2020-21	245.34	290.93	भारत सरकार से अंतिम लागत पत्रक जारी नहीं हुआ है
2021-22	329.08	229.20	भारत सरकार से अंतिम लागत पत्रक जारी नहीं हुआ है
2022-23	220.30	आडिट कार्य प्रक्रियाधीन है।	
2023-24	317.81	आडिट कार्य संपादित होना शेष है।	

शेष राशि की स्वीकृति हेतु अंतिम लागत पत्रक को पुनरीक्षित करने हेतु भारत शासन को लेख किया गया है। **(ग)** भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय व्यय मद में प्रावधान अनुसार अनाज खरीद में प्रशासनिक शुल्क उन खर्चों को संदर्भित करते हैं जो सरकार या उन एजेंसियों द्वारा उठाए जाते हैं जो अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन और निगरानी करती हैं। प्रशासकीय व्यय की राशि का वितरण धान उपार्जन करने वाली सहकारी सोसायटी को नहीं किया जाता है, इन समितियों को अन्य मदों (यथा कमीशन, मंडी लेबर चार्ज आदि) अंतर्गत राशि प्रदाय की जाती है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा मेरे प्रश्न का जो लिखित उत्तर दिया गया है, वह अपूर्ण है। उत्तर के भाग (क) में बताया गया है कि प्रशासनिक मद में विहित दर धान (कॉमन) के लिए रू. **23.00** प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड "ए" के लिए रू. **23.20** प्रति क्विंटल है। माननीय मंत्री जी ने जो दर बतायी है, वह समर्थन मूल्य की 1 प्रतिशत की दर से है। यह 1 प्रतिशत की दर केवल उस धान पर लागू है, जिसका चावल राज्य पुल के लिये उपार्जित होता है। हम अतिशेष धान का चावल केंद्रीय पुल में एफ.सी.आई. को देते हैं। उस चावल के लिये प्रशासनिक व्यय की दर समर्थन मूल्य का ढाई प्रतिशत है। मैं फिर भी माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि कास्ट शीट में प्रशासनिक व्यय मद में विहित दर से प्राप्त राशि कितनी है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक बार पुन: प्रश्न कर दीजिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का विभाग द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह अपूर्ण है। विभाग द्वारा जो लिखित उत्तर दिया गया है, उस उत्तर के भाग (क) में बताया गया है कि प्रशासनिक मद में विहित दर धान (कॉमन) के लिए रू. **23.00** प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड "ए" के लिए रू. **23.20** प्रति क्विंटल है। माननीय मंत्री जी ने जो दर बतायी है, वह समर्थन मूल्य की 1 प्रतिशत की दर से है। यह 1 प्रतिशत की दर केवल उस धान पर लागू है, जिसका चावल राज्य पुल में उपार्जित होता है। हम अतिशेष धान का चावल केंद्रीय पुल में एफ.सी.आई. को देते हैं। उस चावल के लिये प्रशासनिक व्यय की दर का समर्थन मूल्य क्या है ? मैंने माननीय मंत्री जी से यही पूछा है कि कास्ट शीट में प्रशासनिक व्यय मद में विहित दर से प्राप्त राशि कितनी है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कास्ट शीट में प्रशासनिक व्यय की विहित दर 1 प्रतिशत होती है, जिसे माननीय सदस्या ने स्वयं बताया है। धान खरीदी के प्रशासनिक व्यय से आशय यह है कि वितरण संघ का धान खरीदी से संबंधित कार्यालयीन व्यय जैसे संग्रहण केंद्रों में श्रमिक का, कम्प्यूटर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर, धान खरीदी। इस प्रकार का व्यय आता है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने व्यय बता दिया। आपको और कोई प्रश्न करना है ?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी की मेरे पास भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2020 को जारी कास्ट शीट की प्रति है,

जिसमें राज्य पुल के चावल के लिये 1 प्रतिशत और केंद्रीय पुल के चावल के लिये ढाई प्रतिशत की दर निर्धारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि त्रुटि सुधार कर पुनरीक्षित उत्तर दिया जाये। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय मंत्री जी ने आपका सुझाव मान लिया।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आप लिखित में मंगवा लीजिये। मंत्री जी, पूरा उत्तर दे दीजियेगा।

वन स्टॉप सेंटर की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

13. (*क्र. 419) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी अंतर्गत कहां-कहां एवं कब-कब से किसके द्वारा वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं? संचालित सेंटर्स में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं? सेंटरों में कार्यरत् कर्मचारियों को वेतन/मानदेय का भुगतान किस आधार पर किया जा रहा हैं? भोजन व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं की सम्पूर्ण जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :जिला राजनांदगांव में बल्देवबाग, दैनिक दावा कार्यालय के समीप राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में मार्च 2017 से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी में सखी वन स्टॉप सेंटर वर्तमान में संचालित नहीं है, संचालन हेतु स्वीकृति जारी की गयी है एवं संचालन हेतु सेवाप्रदाताओं के चयन की एवं अन्य कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिला राजनांदगांव के सखी वन स्टॉप सेंटर में पीड़िताओं को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं विधिक सलाह एवं परामर्श, आपातकालीन आश्रय, चिकित्सकीय सहायता एवं पुलिस सहायता उपलब्ध करायी गयी है। सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत सेवाप्रदाताओं को, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश एवं अधिकतम व्यय सीमा के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दर पर सेवा शुल्क प्रदाय किया जा रहा है। भोजन व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं की **जानकारी प्रपत्र पर संलग्न[9] है।**

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिए मेरा सीधा-सीधा एक छोटा-सा सवाल है। प्रश्न आपके पास है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

[9] परिशिष्ट "आठ"

समय

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

विश्वविद्यालयों के प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023- 2024 (01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024)

(ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का साठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023- 2024 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024)

(iii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2023-2024

(iv) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024)

(v) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा

(vi) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023- 2024 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024)

पटल पर रखता हूँ।

समय

12.01 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) नगर पालिक निगम दुर्ग में निर्मित व्यावसायिक परिसरों का आवंटन नहीं किया जाना।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर):- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नगर पालिक निगम दुर्ग में निर्मित व्यावसायिक परिसरों का आवंटन नहीं किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ। हम सब जनप्रतिनिधि लोग, विधायक हों, सांसद हों । हम लगातार अपने क्षेत्र, निगम, पंचायतों के लिए...।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना ध्यानाकर्षण पूरा पढ़ दीजिए। जो आपने ध्यानाकर्षण दिया है उसको एक बार पढ़ दीजिए फिर उसके बाद माननीय उपमुख्य मंत्री जी का जवाब आएगा।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पढ़ना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

दुर्ग जिले के नगर पालिक दुर्ग अंतर्गत बहुत से व्यवसायिक परिसरों का निर्माण किया गया है, जिसको आज दिनांक तक न ही आवंटित किया गया है न ही विक्रय किए जाने की कार्यवाही की गई है। पूर्व निर्मित सभी व्यवसायिक परिसरों की स्थिति बहुत खराब हो गई है कुछ व्यवसायिक परिसरों की भवन तो इतनी जर्जर हो गई है कि उसको ध्वस्त किए जाने की स्थिति निर्मित है। उसी प्रकार नवीन निर्मित व्यवसायिक परिसरों की स्थिति बिना उपयोग किए जर्जर होते जा रही है। आम जनता एवं व्यापारीगणों द्वारा निरंतर इन व्यवसायिक परिसरों को आवंटित किए जाने की मांग की गयी है, परंतु निगम के अधिकारियों द्वारा उसे आवंटित किए जाने हेतु वर्तमान स्थिति तक कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है। इन सभी व्यावसायिक परिसरों को निर्माण कर ऐसे ही छोड़ दिया गया है जिससे राज्य शासन की करोड़ों रूपये की राशि का दुरूप्रयोग है, जिससे आम जनता एवं व्यापारीगणों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग) श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिक दुर्ग अंतर्गत कुल 24 व्यवसायिक परिसरों का निर्माण किया गया है। जिनमें कुल 1709 दुकानें बनाई गई हैं, इनमें 1581 दुकानों का आवंटन निकाय द्वारा पूर्ण करा लिया गया है तथा 128 दुकानें वर्तमान में रिक्त हैं। 04 व्यवसायिक परिसरों के 04 दुकानों का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा नेशनल उपभोक्ता फोरम में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण आवंटन शेष है। 107 दुकानों हेतु निविदा प्रक्रिया जारी है। 01 व्यवसायिक परिसर में 02 दुकानों में प्रीमियम राशि जमा कराई गयी, आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष दो परिसर की 15 दुकानों के लिए निविदाकारों के द्वारा निविदा में भाग नहीं लेने के कारण आवंटन शेष है।

रिक्त दुकानों के आवंटन हेतु नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बने अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 एवं विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ8-3/2022/18 दिनांक 17/05/2022 के तहत लगातार निविदा की कार्यवाही की जा रही है। गंजमण्डी व्यवसायिक परिसर एवं जलगृह कॉम्पलेक्स हेतु ग्यारह बार निविदा आमंत्रित की गई है।

रिक्त 128 दुकानों में से 107 दुकानों के लिए निविदा प्रकिया जारी है। गंज मण्डी व्यावसायिक परिसर में 58 एवं जलगृह कॉम्पलेक्स में 33, वाई-शेप ओव्हर ब्रिज के नीचे 03 दुकान आईएचएसडीपी 10 दुकान स्थित है। 03 दुकान (रायपुर नाका व्यावसायिक परिसर तथा गौरव कॉम्पलेक्स) की निविदा प्रक्रिया प्रस्तावित है। उपरोक्त सभी दुकान अच्छी स्थिति में हैं। कुछ दुकानों का टूट-फूट एवं प्लास्टर खराब हुई है जो मरम्मत योग्य है। अत: यह कहना सही नहीं है कि पूर्व में निर्मित सभी व्यावसायिक परिसरों की स्थिति बहुत खराब है तथा जर्जर होने के कारण ध्वस्त किये जाने की स्थिति है। यह कहना भी सही नहीं है कि सभी व्यावसायिक परिसरों को निर्माण कर छोड़ दिया गया है तथा शासन की करोड़ों

रुपये की राशि का दुरूपयोग हो गया है। दुकानों के आवंटन हेतु प्रक्रिया जारी है। अत: आमजनों एवं व्यापारियों में कोई रोष नहीं है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने नगरपालिक निगम दुर्ग की दुकानो के बारे में सविस्तार से बताया है। इसमें मेरा मूल प्रश्न यह है कि गंज मण्डी व्यावसायिक परिसर एवं जलगृह कॉम्पलेक्स के बारे में मेरी चिंता है। पिछली सरकार में 20 करोड़ रुपये की राशि से यह दो कॉम्पलेक्स बनाये गये हैं और आपने बताया है कि गंज मण्डी व्यावसायिक परिसर एवं जलगृह कॉम्पलेक्स हेतु ग्यारह बार निविदा आमंत्रित की गई है, कोई भी निविदाकार नहीं आया। इसमें जानकारी दी गई है कि मण्डी व्यावसायिक परिसर में 58 एवं जलगृह कॉम्पलेक्स में 33 दुकान है, जबकि जलगृह कॉम्पलेक्स में कुल 74 दुकानें हैं। ऐसा लगता है कि जानकारी देने में गलती हो गई है। अभी तक 94 दुकानें नहीं बिकी हैं। चूंकि यह मेरी विधान सभा का स्थानीय मामला है, उसका कारण है कि बाजार दर के हिसाब से जो कलेक्टर दर गाईडलाईन थी, उस गाईडलाईन के हिसाब से भूमि की दर और निर्माण की दर को एक साथ लेकर रेट निर्धारित किया गया, जो वर्तमान बाजार का प्रचलन मूल्य है, उससे ज्यादा उन दुकानों का रेट आया। दूसरा वह लीज में था और लीज में होने के कारण लोगों को हर साल का 2 प्रतिशत किरायानामा भी जुड़ता है। बाजार में जो दर पर सामान्य दुकान मिलेगी, उसकी तुलना में नगर निगम की दुकानें मंहगी मिलने लगी, इस कारण से निविदा में किसी निविदाकार ने भाग नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें शासन का 20 करोड़ रुपये लग चुका है और 11 बार निविदा हो चुकी है और उस बिल्डिंग को निर्माण हुए आज 7 साल से ज्यादा हो गये हैं और कोई निविदाकार नहीं आया है। वह खड़ी बिल्डिंग बिना किसी पक्षकार के नहीं लेने से खराब होती जा रही है। उस बिल्डिंग से सरकार को कोई प्रकार का पैसा नहीं मिल रहा है। इस काम के लिए, उस काम के लिए हम नगर निगमों में लगातार आप से ही मांग करते हैं, लेकिन नगर निगमों की पेमेंट देने की भी स्थिति नहीं रहती है। आपने यह जो व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण किया है, नगर निगम के हित में एक बड़ा काम हो सकता है। एक दुकान की न्यूनतम कीमत 35 लाख रुपये है। मेरा यह निवेदन है कि जो हमारी कंस्ट्रकशन कॉस्ट है, उसमें जितनी रुपये की कंस्ट्रक्शन की लागत आई है, उसको छोड़कर कलेक्टर गाईडलाईन के द्वारा जो बाजार दर से जमीन का मूल्यांकन किया है, उसमें अगर आप 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत कम कर देते। चूंकि 11 बार निविदा आमंत्रित हो चुकी है। हम तो उसको आसानी से कर सकते हैं, कलेक्टर दर की गाईडलाईन में ही वह सारी दुकानें के आवंटिन की प्रकिया कलेक्टर ही करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम उस दर को यहां पर अगर कम करा दें तो हमारा कंस्ट्रक्शन का मूल्य है, अगर एक दुकान में 35 लाख रुपये मिलता है, नगर निगमों को 20 करोड़ रुपये तत्काल मिल जायेगा। यह सिर्फ मेरे दुर्ग नगर निगम की बात नहीं है, हम दुर्ग की ओर जाते हैं तो भिलाई, चरौंदा नगर निगम में भी 100 करोड़

रुपये की लागत से व्यावसायिक परिसर हैं, 25 करोड़ रुपये की लागत से पॉवर हाउस में कॉम्पलेक्स बना है। दुर्ग नगर निगम की यह जो सारी बिल्डिंग खड़ी हैं, अगर हम कलेक्टर गाईडलाईन संशोधित कर दें, अगर उसका रेट 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत कम कर दें तो मैं समझता हूं जितनी हमारी बिल्डिंग हैं, सारी बिल्डिंग नीलामी में तत्काल बिक जायेंगी। जिससे हमारे नगर निगम की आय का एक स्त्रोत जनरेट होगा, एक स्थाई पैसा आयेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि किरायानामा के रूप में जो हमको मासिक फीस मिलनी है, हमको वह भी राशि मिलेगी।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी गयी है वह सही है चाहे वह गंज मंडी व्यावसायिक परिसर से संबंधित हो, जल गृह व्यावसायिक परिसर से संबंधित हो । गंज मंडी व्यावसायिक परिसर में कुल 74 दुकानें निर्मित हैं उसमें से 16 आवंटित हो चुकी हैं और इसलिए 58 रिक्त कहा है और जल गृह व्यावसायिक परिसर में 44 दुकानें निर्मित की गई हैं जिसमें से 11 पहले से आवंटित हैं, 33 के लिए निविदा प्रक्रिया की जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नगर निगम के संपत्ति का अंतरण, संपत्ति अंतरण अधिनियम - 1994 से शासित होता है और उसमें जो नियम-प्रक्रिया दी गई है उसके हिसाब से ही उसके रेट निर्धारित हैं और यह सही है कि माननीय सदस्य ने जो कहा कि जो मार्केट रेट है वह व्यावसायिक एरिया होने के कारण से लगभग उसी के बराबर का रेट हो जा रहा है और इसलिए लोगों को शायद लगता होगा कि हम निजी व्यक्ति से उसी भाव में ले लेंगे पर इस पर क्या कर सकते हैं, क्या हम कोई रियायत दे सकते हैं ? इस पर ज़रूर विचार करेंगे ताकि इन दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि शासन अपने नियम में संशोधित तो कर सकता है । शासन से नियम संशोधित करके संबंधित कलेक्टर को जरा आवश्यक गाईड-लाईन दे दें क्योंकि पिछली बार ही मैंने तारांकित प्रश्न में इसको लगाया था, उसमें जो जानकारी आयी कि अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मुझे निरंक कार्रवाई की सूचना लिखित में दी गई है । मेरा यह निवेदन है कि अगर हम जल्दी इसमें त्वरित कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, शासन आवश्यक नयी गाईड-लाईन तैयार नहीं करेगा तो यह केवल दुर्ग की बात नहीं है, यह सारे नगर-निगम में जितने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स जो आते हैं, हम 11 बार निविदा कर चुके हैं, यदि 11 बार निविदा के बाद कोई पक्षकार नहीं आया तो शासन को तो अधिकार है कि कलेक्टर को नयी गाईड-लाईन जारी कर दे । बिल्डिंग की जो लागत है उसको हम कहीं कम करने की बात नहीं कर रहे हैं । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो ज़मीन है, जो आवंटित ज़मीन है, जो राज्य शासन से हमको दिया गया है या जिला प्रशासन के द्वारा जो आवंटित की गई है उस ज़मीन को जो कलेक्टर दर रेट है, मैं उसी में संशोधित करने की बात कर रहा हूं । उसमें 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत की छूट अगर राज्य शासन चाहे तो वह कर सकता है जिससे हमारा जो सैकड़ों करोड़ अभी जाम है, हमको अभी एक

पैसा नहीं मिल रहा है । एक नगर -निगमों का ठोस इंकम का साधन बनेगा, उसका 2 परसेंट वार्षिक जो किरायानामा है वह पैसा भी हमारा लोगों का payment और सब प्रकार के स्थानीय मूलभूत कामों में काम आएगा । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यह निवेदन है कि शासन नियम संशोधित करके जल्दी इसको एक कुछ ऐसा नियम बनाये कि संबंधित कलेक्टर को निर्देशित करें, यही मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन भी इस बात को लेकर चिंतित है कि निकायों की आय बढ़े, उनके राजस्व में वृद्धि हो और इतनी बड़ी जो property लगी है उसका सदुपयोग हो और निकाय को आय हो पर इसके लिए नियम-प्रक्रिया निर्धारित है । कलेक्टर दर भी तय करने की एक नियम और प्रक्रिया है कि किस आधार पर कलेक्टर दर निर्धारित होता है, अपने मन से कलेक्टर नहीं कर सकते फिर भी जो इतनी दुकानें बची हैं वह किस प्रकार से नीलामी में उठ जाए उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं नियम में रहते हुए वह ज़रूर करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये सुनील जी पूछ लीजिये ।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं केवल सुझाव दे रहा हूं क्योंकि जब मैं महापौर था और केंद्र सरकार से मुझको जब पैसा मिला था तो मंगलम के पास में दुकानें बनाया था, गांधी चौक में दुकानें बनाया था । 17 साल हो गये वह दुकानें आज भी फँसी हैं, मैं अरुण साव जी की बात से सौ परसेंट सहमत हूं क्योंकि एक नंबर में बहुत पैसा जो है, वह अगर आप करेंगे तो बहुत लोग नहीं दे पाते लेकिन उसका रास्ता निकालना होगा । 17-17 साल हो गये, अब दुकानें खंडहर हो रही हैं तो अगर आप रास्ता नहीं निकालेंगे और पूरे प्रदेश की चिंता...।

अध्यक्ष महोदय :- आप बताइए न, सुझाव दीजिए न ।

श्री सुनील सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि उसका rate का निर्धारण करके जो है, जो भी market value उसका टेंडर निकाल लें और जो आता है उसके अंदर में आप जो है कलेक्टर्स और committee बैठकर जो है उस पर निर्णय ले लें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, राजेश जी आप भी पूछ लीजिये । आप भी सुझाव दे रहे हैं, आपका भी सुझाव आ जाये ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक रूप से माननीय मंत्री जी ने जिस उत्तर पर कहा है तो गाईड-लाईन के आधार पर मार्केट के अंदर अगर दुकान बेचने जाते हैं तो आज की स्थिति में नहीं बिकती है क्योंकि सौ प्रतिशत एक नंबर में पैसा देना पड़ता है लेकिन दूसरा इसमें आरक्षण का मामला है । दुकानें इसलिए भी फँसी पड़ी है कि आपके उसमें आरक्षण का प्रावधान है, यह करोड़ों रुपए की property 10 साल-15 साल से धीरे-धीरे खंडहर होती जा रही है । एक policy बना सकते हैं और आपके इसमें policy का प्रावधान है । आप किराये-रेंट पर भी दे सकते हैं

जिस property से हमें एक रुपए की आमदनी नहीं हो रही है । हम उसको रेंट पर देने का प्रावधान ला सकते हैं। उसके कारण वह पूरा क्षेत्र अबाध हो जाएगा, दुकानें अबाध हो जायेंगी और निगम के कुछ आमदनी के स्रोत निर्मित हो जायेंगे। इसलिए प्राइम लोकेशन में ये जितनी भी हैं, दुर्ग में भी बता दें, मंडी में सब प्राइम लोकेशन की हैं और गाइडलाइन के आधार पर कुछ नहीं, अगर सरकार का गाइडलाइन स्पष्ट है कि हमारे शहर के अंदर कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर सरकारी मकान से लेकर सबके किराये का निर्धारण होता है। अगर उस गाइडलाइन में भी हम कॉमर्शियल का कर देंगे तो भी बहुत बड़ी राहत हो जायेगी। यह मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। इस पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। सुझाव आ गया। आप देख लीजिए। बघेल लखेश्वर जी।

(2) जिला बस्तर अंतर्गत कोसारटेडा डेम के निर्माण से प्रभावित किसानों को 5 एकड़ भूमि/आवासीय प्लाट एवं नौकरी नहीं दिया जाना।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है : -

जिला बस्तर अंतर्गत विकासखण्ड बस्तर क्षेत्र का कोसारटेडा डेम, जिसे सैकड़ों किसानों की आर्थिक व सामाजिक समृद्धि का कारण माना जाता है और हो भी रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर तत्कालीन सरकार के झूठे वायदों व उनके द्वारा दिखाये गये सब्जबाग में फंसकर इस कार्ययोजना को फलीभूत करने में अपना घर-बार, अपनी जमीन गंवा चुके लोग आज 15-20 वर्ष होने के बाद भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। प्रभावित परिवारों को 5 एकड़ जमीन, आवासीय प्लाट व नौकरी देने का वायदा किया गया था, लेकिन वे सभी वायदे थोथा वायदा ही साबित हो रहे हैं। प्रभावित परिवारों में से कुछ परिवार को उनकी जमीन व घर से बेदखल करने के बाद वे पास के गांव में स्वयं के श्रमदान से घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन वह जमीन अभी-भी उन्हें नहीं दी गई है। पहले ये परिवार अपने खुद की कृषि भूमि में खेती कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन शासन-प्रशासन की बेरूखी की वजह से अब ये परिवार दूसरों की जमीन में मजदूरी करने को मजबूर हैं। इन प्रभावित परिवारों की संख्या सैकड़ों में है। न्याय की गुहार के साथ दर-दर भटक रहे हैं। ये सभी परिवार अपने व अपने बच्चों के भरण-पोषण व भविष्य को लेकर चिंतित व दुःखी हैं, इससे शासन-प्रशासन के प्रति आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

जल संसाधन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले की कोसारटेडा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना के निर्माण की प्रथम प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 1980 में राशि रू. 601.00 लाख की जारी की गई थी, जिसे छत्तीसगढ़

शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2010 में राशि रू. 15465.00 लाख (पंद्रह हजार चार सौ पैंसठ लाख) की प्रदान की गई थी, जिसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता खरीफ 7360.00 हेक्टेयर एवं रबी 3760.00 हेक्टेयर, कुल 11120 हेक्टेयर है, जिससे जिले के 25 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। परियोजना का शीर्ष कार्य वर्ष 2008 एवं नहर कार्य 2016 में पूर्ण किया गया है। कोसारटेडा बांध परियोजना अंतर्गत भू-अर्जन अधिनियम, 1894 एवं आदर्श पुर्नवास नीति, 2005 यथासंशोधित 2007 के नीति-निर्देश, नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए शीर्ष कार्य हेतु राशि रू. 878.13 लाख का अवार्ड वर्ष 1983-2014 में पारित कर 05 ग्रामों के 238 भू-स्वामियों से 615.35 हेक्टेयर तथा नहर कार्य हेतु राशि रू. 201.59 लाख का अवार्ड वर्ष 2003-2013 में पारित कर 23 ग्रामों के 828 भू-स्वामियों से 124.61 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया है।

इस प्रकार परियोजना के निर्माण हेतु राशि रू. 1079.72 लाख का अवार्ड पारित कर कुल 1066 भू-स्वामियों से 739.96 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया है। पारित अवार्ड राशि रू. 1079.72 लाख के विरूद्ध, राशि रू 1038.01 लाख का भुगतान 974 भू-स्वामियों को किया जा चुका है एवं शीर्ष कार्य अंतर्गत 02 भू-स्वामियों को राशि रू. 3.54 लाख एवं नहर कार्य अंतर्गत 90 भू-स्वामियों को राशि रू. 38.17 लाख इस प्रकार कुल 92 भू-स्वामियों को राशि रू. 41.71 लाख का अवार्ड प्राप्ति हेतु बारंबार स्मरण कराया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति, 2005 यथासंशोधित 2007 के पैरा 8.1, 8.2 के अनुसार डुबान प्रभावित परिवारों को पुनर्वास अनुदान, परिवहन व्यय एवं बांध के समीप आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। परियोजना अंतर्गत सैंच्य क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। डुबान प्रभावित परिवारों द्वारा रिक्त शासकीय भूमि में कृषि एवं समूह गठन कर मछली पालन से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। इस प्रकार परियोजना निर्माण से जिला-बस्तर में खुशहाली एवं आर्थिक सम्पन्नता निर्मित हुई है।

अतः आम जनता में हर्ष व्याप्त है।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, कोसारटेडा डेम, इंद्रावती से भी ज्यादा जीवनदायिनी बन गया है । इंद्रावती के संबंध में मैंने एक ध्यानाकर्षण लगाया है । 2-3 किलोमीटर डेम सूख गया । अब सिंचाई के लिए या अन्य चीजों के लिए कोसारटेडा से ही पानी जा रहा है । यहां के किसान दर-दर भटक रहे हैं, कई समाचार पत्रों में बार-बार आता रहता है । मंत्री जी का इलाका है, मंत्री जी भी हैं, सब कुछ है। इस बांध को बनाने में इनके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका भी थी । लेकिन जिस तरह से किसान बार-बार हड़ताल वगैरह कर रहे हैं, यह बड़ा दुखद है । मैंने इस विषय को पेपर कटिंग के आधार पर लगाया है । वास्तविकता की जानकारी तो नहीं है, आपको जानकारी होगी । लेकिन इसमें एक प्रश्न करना चाहूंगा कि किन नियमों, शर्तों के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण किया गया था और क्या-क्या वायदे

किये गये थे ? हम किसानों को कितने एकड़ जमीन देंगे और कितना क्या देंगे, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण लाया है । यह बस्तर की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपकी वजह से हम उस योजना को पूर्ण कर पाए । आपके मार्गदर्शन में वह योजना पूर्ण हुई । 1980 से इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी । 2005 में आपके मार्गदर्शन में जब आदर्श पुनर्वास नीति बनी, उसके बाद जाकर आपने जो प्रावधान किया, उसके बाद उसकी लाईनिंग का कार्य, उसके हेडवर्क का कार्य, सब कार्यों को हमने प्राथमिकता के साथ पूरा कराया अन्यथा वह कार्य आज भी अपूर्ण रहता । आप इस बात को देख लीजिए जो लोग किसान पुत्र होने की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, किसानों के लिए सिंचाई का एक इंच रकबा भी नहीं बढ़ा पाते और जब बन जाता है तो उसमें प्रश्न करते हैं कि किस तरीके से उसको बाधित किया जाय, तो ये मानसिकता है । अब यहां पर हमारे किसानों को पानी मिल रहा है, मछली पालन हो रहा है और जो वहां की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है । लगभग 11 हजार हेक्टेयर सिंचाई का क्षेत्र है, पेयजल की समसया है, उसको लेकर इस परियोजना को स्वीकृति मिली है । मैं तो केवल आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके कारण से इतनी बड़ी योजना पूरी हो पाई है अन्यथा यह योजना भी पूरी नहीं हो पाती । जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे बस्तर को उपेक्षित करके रखा । लेकिन आपके दिशा निर्देश पर, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हम लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं और इस दृष्टि से हम आगे भी काम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, मैं उसमें कुछ चीज जोड़ देता हूं।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही धन्यवाद दे दी है।

अध्यक्ष महोदय :- जब मैं मुख्यमंत्री बना और जब भी बस्तर जाता था, केदार मेरे साथ बैठा रहता था। मैं उस बांध को देखकर कहता था कि अभी तक इसका नाला क्लोजर क्यों नहीं हुआ है। उपर से उड़ते समय आते, समय जाते समय देखता था। मैंने इनको कहा तो उन्होंने कहा कि मुआवजा का प्रकरण है। दूसरी बार केबिनेट में इसको रिवाईज मुआवजा का प्रकरण लाकर फिर से मुआवजा देकर इस काम को शुरू किया गया और (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 1980 से जो काम बंद था, आपके लिए वह 11 हजार हेक्टेयर बहुत उपयोगी डैम है। मगर मुझे अच्छा लगता है कि उस प्रोजेक्ट को मैंने हेलीकॉप्टर से बैठकर सर्वे कराकर मेरे दिमाग में आया और उसको केबिनेट में लाकर एक बार और मुआवजा राशि दिलवाने का काम किया। आज यह बनकर तैयार हो गया है। मुझे याद आता है कि कोसारटेडा डैम कैसे बना। चलिए, आप प्रश्न करिए।

श्री लखेश्वर बघेल :- मैंने पहले मंत्री जी और उनके परिवार को धन्यवाद दिया, अध्यक्ष महोदय आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बहुत बड़ी परियोजना है और उसके कारण से हमारा जल स्तर बढ़ा

है, जो स्तर नीचे गिर रहा था, वह उपर आ गया। मंत्री जी मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन नियम शर्तों के अधीन जमीन अधिग्रहण की गई थी, किसानों से क्या वायदा किया गया था ? इसमें बार-बार पत्राचार और पेपरबाजी हो रही है, मैंने उसके संबंध में प्रश्न पूछा था। 92 किसान राशि नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, इतने सालों के बावजूद भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं, इसके क्या कारण है ? पेपर में जिस प्रकार से आ रहा है कि इनको 5 एकड़ जमीन देने की बात थी, आवासीय जमीन देने की बात थी, नौकरी देने की बात थी, क्या ये नियम शर्तें थी ? मैं यह जानना चाह रहा हूं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श पुनर्वास नीति जो आपकी अध्यक्षता में गठित हुई थी, उसके बाद वहां पर अलग से पैकेज देकर उस योजना को पूर्ण कराया गया। आदर्श पुनर्वास नीति में जो सिंचाई परियोजना है, जो जनहित में कार्य करने वाले हैं, उसके लिए या तो उनको जमीन देने का प्रावधान है, यानी जमीन नहीं मिलती है तो उन्हें मुआवजा राशि देने का प्रावधान है, उसके तहत मुआवजा राशि अवार्ड पारित करके दी गई है। आप पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, आप लोग वहां पर जाकर लोगों को उद्वेलित करते हैं। आपकी सरकार में आप लोगों ने किस तरीके से उनसे वादा किया था, पिछली बार आपकी सरकार रही। मैं उस समय विधायक भी नहीं था, आप विधायक रहे। आप बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का दायित्व भी निर्वहन कर रहे थे, आप लोगों ने उन लोगों से बहुत सारा वादा भी किया था लेकिन आपने उन वादों को पूरा नहीं किया। वर्ष 2021 में आपकी ही सरकार में जो प्रस्ताव वहां से भेजा गया था आप लोगों ने उस प्रस्ताव को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने एक सिरे से नकार दिया। आज आप यह कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं, किसान हितैषी हैं, आपका वास्तविक चेहरा लोगों के सामने दिख रहा है। लोग जान रहे हैं कि आप किस तरीके से आदिवासियों के हित में केवल बाहर सड़कों में बात करते हैं। जब आपको सरकार का दायित्व मिलता है तब उनके हित में काम नहीं करते हैं, उसके वास्तविक चेहरे का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे कोसारटेडा परियोजना के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। आप वहां पर केवल राजनीति करने जाते हैं। आपने कभी भी वहां के लोगों के लिए योजना बनाकर काम नहीं किया, उनको किसी तरीके से लाभ देने का काम नहीं किया। अब जब यह योजना बन गई है तो आप पेपरकटिंग के माध्यम से क्यों इस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न कराते हैं। वहां पर जो लोग हैं, उनको उसकी सुविधा का लाभ मिले, उस दृष्टि से आपकी लड़ाई हो। आप लोगों की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप आपका आदिवासी विरोधी वास्तविक चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। चाहे बस्तर हो या सरगुजा हो, लोग आपको नकार चुके हैं, दोनों स्थिति में वहां पर आपकी किस तरह की स्थिति हो रही है, वह आपको स्वयं देखने का प्राप्त हो रहा है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि वह योजना पूर्ण हुई है और उस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ

हमारे लोगों को प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, इस दृष्टि से हम काम करेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से छोटा सा सवाल है, लेकिन जिस तरीके से संकीर्ण मानसिकता के साथ मुझे जवाब मिल रहा है तो यह बड़े दु:ख की बात है। आपको ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी कि कौन कैसा है? आपको तो केवल इतना सा जवाब देना है। मंत्री महोदय, यह आपकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। हमको भी ये सब सुनना पसंद नहीं है। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, यह हुआ। 10 साल हो गये हैं, मैं वहां पर नहीं गया हूं। आप जाकर बरगलाते हैं। हम लोग बरगलाते नहीं हैं। आज जिस प्रकार से पत्राचार हो रहा है, जिस तरह से यह बात पेपर में आ रही है और इतने दिन से यह कार्य नहीं हो रहा है तो हमको लज्जा लग रही है कि इतनी संवेदनशील सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको इसको नहीं करना है तो आप मत करियेगा। हम लोग जब भी सरकार में आएंगे, तब करेंगे। यह बात है। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, वह अच्छी बात नहीं है। यह संकीर्ण मानसिकता है। आप करिये या न करिये, वह अलग बात है। यह मामला आपका है, लेकिन जिस प्रकार से।

लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- बघेल जी, जब आप लोग सरकार में थे तो आप लोगों ने इसको क्यों नहीं किया ? आप बोलते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे, तब करेंगे। आपको जनता ने 5 साल का मौका दिया था तो आपने क्यों नहीं किया ?

श्री लखेश्वर बघेल :- हां, हम लोगों ने इसको नहीं किया, इसलिए हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं। क्या आप किसी के घर का कार्य कर रहे हैं? कोई भी कार्रवाई सरकार करती है। हम लोग खैरात में किसी को नहीं देते हैं। आप लोग सरकार के पैसे को वेस्ट करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आपने 5 साल में इसको क्यों नहीं किया ? अभी आप बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। 5 साल तक आपकी सरकार थी। ...(व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- 5 साल तक आपकी सरकार रही। आपने 5 साल तक इसको कचरे के डब्बे में डालकर निरस्त कर दिया। आपने उनके प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। ...(व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- बघेल जी, यह कोई नया नहीं है। इसको हमारी सरकार ने पूरा कर दिया। ...(व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- क्या हमारी सरकार ने नहीं किया ? हमारी सरकार ने 2 साल तक इसके लिए प्रयास किया है। आप लोग इस तरह का जवाब मत दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बैठे हैं। उनके नेतृत्व में स्पेशल पैकेज करके हम लोगों ने इस योजना को पूरा कराया। ...(व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि ऐसा हुआ, फलाना हुआ। यदि आपको जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए। कोई बात नहीं। हम भविष्य में आपसे कभी भी कोई प्रश्न ही नहीं करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बघेल जी, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हमको प्रश्न ही नहीं करना है। ऐसी मानसिकता वाले से हम क्या प्रश्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। नियम-267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं।

समय :

12.32 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

01. श्री अजय चंद्राकर
02. श्री पुन्नूलाल मोहले
03. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
04. श्रीमती अंबिका मरकाम
05. श्री दलेश्वर साहू

समय :

12.32 बजे

प्रतिवेदन की प्रस्तुति

लोक लेखा समिति का प्रथम से लेकर सत्ताइसवां तक 27 प्रतिवेदन

सभापति महोदय, लोक लेखा समिति (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का प्रथम से लेकर सत्ताइसवां तक 27 प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय :

12.33 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में शामिल निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्री ललित चन्द्राकर

02. श्री दलेश्वर साहू
03. श्री पुन्नूलाल मोहले
04. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
05. श्री जनक ध्रुव
06. श्री लखेश्वर बघेल
07. श्री धरम लाल कौशिक
08. श्रीमती अनिला भेंडिया

अध्यक्ष महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ माननीय सदस्यों का निर्वाचन। संसदीय कार्य मंत्री जी।

समय :

12.34 बजे

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ माननीय सदस्यों का निर्वाचन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि हेतु अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि "सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि हेतु अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय

12.35 बजे

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के लिए 09 माननीय सदस्यों का निर्वाचन

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हो।"

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि -

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि "सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025 को अपराह्न 4:00 बजे तक दिए जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को अपराह्न 2:00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगी।
3. उम्मीद्वारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 को प्रात: 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा।

निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित "सूचना कार्यालय" से प्राप्त किए जा सकते हैं।

समय

12.38 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय :- माननीय उमेश पटेल जी चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत हुआ।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, उधर से आपका पहला भाषण है।

श्री उमेश पटेल :- बैठ जाऊं ?

श्री राजेश मूणत :- नहीं-नहीं, आप अच्छे से बोलना, दिल से बोलना, राजनीति से ऊपर उठकर बोलना।

श्री उमेश पटेल :- वह चश्मा तो आप लोग पहनते हो।

श्री राजेश मूणत :- मेरा तो चश्मा है ही नहीं। मैं खाली पढ़ने के लिए चश्मा लगाता हूं।

श्री उमेश पटेल :- बाकी लोगों के पास चश्मा है।

श्री राजेश मूणत :- मैं चश्मा रखता ही नहीं। खाली पढ़ने के लिए चश्मा लगाता हूं। आप तो वैसे भी पढ़े-लिखे हुए भाई हो, वहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि सामूहिक जवाबदारी है। मगर वित्त मंत्री जी का भाषण शुरू हो रहा है और वित्त मंत्री जी गायब हैं। ऐसे में हम लोग अपना भाषण नहीं देना चाहेंगे। जब आ जाये तो बुलवा लीजियेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सभा से बाहर चले गये)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.40 से 1.06 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
01:06 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपका प्रवेश बिना घंटी का हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप घंटी सुन नहीं पाये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने चिंता की थी कि रायगढ़ जिला खरसिया में आता है। इसीलिये खरसिया का आदमी बोले और रायगढ़ का आदमी न रहे तो आगे बात नहीं बनेगी। नेता जी, आपने चिंता की इसलिए आपको बधाई हो।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- भैया, ऐसा है कि खग जाने खग ही के भाषा। दोनों एक-दूसरे भाषा को समझते हैं तो दोनों तो रहें।

अध्यक्ष महोदय :- श्री उमेश पटेल जी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भाषण शुरू करूं, उसके पहले आपको एक बात कहना मुझे अति आवश्यक लग रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके पहले मैं आपको एक बात कह देता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, वह औपचारिकतावश दायित्व पूरा कर रहा हूं, मैं सरकार के बजट से सहमत हूं, आप ऐसा कह दीजिये। आप विरोध की औपचारिकता पूरी कर रहा हूं कह दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यहां माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। डौंडीलोहारा में अभी जनपद का वोटिंग होना था और हमारी नेत्री अनिला भेंडिया जी हैं, उनके साथ 9 सदस्य अंदर गये। जैसे ही 9 सदस्य अंदर गये, कांग्रेस का बहुमत दिखा। वहां का अधिकारी मेडिकल का बहाना लेकर cancel करके भाग गया। यह अभी की घटना है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, अभी चस्पा कर दिया गया है कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है और डौंडीलोहारा में मतदान हो रहा है। सम्बलपुर पंचायत का मामला है कि 44 वोट एक ठाकुर को मिला, 35 वोट किसी एक को मिला और जिसको 7 वोट मिला है, उसको निर्चाचित घोषित कर दिया गया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो यहीं बैठे हैं। मैं तो यह चाहूंगा कि उस अधिकारी को बुलवा कर का मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल टेस्ट ही करवा लीजिये क्योंकि अब चुनाव इतना नजदीक आने के बाद उसको हटा दिया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आपको यह मालूम है कि कितनी जगह निर्विरोध चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है?

श्री उमेश पटेल :- बिल्कुल ठीक है। निर्विरोध चुनाव एक अलग प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया से हो रहा है। अजय जी बात बदलने की कोशिश मत करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, डरवा कर निर्विरोध चुनाव कराये जा रहे हैं और जो लड़ना चाहते हैं, उसका चुनाव cancel करवा रहे हैं। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- क्या प्रक्रिया को छोड़ देंगे? प्रक्रिया में चुनाव कराईये। आप लोग [xx] तो मत करिये।

श्री उमेश पटेल :- आप लोग प्रक्रिया और नियम का पालन करिये। यदि छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया का पालन नहीं होगा तो हम यहां किस बात का भाषण देंगे? यदि लोकतंत्र में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया जायेगा तो यह भाषण देने का क्या मतलब है?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में 'One Nation, One Election' का डंका बज रहा है। अब आप लोग पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का एक दिन One Nation, One Election नहीं करा पा रहे हैं। आप लोग अलग-अलग तारीखें दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यहां तो One Nation, One Election करके दिखा दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्मयंत्री जी की ओर अपनी बात पहुंचा रहा हूं। आपको बोल जरूर रहा हूं। आप नाराज मत होईएगा।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल। आपने बात रख दी।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, इसी में एक बात है।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय नेता जी, क्या आप One Nation, One Election में सहमत हैं? (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, इही मा एक मोर बात हावय कि मालखरौदा में बी.डी.सी. के गलती होथे। दोनों तरफ के वोट हर बराबर आ जाथे ता तहसीलदार ही हर ओखर परची डालथे। नियमत: ये होथे कि कोई दूसरा आदमी हर आके परची ला निकालतिस, लेकिन स्वयं तहसीलदार हर परची निकाल देहे रिहीस हे। मोर माननीय मुख्यमंत्री जी अऊ गृह मंत्री जी से निवेदन हे कि अइसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी भी ओ हर बइथे हे, आवेदन देहे। ये भी बात ला आपके संज्ञान मा डाल देवत हौं कि ऐसे तहसीलदार के ऊपर मा कार्रवाई होना चाहिए, जो अपन बढ़-चढ़ कर स्वयं चुनाव लड़त हौं जइसे स्वयं परची निकाले रिहीस हावय।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चर्चा प्रारंभ कीजिये। आपने जानकारी दे दी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट भाषण पर चर्चा के लिये खड़ा हुआ हूँ । वैसे बजट तो बहुत लंबा है और भाषण भी बहुत लंबा हुआ है...।

डॉ.चरणदास महंत :- हस्तलिखित है, इसलिये लंबा है ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हम तो सीधे डेटा पर बात करते हैं । पिछले वर्ष वर्ष 2024-2025 में जो अनुमान लगाया गया था, मेरे पास पुराने बजट की कॉपी है । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसमें अनुमान लगाया था कि राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 16,292 करोड़ होगा, जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.90 होगा । अध्यक्ष महोदय, यह हमारा reviced estimate आया है, इसमें हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है या GSDP है, वह लगभग 5 persent का है । अध्यक्ष महोदय, हमारा 2.9 का अनुमान था और अभी यह भी अनुमान है, revised estimate ही है, जहां 10 महीने का आंकड़ा होगा और 2 महीने का अनुमान लगाया गया होगा, इसमें 5 persent है । अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों हो रहा है ? हमने जो वर्ष 2024-2025 में अनुमान लगाया था कि हमारा जो expenditure है, वह मोटा-मोटा 1 लाख 47 हजार करोड़ के आसपास होगा और अनुपूरक तथा सब कुछ जोड़ने के बाद 1 लाख 51 हजार करोड़ के आसपास गये और जो हमारा recipt होना चाहिये, जो हमने 1 लाख 26 हजार करोड़ का अनुमान लगाया था, वह 1 लाख 21 हजार करोड़ के आसपास रह गया है । अध्यक्ष महोदय, हमारा expenditure बढ़ा और हमारा जो recipt है, वह लगभग 5 हजार करोड़ रूपये के लगभग कम हुआ है, इसमें कुछ आंकड़े इधर-उधर हो सकते हैं, यहां 5 persent का अंतर आ गया है । यदि इसे GSDP के persent में निकालेंगे तो सीधा 5 persent है । अध्यक्ष महोदय, 5 persent क्या important है, इसलिये क्योंकि FRBM का जो नियम है या उनकी जो कमेटी है, जो recommend करती है, उनका 3 persent से ऊपर के लिये recommendation नहीं है ? यह 3 persent के अंदर रहता है तो उसी को अच्छा वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है और यह 5 persent का होना, हमारे लिये उतना अच्छा नहीं है ।

श्री अमर अग्रवाल :- कॉपी देखकर क्यों बोल रहे हो भाई ?

श्री उमेश पटेल :- मैं आपकी बात समझ गया, आप रहने दीजिए ना ? उधर ही तो देख रहा हूँ और किधर देख रहा हूँ ? मैं तो अध्यक्ष जी के तरफ ज्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि वह टोक देंगे कि इधर देखकर चर्चा करें ।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, यह मामला घूम-फिरकर खरसिया के इर्द-गिर्द ही आया है ।

श्री उमेश पटेल :- देखिये, आपको बता रहा हूँ कि खरसिया वह ताकत रखता है कि छत्तीसगढ़ की पूरी economy चला सकता है । अध्यक्ष महोदय, यह GSDP से हमारा persent है । अध्यक्ष महोदय, मैं recipt का देख रहा था कि हम लोग कहां कम पड़े, जो main item है, जिसमें State Own Tax 49,700 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था, जिसमें हमारी प्राप्तियॉ 26,200 करोड़ प्राप्तियॉ हुई है । यहां हम लोगों को State Own Tax में लगभग 4 हजार करोड़ की कमी दिख रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं अब इसके अंदर गया तो State GST है, यहां हमने 17,446 करोड़ का अनुमान लगाया था । हमारी अभी तक revised estimate है, वह 16,000 करोड़ के आसपास है । यहां भी थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन जो ज्यादा कमी दिख रही है वह Sale Tax and Wealth Tax पर दिख रही

है । हमने Vat पर 9960 करोड़ का अनुमान लगाया था और अभी जो revised estimate है, वह 6490 करोड़ है, यहां State GST में लगभग 3000 करोड़ की कमी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि हमारी प्राप्तियॉ इतनी कम हुई है, उसका महत्वपूर्ण क्या कारण रहा है ? हम लगभग 4000 करोड़ की कमी क्यों देख रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारा जो बजट है, इसमें 3 महत्वपूर्ण खंड है या तीन महत्वपूर्ण भाग है, एक Agriculture, एक है Manufacturing और एक है Service Sector । 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 पर हमने जो अनुमान लगाया है, उसमें आप Agriculture पर देखेंगे तो हमने 2022-23 में GSDP की तुलना में 9.3 प्रतिशत से Grow किया था । हम लोग 2023-24 में 9 प्रतिशत से 5.8 प्रतिशत पर आये और हम 2024-25 में भी 5.8 प्रतिशत पर आये तो Agriculture Sector में कमी दिख रही है ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सेक्टर है- Manufacturing का । Manufacturing Sector में हम लोग 2022-23 में 1.5 प्रतिशत पर थे, 2023-24 में 3.3 प्रतिशत पर थे और अभी हम लोगों ने 7.1 प्रतिशत का Estimate लगाया है । हमें यहां बढ़ोत्तरी दिख रही है, लेकिन Service Sector पर आएंगे तो Service Sector में 2022-23 में हम 11.3 प्रतिशत पर थे, जो हमारा Growth था । हम 2023-24 में 10.4 प्रतिशत पर थे, यहां से Deep हुआ और अभी जो हमारा अनुमान है, वह 8.5 प्रतिशत का है । मतलब हम लोग लगातार Deep की तरफ जा रहे हैं । Service Sector और Agriculture Sector, इन दोनों पर हमें कहीं न कहीं कमजोरी नजर आ रही है और इस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि यह दोनों ही बहुत Important sector हैं । अगर 90 की दहाई को देखें तो Service Sector ही Indian Economy को आगे बढ़ाया था और Service Sector पर ही हम लोग अपना पूरा weightage रख रहे हैं क्योंकि अगर अभी के GSDP को भी देखें तो Service Sector पूरी Economy पर लगभग 37 प्रतिशत योगदान देता है, Agriculture Sector लगभग 27 प्रतिशत योगदान देता है और Manufacturing Sector लगभग 36 प्रतिशत योगदान देता है । अगर आप Service Sector and Agriculture Sector को मिलाएं तो यह दोनों सेक्टर लगभग 65 प्रतिशत के आसपास होते हैं, जो कि हमें दोनों सेक्टरों पर कार्य करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ज्यादा पिछड़ जाएंगे तो फिर हमारे लिए Recovery बहुत मुश्किल होने वाली है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक विषय पर बहुत जोर लगाकर कहा कि हम लोगों का फोकस Capital Expenditure पर है । होना भी चाहिए । हम लोगों को Capital Expenditure पर ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, मैं इससे बहुत सहमत हूं, लेकिन वह डेटा नहीं बोलता है । अगर Capital Expenditure में Loan given by state and repayment of death को अगर मैं हटा दूं, अगर इन दोनों हिस्से को हटा दूं तो जो Infrastructure पर जो Expenditure होगा, अगर मैं उस भाग को लूं तो हमने 22,300 करोड़ के आसपास अनुमान था और हमने लगभग उतना ही

खर्च किया है, लेकिन यह GSDP का कितना प्रतिशत हो रहा है ? हम जो Infrastructure पर 22,900 करोड़ रूपए खर्च करने जा रहे हैं, यह GSDP का सिर्फ 4 प्रतिशत होता है । हमारे Capital Expenditure पर Loan Repayment एक बड़ा Important part हो रहा है और Loan Given by state वह तो छोटा Part है, लेकिन हमारा Loan Repayment बड़ा हिस्सा होता जा रहा है और यह Loan Repayment बढ़ता क्यों जा रहा है? एक और विषय पर मैं थोड़ी गंभीर स्थिति पर बात करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी Barrowing लगातार बढ़ती जा रही है । इस चीज को पार्टीगत नजरिए से देखने की बजाय अब यह स्थिति बनती जा रही है कि हम लोग इस पर बैठकर चर्चा करें । छत्तीसगढ़ की Barrowing जो Last year है, वह मोटा-मोटी लगभग 40 हजार करोड़ की है और यह स्थिति आगे आने वाले समय में ज्यादा गंभीर मत हो, ऐसी स्थिति मत बने कि हम लोग लगातार Barrowing पर ही चलें, केन्द्र से जो ग्रांट है, उसी पर चलें । इसको भी बदलने की आवश्यकता है ओर यह अब परसेंटेज के हिसाब से भी मोटा-मोटी लगभग 40 हजार करोड़ GDP का हो जाएगा, 8 परसेंट के आसपास । साल में हमारा जो borrowing है, वह 8 प्रतिशत के आसपास होना चाहिए। ये गंभीर स्थिति बनती जा रही है और इस पर हमें वर्क करने की आवश्यकता है। मैं इस आंकड़े को देख रहा था। अलग-अलग विभागों या सेक्टरों में यदि इसे देखें तो जो हम agriculture और allied activity की बात कर रहे थे, तो agriculture और allied activity में हमारा जो last year और इस साल का projection है, उसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि है। अब 4 प्रतिशत की वृद्धि को वृद्धि कैसे मानें? जब आप aspect कर रहे हैं कि आपकी जी.डी.पी. 12% से ग्रो होने वाली है और यदि agriculture में 4% ग्रो हो रहा है, तो वृद्धि कहां हुई? जब आपका inflation 7% है और यदि आपका agriculture 4% से ग्रो हो रहा है, तो वह वृद्धि कहां रही? ये तो agriculture में हम deep पर अर्थात नीचे जा रहे हैं। Education में 15% है, ठीक है, मैं इसे मानूंगा कि वृद्धि है लेकिन health and family welfare में लगभग 8% की वृद्धि है। यदि आपकी जी.डी.पी. 12% से ग्रो हो रही है और health and family welfare में 8% की वृद्धि है, तो इसका मतलब वह भी नीचे गया। Social welfare and nutrition में लगभग 6% की वृद्धि है, आपकी जी.डी.पी. लगभग 10% है, इसलिए इसमें भी कमी है। Housing में लगभग 9% है। आपका ट्रांसपोर्ट ज्यादा बढ़ा है और ये 14% है। Road and bridges बढ़ा है, पुलिसिंग बढ़ी है, जो 16% है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन दो विभाग जिस पर मैं मुख्य रूप से चर्चा करना चाह रहा था कि rural development में हमारा जो last year का projection था और इस साल के projection में हम लोगों ने लगभग 2% की कमी की है, जबकि इसकी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आवश्यकता है। rural development ऐसा डिपार्टमेंट है, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता होनी चाहिए। यह मैं पिछले साल का जो revise estimate है और अभी का compare कर रहा हूं, इसलिए -2% (minus

two percent) है। जो energy है, जो revise estimate हम लोगों ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है, वहां से अगर हम अभी का compare करें, जो कि इस समय budgeted estimate है, तो energy में -25% (minus twenty five percent) है। क्या हम लोग एक energy hungry state नहीं हैं? क्या हम लोग बहुत सारे M.O.U. sign नहीं करने वाले हैं? हमें और energy की आवश्यकता नहीं है? Energy department में 25% की कमी, मतलब हमने पिछले साल लगभग 7 हजार 200 करोड़ का projection किया था, वहॉ से हमारा revise estimate 8 हजार 200 करोड़ का रहा और इस साल हमने बजट 6 हजार करोड़ का रखा है, तो मुझे लगता है कि ये अनुमान या तो गलत है, क्योंकि energy में हमें spending की आवश्यकता होगी। energy में spending की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि इसमें इतने maintenance की आवश्यकता होती है, ट्रांसफार्मर, लाईन में सुधार की इतनी जरुरत पड़ती है कि लगातार इसमें काम करने की आवश्यकता है, इसलिए यहॉ खर्च तो होगा। यहॉ खर्च और अधिक होगा, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। इस पर मैं माननीय मंत्री जी से जरूर कहूंगा कि हम लोग energy hungry state बनने जा रहे हैं, इसलिए इसे एक बार देख लिया जाए क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं दिक्कत होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, F.R.B.M. review committee को वर्ष 2017 में Mr. N.K.Singh जी चेयर कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि - "outstanding debt should not be more than 20% for state." अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने जो अनुमान लगाया था, अभी का जो revise estimate है, अगर मैं उससे calculation करूं, तो ये जी.एस.डी.पी. का 28.9% बनता है। अगर इसी अनुमान से हम लोग चलें, तो अगले साल जो projection होगा, वह 29.6% का होगा। यह ठीक है कि जी.एस.टी. से जो रिपेमेन्ट आयेगा, मैं अभी उसको इसमें include नहीं कर रहा हूं। मैं उसको समझ रहा हूं। लेकिन आप इसको जरूर दिखवा लीजिये क्योंकि यह जो outstanding डेट है। आने वाले दिनों में यह भी हमारे लिये एक सर दर्द बनने जा रहा है। यह सारी चीजें मैंने अपने बजट भाषण में कहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग पुलिसिंग पर बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं। मैं इससे सहमत हूं कि पुलिस पर खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या आप पुलिस को equip कर रहे हैं, जिससे आज का जो साइबर क्राईम है, पुलिस उस पर सही ढंग से काम कर सके ? अध्यक्ष महोदय, उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उन्हें equip करने की आवश्यकता है क्योंकि हमें मुश्किल से सुनने मिलता है कि साइबर क्राईम का अपराधी पकड़ा गया। साइबर क्राईम होते हैं, लोग ठगे जाते हैं और ठगे जाने के बाद बहुत जगह साइबर क्राईम में पुलिस भी हाथ खड़ा कर देती है। हम उनकी ट्रेनिंग पर ज्यादा खर्चा करें, उनकी equipment पर ज्यादा खर्चा करें, यह देखे की उन्हें किस तरह की आवश्यकता है। यहां हमारे सत्ता पक्ष के सारे मित्रगण हैं। मैं उनसे पुलिस विभाग के संदर्भ में कहूंगा कि पुलिस के बूट की धमक को बनाए रखिये। पुलिस के बूट की धमक होनी चाहिए। अपराधियों पर पुलिस के बूट की

धमक की गूंज होनी चाहिए। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में जिस तरह से स्थितियां बन रही है, उसके फलस्वरूप मैं आज इस स्थिति में हूं और मैं यह कह सकता हूं कि पुलिस के बूट की धमक अब अपराधियों में नहीं रही। हम लोग चाहे जवाब में कुछ भी कहें लेकिन छत्तीसगढ़ में पुलिस नाकामयाब है। पुलिस अपराधियों को बैठाने में नाकामयाब हो रही है। यहां आगजनी की घटना, चोरी की घटना, लूट की घटना और बड़ी-बड़ी घटनाएं तो हुई है। यहां माननीय उप मुख्यमंत्री (गृह) जी बैठे हैं। उनके क्षेत्र में कई सारी घटनाएं हुई हैं। उस समय तो एक सीरिज चली है। चाहे आदिवासियों की मौत की बात हो, चाहे माता और बेटी की मौत की बात हो, चाहे कवर्धा में किसी व्यक्ति को जिंदा जलाने की बात हो, चाहे किसी आदमी को जेल ले जाते समय जेल में उसकी मौत होने की बात हो, यहां ऐसी तरह-तरह की घटनाएं हुई हैं। एस.डी.एम. को लोग दौड़ा रहे थे। पब्लिक पीछे-पीछे दौड़ रही थी और एस.डी.एम. आगे-आगे दौड़ रहे थे। एक एडिशनल एस.पी. कई सारे लोगों के सामने जूझ रही थी। इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं। यहां बलौदा बाजार की घटना हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहूंगा कि पुलिस पर जो खर्चा हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और पुलिस के आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि पुलिस के आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाया जायेगा तो यह बजट में जितना खर्च करने की कोशिश की जा रही है, वह खत्म हो जायेगा। आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाईये। यहां सारे सत्ता पक्ष के मित्र बैठे हैं। मैं इन्हीं से कहूंगा कि पुलिस के आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिये क्योंकि यह एक ऐसा स्तंभ है, जिसके रहते हुए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं।

श्री राजेश मूणत :- उमेश जी, वित्तीय प्रबंधन को और कुछ सुझावों को छोड़कर बजट भाषण अच्छा रहा न ? आप कुछ तो तारीफ कर दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- तोर भाषण ही तो ठीक रहिथे बस।

श्री राजेश मूणत :- कम से कम भाषण अच्छा तो है ना ? यादव जी, कथा अच्छी होती है तो चढ़ावा भी अच्छा आता है।

श्री रामकुमार यादव :- भाषण से राशन नइ मिलय। यह बात ला याद रखबे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बारे में बोलना चाहूंगा। मैंने आज ही माननीय मंत्री जी से कहा और अगर वे हिम्मत दिखाते तो मैं आपके लिये मेज थपथपाने के लिये तैयार था। मैं आपकी तारीफ करता क्योंकि आपने यह योजना महतारी के नाम से चालू की।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा। सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिये स्थगित।

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय
3.01 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय :- माननीय उमेश पटेल जी, अपना भाषण जारी करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उमेश भाई, आपका भोजन-वोजन अच्छे से हुआ? नहीं। मेरा मतलब यह है कि आप भोजनावकाश में भोजन करने गये थे तो आपको खाना-वाना मिला?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आपने खाना खा लिया तो थोड़ा चाय भी पीकर आ जाईये, ताजगी रहेगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, लंच से पहले जो छत्तीसगढ़ सरकार की Flagship Projects बात हो रही थी। यह सरकार महतारी वंदन योजना के नाम से अपनी पीठ थपथपाती है। मैंने आज ही महतारी वंदन योजना पर प्रश्न भी लगाया था और उसमें कई सारी बातें सामने आयी हैं। इसमें सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि यह योजना महतारी के नाम से है और हमारे बीच में जो महतारी का स्वरूप आता है, वह एक बुजुर्ग महिला का आता है। हमारे प्रदेश में जो 60 वर्ष से ऊपर की बुजुर्ग महिलाएं हैं, आप उनको 500 रूपये कम दे रहे हैं। आपका नाम और जो काम है। आपकी योजना का नाम महतारी वंदन योजना है और उसमें जिस तरह से आप उन बुजुर्ग महिलाओं का 500 रूपये काट रहे हो। यह दोनों बातें जम नहीं रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, सिर्फ इस बात के लिए ऐसा है तो मेरे ख्याल से उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी। उनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी तो इसे उनके लिए कर देना चाहिए। अगर इसको उनके लिए करेगे...।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उमेश जी एक विषय रख रहे हैं। महतारी वंदन योजना के नाम से स्पष्ट है, उसमें कोई कमी है तो आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आप इसके पहले इसी विषय पर बहिर्गमन करके चले गये थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बातें कही हैं। उस विभाग के मंत्री ने उसका स्पष्ट उत्तर दे दिया। इसलिए आप महतारी वंदन योजना के कारण वहां विपक्ष में चले गये। अब इस योजना का विरोध मत करिये। आप हमारी सरकार को धन्यवाद् दीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। इस महतारी वंदन योजना के तहत...।

श्री उमेश पटेल :- आप मेरी बात सुनिए। माननीय मूणत जी, हम इधर विपक्ष में आ गये। हमने यह मान लिया। यह तो फैक्ट है इसको कौन बदल सकता है ? अभी हम लोग सरकार में नहीं हैं। हमने कुछ गलतियां की होंगी तभी तो सरकार में नहीं है। इस बात को कौन मना कर रहा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय,आप अभी सरकार में नहीं हैं। आपने यह मान लिया ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हम तो यहां अपने विपक्ष के किरदार को निभाने आए हैं।

श्री राजेश मूणत :- नहीं-नहीं। आप अपना किरदार निभाईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर हम अपने विपक्ष के काम को करने आएं हैं। क्या आप उसको रोकना चाहते हैं ? क्या आप यह बोलना चाहते हैं कि आप अपने विपक्ष का काम मत करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आपको कोई कैसे रोक सकता है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, क्या विपक्ष को यह अधिकार नहीं है कि सरकार को उनकी कमियों को बतायी जायें।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। बिल्कुल उसकी कमियां बतानी चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, सरकार को दर्पण दिखाया जाये। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको बताया जाए। तो आप बार-बार क्यों मना कर रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उमेश पटेल जी, पूर्व के कार्यकाल में आप मंत्री थे, लेकिन आप उस समय तो कुछ नहीं बोलते थे। यही तो तकलीफ थी। माननीय नेता जी, वहां ऊपर बैठते थे और वहां आपकी चलती नहीं थी। आपने ही घोषणा की थी। यहां पर हम इतनी बात कर रहे हैं तो आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि हम, उनको बेरोजगार युवकों को प्रति माह हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् 500 रूपये देंगे। अब आप कहेंगे कि प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया। आपको जनता ने नकार दिया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय राजेश जी, मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ। हम लोग कौन से विधान सभा की बात कर रहे हैं ? अभी हम लोग 6 वीं विधान सभा में हैं। क्या आपको यह बात याद है ? हम लोग अभी 5 वीं विधान सभा में नहीं हैं। यह छठवीं विधान सभा है।

सभापति महोदय :- माननीय उमेश पटेल जी, आप अपने विषय पर आईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना के बारे में बात नहीं करना चाहते, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि क्योंकि इसमें बार-बार पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन आप उन बुजुर्ग महिलाओं के साथ अन्याय कर रही हैं, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बोल रहा हूं। आप उन बुजुर्ग महिलाओं के साथ गलत कर रही हैं। अगर आपको करने नहीं दिया जा रहा है तो उनको बोलिये। मुझे पता है कि आपकी इच्छा होगी, लेकिन आपको काम करने से यहां कुछ लोग रोक रहे हैं। आपको काम करने से मत रूकिये। एक महिला होने के नाते आप महतारी के उस भाव को जरूर समझती होंगी।

इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसमें आप दृढ़ होकर जो भी लोग इसको करने से आपको रोक रहे होंगे, उससे दूर हटिये। मेरे ख्याल से मेरी जितनी समझ है बहुत ज्यादा एमाउण्ट नहीं होना चाहिए, बहुत भारी संख्या भी नहीं होनी चाहिए। आप इसको करिये। माननीय सभापति महोदय, एक महतारी वंदन योजना, एक प्रधानमंत्री आवास पर बोलते हैं। प्रधानमंत्री आवास हमने इतना किया, संख्या में तो उनकी 18 लाख बोलने की आदत पड़ गई है। मैं दूसरे पक्ष पर जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास में 1 लाख 20 हजार रुपये मिलते हैं। मान लीजिए 30X30 का हम एक मकान बनाना चाह रहे हैं। मैंने एक सरकारी सब इंजीनियर से निवेदन किया कि आप 30X30 के प्रधानमंत्री आवास के लिए आज कितनी लागत आयेगी, उसके लिए एक estimate बनाकर दीजिए। वह जो estimate बनाये, उसमें लगभग 1 लाख 90 हजार रुपये का estimate बन रहा है। मुझे भी यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज लोगों को 1 लाख 20 हजार रुपये कम पड़ रहा है। ठीक है, जब यह योजना शुरू हुई होगी, उस समय यह एमाउण्ट शायद ठीक रहा होगा। लेकिन आज के inflation में, मंहगाई में यह राशि कम हो रही है। मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर इसको राष्ट्रीय स्तर पर ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये न। यदि राशि कम पड़ रही है, शायद इसीलिए आप लोगों ने नहीं दिया होगा। जब आप लोग थे तो राशि कम है करके आप लोगों ने नहीं दिया होगा। दूसरा चूंकि दिल्ली सरकार स्वीकृत करती है तो आपके 3 लापता सांसद हैं, वह तीनों लापता सांसद को खोजकर बोलिये कि अभी संसद का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, वहां मांग करिये।

श्री उमेश पटेल :- मैं तो यहां छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके सांसद लापता हैं, उनको बोलिये। आप लोग किसलिए लापता सांसद बनाये? आप उनको बोलिये कि इस बात को दिल्ली में उठायें।

श्री उमेश पटेल :- मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर रहा हूं। अगर आपको छत्तीसगढ़ सरकार की बात नहीं करनी है, दिल्ली के लिए बात करनी है तो उसमें भी बात करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- तीनों लापता हैं, क्या आप उनको पहचानते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- वह सब लोग अपनी- अपनी जगह में गिल्ली-डंडा, गुलेल खेलने गये हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसको छत्तीसगढ़ सरकार में ले जा रहा था कि केन्द्र सरकार का जो 50 प्रतिशत का अंश है, अगर उसमें आपको अपना अंश बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दीजिए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि लोग छत बनाने से पहले रोक के रूक जायें। अगर इतना प्रोसेस हमने आगे बढ़ा दिया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उमेश जी, इतना ही बता दीजिए।

सभापति महोदय :- उमेश जी, अपने आसन में ठीक से बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मना कर रहे हैं, अब बैठ जाईये। मैं यही चाहूंगा कि अगर सरकार प्रधानमंत्री आवास सही में देना चाहती है, अगर विज्ञापन करना है तो बात अलग है, अगर सही में गरीबों के हित में काम करना चाहती है तो मुझे लगता है कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार को अंशदान बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इसके लिए दिल्ली सरकार तैयार नहीं है तो छत्तीसगढ़ सरकार को अपना अंशदान और बढ़ाना चाहिए और इसको लगभग 1 लाख 70-80 हजार रुपये के आसपास ले जाना चाहिए। यह मेरी सोच है।

माननीय सभापति महोदय, एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हालांकि वह इनका नहीं है। लेकिन जिसके बारे में बार-बार बजट में बात की गई है वह धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना है। यह सरकार किसानों के प्रति किस तरह से [xx] दे रही है, [xx] नहीं कहना चाहिए, [xx] कर रही है। मैं इस तरह से कहूंगा कि जो अंतिम दिनों में अलग-अलग जिले में किसान बचे थे। मेरे ख्याल से जांजगीर का हमारे पास आंकड़ा है, 6 हजार किसान धान नहीं बेच पाये, 1 लाख 47 हजार क्विंटल कम खरीदी हुई है । हर जिले का अलग-अलग आंकड़ा है । कई जगह तो मुझे खुद बात करनी पड़ी कि भई धान इनका गया हुआ है खरीद लो तो अलग-अलग तरीके से परेशानी है । आप क्या सोचना चाहते हैं कि यहां का किसान [xx] है ? आप बार-बार तहसीलदार को, एसडीएम को, आर.आई. को उनके घर भेज रहे हैं । एक प्रक्रिया बना लीजिए कि किस तरह से धान खरीदी हो लेकिन यह तो एहसास मत कराइए कि यहां का किसान [xx] है ।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, एक मिनट । मैं आपसे क्षमा चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही आग्रह है कि इस [xx] शब्द को विलोपित कर दें ।

श्री उमेश पटेल :- मैंने किसी को [xx] नहीं कहा ।

श्री राजेश मूणत :- नहीं-नहीं । किसान अन्नदाता है और इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है ।

श्री उमेश पटेल :- आप एहसास दिला रहे हैं । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- व्यवहार वैसा किया गया है, बोलने का सार ऐसा है कि सरकार की...। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह आग्रह है कि आप ऐसा बोल दें कि उनके साथ अन्याय हो रहा है । किसान [xx] नहीं है, किसान अन्नदाता है और अगर इस मानसिकता से आप बोल रहे हैं तो मैं इसकी निंदा करता हूं ।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है, आपने कर लिया । माननीय सभापति महोदय, मैंने [xx] नहीं कहा । मैंने कहा कि यह जो पार्टी सरकार में आई है यह किसानों को अपने आपको **चोर** महसूस करवा रही है । बार-बार उनके घर में दबिश देना, एक-बार आर.आई. देना, एक-बार पटवारी का देना । यह क्या है ? हर जगह यही show करना कि यह किसान यहां खेती-किसानी यानी अन्नदाता तो आपका सिर्फ बोलने के

लिए है । आप बड़े-बड़े मंच पर बोलेंगे कि यह अन्नदाता है, हम अन्नदाताओं के लिये यह कर रहे हैं लेकिन Ground reality यह है कि आप उनको एक [xx] जैसा महसूस करवा रहे हैं ।

श्री राजेश मूणत :- मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक शब्द के लिये आग्रह कर रहा हूं कि किसान क्या है? अन्नदाता है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा और किसान के बारे में बात करेंगे तो फिर बहुत पुरानी सब बातें रिपीट हो जाएंगी । छत्तीसगढ़ में इसी किसान का धान डूबो-डुबोकर निकालकर देखा गया है । इसी किसान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, छत्तीसगढ़ में अपनी मांग को लेकर के आए थे, इन्हीं किसानों के घर में घुस-घुस करके चालान बनाए थे । मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इतिहास न पलटें । किसान ईमानदार है, किसान छत्तीसगढ़ का अन्नदाता है और इसलिये अगर उस पर बात-चीत करें तो यह मेरा आग्रह है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- राजेश मूणत भैया, आप धमतरी को याद कर लीजिये ।

श्री राजेश मूणत :- मुझे तो सब चीजें अच्छे से याद हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप धमतरी को याद कीजिये कि कैसे लाठियां चलीं ? आप धमतरी की बात कीजिये ।(व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आप जहां के विधायक हैं । मैं वहीं की बात कर लेता हूं। मैं पुराना इतिहास बता देता हूं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं भी आपको इतिहास याद दिला रहा हूं ।

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए । मूणत जी बैठिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं या तो आप यह कर दीजिए कि यहां जो छठवीं विधानसभा है उससे related चीज़ों की बात होगी कि सभी की बात हो सकती है ? अगर शुरू से करना है तो फिर शुरू से करते हैं ।

सभापति महोदय :- अभी तो बजट पर चर्चा है, आप बजट पर बोलिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, बजट पर चर्चा है । इस सरकार के बजट पर सब चर्चा है कि वर्ष 2001 के बजट पर चर्चा है ? अगर वहां से शुरू करेंगे तो करते हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- आप पिछली बातों से इतना भयभीत होकर भाग क्यों रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं भाग नहीं रहा हूं । मैं यह बोल रहा हूं कि आप उसके लिए अलग से चर्चा करा लीजिए । मैं आपको इस बात को कहता हूं कि मैं आपकी किसी बात से नहीं भागूंगा । हर बात के लिये खड़ा रहूंगा लेकिन बात यह है कि यहां हम बजट में चर्चा के लिए खड़े

हुए हैं, बजट भाषण में जो-जो बातें आयी हैं, मैं उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं । मैं तो कहीं बाहर इधर-उधर भटक नहीं रहा हूं । मूणत जी आप भटका रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप मत भटकिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर यह इनकी सही में इच्छा है तो इन सब चीज़ों को छोड़ें । हम लोग रकबा बढ़ाने की बात कर रहे हैं । अभी गर्मी फ़सल के लिए अलग-अलग तरह की अफवाहें फैलायीं गयीं मतलब यह बातें शायद मैं पहले भी कर चुका हूं फिर से दोबारा नहीं कहूंगा लेकिन कभी कहते हैं कि भई गर्मी फ़सल में जो लगाएंगे उसके लिए हम उनको जेल करेंगे या fine करेंगे इस तरह की बातें आ रही हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप मुझे थोड़ा सा यह बता दीजिये कि आप आवास में बात कर रहे हो, आप रबी फ़सल में आ गए, किसान में आ गए, आर.आई. भेज रहे हैं तो आय-व्यय पर चर्चा है, सामान्य चर्चा है या विनियोग पर चर्चा है ?

श्री उमेश पटेल :- एक्चुअली आप तब सो रहे थे । सुनिये न, विनियोग पर नहीं इसलिये क्योंकि...।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी जो बोल रहे हो क्या वह विनियोग पर चर्चा है ? आप यह बताईए न कि क्या आप आय-व्यय की चर्चा पर बोल रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- मैंने आय-व्यय की चर्चा पहले की है, आप उस समय सो रहे थे । आप सुन नहीं पाये हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- विनियोग तो बाद में आयेगा ।

श्री उमेश पटेल :- विनियोग पर नहीं ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो अभी जितना भाषण कर रहे हैं उसका बजट से क्या संबंध है ?

श्री उमेश पटेल :- मैं यह भाषण किसलिये कर रहा हूं उसको सुन लीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जितना भाषण कर रहे हैं उसका बजट से क्या संबंध है ? उसकी प्रशंसा करिये न । बजट में इतने सारे आंकड़े हैं ।

श्री उमेश पटेल :- मैं इसीलिये तो बोल रहा हूं कि माननीय मंत्री जी के बजट भाषण में यह सारी बातें आ गयी हैं ।

सभापति महोदय :- अजय जी, उमेश जी, आपस में चर्चा मत करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने अभी के भाषण में जो फर्स्ट पाइण्ट बोला है, वह बजट था। अभी जो बोल रहे हो, वह बजट नहीं है। इसीलिए मैंने पूछा कि विनियोग में भाषण दे रहे हो या बजट में भाषण दे रहे हो?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूं। सुन तो लीजिए न, आप सुनते नहीं हैं न, यही तो आपकी दिक्कत है और जब सुनना रहता है तब पीछे जाकर सोते हो। (हंसी) मैं इसलिए सारी बातों का उल्लेख कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी के भाषण में ये सारी बातें आई हैं। उन्हीं योजनाओं के बारे में बोल रहा हूं, जिस बारे में पैसा दिया गया है तो ये बजट से रिलेटेड चीजों पर ही मैं बोल रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आय-व्ययक पर?

श्री उमेश पटेल :- माननीय, आप तो थे नहीं?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चर्चा है, वह आय-व्ययक पर चर्चा नहीं, आंये-बांये की चर्चा लग रही है।

श्री उमेश पटेल :- आप लंच के पहले कहां थे? आप कहां गये थे? थाइलैण्ड गये थे या और कहीं गये थे? (हंसी)

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, अब इनके जो नेता हैं, वे तो कहां-कहां जाते हैं, वही देश इनको याद रहता है। बाकी देश मालूम ही नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- आप लंच से पहले कहां गये थे, यह तो बताइए।

सभापति महोदय :- उमेश जी, बजट पर आइए।

श्री उमेश पटेल :- आप इनको सुनिए न।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, एक्चुअल में क्या हो गया? उमेश जी जहां लंच करने गए थे, वहां इतनी भीड़ थी कि वहां उन्हें लंच नहीं मिला और उनको छेड़ीखेड़ी के आगे तक जाना पड़ा।

श्री उमेश पटेल :- सही बात है।

श्री राजेश मूणत :- वहां से यहां तक आते-आते थक गए, जो बोलना था, वह वे लंच के साथ भूल गए। (हंसी)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। कृपया बजट पर आएं और चर्चा करें।

श्री उमेश पटेल :- मैं यही बात कह रहा हूं कि जिन-जिन चीजों पर माननीय मंत्री जी ने पैसे की मांग की है, उन्हीं विषयों पर मैं बोल रहा हूं और इसीलिए मैं इस बजट का विरोध कर रहा हूं। जिन चीजों को जिस हिसाब से करनी चाहिए, जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए, उस हिसाब से मैनेज हो नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, अभी जो त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय चुनाव में भी कई तरह की शिकायतें मिली हैं। हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि उनके यहां किस तरह से बदल दिया गया, रोक दिया गया। अभी एक पेपर में मैं पढ़ रहा था कि महिलाएं जीतकर आई हैं, जनप्रतिनिधि बनी हैं और पुरुषों को शपथ दिला दिया गया। ऐसा-ऐसा चल रहा है। एक जगह अनिला भेड़िया जी, वहां अभी

भी धरने में बैठी हैं। जबरदस्ती वहां से अधिकारी भाग गए। तो ये तो चल रहा है। अगर वहां आज वोटिंग होना है, नौ लोग वहां पहुंच चुके हैं, बहुत सिंपल सी बात है 10 मिनट के अंदर में वोटिंग होना है। लेकिन नहीं। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र में ये इस तरह से काम करना चाहते हैं कि साम, दाम, दंड, भेद से हमारी सरकार बन जाए। मुबारक हो भईया, आपकी सरकार बन जाएगी। लेकिन होगा कुछ नहीं। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कुछ नहीं होगा। आप उठकर आ गये हैं, यह पता चल गया है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। ठीक है।

श्री केदार कश्यप :- इधर भी धन्यवाद कर दीजिए। आप ही के क्षेत्र से हैं। उनका गृह जिला है। माननीय वित्त मंत्री जी आपके ही गृह जिला से आते हैं। इतना अच्छा बजट लेकर आये हैं, इसके लिए धन्यवाद दीजिए।

सभापति महोदय :- माननीय अमर अग्रवाल जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, आपको जाने के लिए धन्यवाद नहीं दिये हैं। (हंसी) अभी और चलेगी।

सभापति महोदय :- माननीय अमर अग्रवाल जी।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, कल हमारे छत्तीसगढ़ का 2025-2026 का बजट, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी जी ने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया । सभापति महोदय, किसी भी सरकार के सामने बजट बनाते समय दो बड़ी चुनौतियां होती हैं । एक चुनौती होती है कि जो छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान जरूरतें हैं या छत्तीसगढ़ की आम गरीब जनता, गांव की, किसान की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना और दूसरी तरफ विकसित छत्तीसगढ़ बनाना और उसकी नींव डालने का काम करना । ये दो बड़ी चुनौतियां होती हैं । सभापति महोदय, मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन दो बड़ी चुनौतियों का इस बजट में बहुत सामंजस्य बैठाते हुए कल इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है । सभापति महोदय, इस प्रदेश में जब 2023 में चुनाव हुए थे और मोदी गारंटी 2023 के आधार पर हम चुनाव में गए थे । उस मोदी गारंटी 2023 की जो हमारी कमेटी बनी थी, उसका सह-संयोजक के दायित्व के रूप में मैंने उसमें काम किया था और पूरे प्रदेश में लगभग सारे विधान सभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला । सरकार से सारे वर्गों की जो अपेक्षाएं थीं, किसान की, गांव की, गरीब की, प्रोफेशनल्स की, उद्योग की, हमने पूरी कोशिश की कि उन जन-भावनाओं के आधार पर हम जनता के बीच जाएं और हमने मोदी गारंटी 2023 बनाया और वह जन-भावनाओं के आधार पर था । उसके आधार पर हमारी सरकार बनी । सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि हमने मोदी गारंटी 2023 बनाया । वास्तव में, उन गारंटियों को पूरा करना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि वे सारी योजनाएं वित्त से

जुड़ी होती हैं । सरकार के अपने संसाधन होते हैं और घोषणाएं अलग होती हैं । लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सदसयों ने उस मोदी गारंटी 2023 पर बहुत अल्प समय में काम किया, आज सवा साल हुआ है । अगर मैं ज़िक्र करूं, 3100 रूपए प्रति क्विंटल और जो पहले चार किश्तों में दिया जाता था, जो आज किसानों के हितैषी बनते हैं और किसानों के लिए बडी बड़ी बात करते हैं, समर्थन मूल्य के अतिरिक्त जो पैसा दिया जाता था, वह चार किश्तों में दिया जाता था । हमने एक मुश्त देने का वायदा किया । सभापति महोदय, दो सीज़न हो गए हमने 3100 रूपए क्विंटल खरीदने का वह वायदा अक्षरश: पूरा किया। सभापति महोदय, हमने प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री अरूण साव जी थे । हजारों की संख्या में लोग आए और हमने फार्म भी भरवाया और हमने वायदा किया कि हमारी सरकार बनते मुख्यमंत्री पहला कोई काम करेगा तो प्रधानमंत्री आवास के लिए करेगा, निवास में बाद में जाएगा (मेजों की थपथपाहट) । उसको हमने पूरा किया । पहली केबिनेट में पूरे 18 लाख गरीबों के आवास की स्वीकृति दी गई और अब तो भारत सरकार ने उसके पैरामीटर को ही बदल दी जिसका जिक्र कल बजट भाषण में आया। अब 5 एकड़ असिंचित, ढाई एकड़ सिंचित, 15 हजार रूपए इनकम, इसे तो करीब-करीब कहना चाहिए कि गरीबी रेखा से जो थोड़े से उपर हैं, उनको भी पात्रता मिलेगी। इस बजट में भी देखेंगे तो 8500 करोड़ रूपए केवल ग्रामीण गरीबों के आवास के लिए प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन। हमने वादा किया, एक बहुत बड़ी योजना थी, आज 70 लाख बहनों को उसकी सुविधा मिल रही है और समय पर मिल रही है। तेंदूपत्ता के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि हमारे जो अनुसूचित जनजाति की आबादी है, उनकी जीविका का साधन ही वनोपज है, उसको हमने पूरा करने का काम किया। रामलला दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है। वास्तव में हमने मोदी की गारंटी 2023 को इतने अल्प समय में पूरा किया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे सार्वजनिक जीवन में काम करते वर्षों हो गया, अनेकों राज्यों का अध्ययन करते वर्षों हो गया, इतने कम समय में अपने किये हुए वादों को पूरा करने वाली देश की गिनी चुनी सरकारों में एक छत्तीसगढ़ की सरकार है, जिसने अल्प समय में पूरा किया मैं ऐसा मानता हूं। (मेजों की थपथपाहट) हमने अपना वादा पूरा किया, उसका जन समर्थन भी मिल रहा है। उसका जनसमर्थन लोकसभा चुनाव में मिला, रायपुर दक्षिण के चुनाव में मिला और अभी जो लोकल संस्थाएं हैं, चाहे वह पंचायत चुनाव हो, चाहे वह नगरीय निकाय चुनाव हो, उसमें दिखाई देता है कि हमने जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया और जनता यह मानती है कि हमारी जनभावनाओं को पूरा करने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है जिसने वादा पूरा किया। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, इनका जनाधार धीरे-धीरे जा रहा है। जब जनाधार जाता है तो स्वाभाविक है, चिंता भी होती है। राजनीतिक दल में काम करने वाले जब जनाधार जाता है तो मैं

आजकल प्रश्न देखता हूं, उसमें ढूंढते रहते हैं कि कुछ मिल जाए। उमेश जी महतारी वंदन का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 500 रूपए कांट दिए। किसानों के बारे में कहेंगे कि धान खरीदी नहीं हुई। इन सारी चीजों में कमी ढूंढते रहते हैं, अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जब मैं इनके प्रश्नों को देखता हूं, इनकी चिढ़चिढ़ाहट को देखता हूं तो विधवा प्रलाप जैसे दिखता है, जब सरकार चली गई और प्रलाप करे। ये वो विधवा है जिसने अपने माथे का सिंदूर खुद अपने हाथ से मिटाया है। इनकी सरकार खुद अपने कर्मों से गई है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री विक्रम मंडावी :- अमर भैया, आप मंत्री बन रहे हो न ?

श्री अमर अग्रवाल :- मैं मंत्री बनूं या न बनूं, मैं आप जैसे प्रलाप नहीं करता । मैंने तो पहले कहा कि आप वो विधवा हो जिसने अपनी मांग का सिंदूर अपने हाथ से हटाया है, अपने [xx] से हटाया है। आपका वह प्रलाप है।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आप कौन से विधवा हो जिसने मंत्री पद खो दिया, यह हमको बता दीजिए। आपने मंत्री पद खोया है तो कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो मंत्री नहीं बनाया जा रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, एमन अइसने कर्म करत हे, एमन दोनों हाथ के चूड़ी ला....। एमन अपने चूड़ी ला कुचरत हे। 500 रूपया दे में ठगत हावए, अउ 170 रूपए ला कोन दीही। मोदी के गारंटी कहत हव, जब आप दिल्ली जाहा, अउ मोदी जी पूछही क्यों भाई मैंने 170 रूपए भेजा था, उसको क्यों नहीं दिए करके तो तुमन कइसे कहू, उहू ला बतईहा।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं आ रहा हूं सबको बताऊंगा, आप सुनते जाईए। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मैं सह संयोजक था, जब मैंने इन सारी कमिटमेंट को पूरा होते देखा तो वास्तव में प्रसन्नता होती है। इस सरकार के प्रति जनता का एक विश्वास बढ़ा है, वह किसी भी सरकार के लिए बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव होता है। मैं वह समय याद करने लग गया, जब वर्ष 2018 में इनका जो जन घोषणा पत्र था, उसको टी.एस. सिंहदेव जी ने बनाया था। उनकी सरकार आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? उनके वायदे पूरे नहीं हुए। वास्तव में जिसने वह जन घोषणा पत्र बनाया, उसको चिट्ठी लिखनी पड़ी कि जन घोषणा को मैंने बनाया है, प्रधानमंत्री आवास देने का हमारा वायदा है और हमारे पास राज्यांश नहीं है तो मैं अपने आप को विवश पाता हूं और इस विभाग से स्वयं को पृथक करता हूं। यह उनकी कार्यशैली रही। लेकिन आज यदि हम इस सरकार की कार्यशैली को देखें तो आज इसका एक-एक सदस्य, चाहे वह विधायक हो या जनता हो, वह प्रसन्न है कि इस सरकार ने अपने सारे वायदे पूरे किये।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो यह विकास की अवधारणा पर नया राज्य बना। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को

विकास की अवधारणा पर बनाया था। मुझे आज प्रसन्नता है कि विकास की अवधारणा पर बना हुआ यह छत्तीसगढ़ वास्तव में आज उनके सपनों को पूरा कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यदि आज मैं हमारे फायनेंस के कुछ पैरामीटर की बात करूं, जिसका जिक्र उमेश जी कर रहे थे तो 2000 के दशक के पूर्व जब इस देश के सारे राज्यों की आर्थिक स्थिति चरमराने लग गई और सारी सरकारें कर्ज के जाल में फंसने लग गईं, उस समय एक समिति बनी कि पूरे राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या हो, वित्तीय अनुशासन कैसे हो, वित्तीय पालन कैसे हो व राज्य सरकार के लिए गाइडलाइन क्या हो ? उसका जो निष्कर्ष आया, उसमें उसके कुछ पैरामीटर बने कि सरकारों की लोन लेने की पात्रता क्या होगी ? सरकारों की लोन लेने की पात्रता, जो उस राज्य की GSDP होगी, उसके कुछ percentage में होगी। सरकारों का कुल कर्जा GSDP का कितना percentage होगा ? revenue losses and revenue expenditure कैसे नियंत्रित होंगे ? ये सारे पैरामीटर बने। मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ आज उन सारे पैरामीटर पर खरा उतरता है और छत्तीसगढ़ देश के ऐसे 1-2 राज्यों में शामिल है। (मेजों की थपथपाहट) GSDP के आधार पर जो लोन लेने की पात्रता है। कल ही हमारा बजट आया है कि जो 3 percent की पात्रता है, उससे कम percentage पर यह सरकार लोन उठाएगी। हमारे राज्य के ऊपर GSDP का जो टोटल कर्ज होना चाहिए, उसकी 25 percent की सीमा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य का GSDP का लोन 25 percent की सीमा के अंदर है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी प्रदेश का आर्थिक सूचक उसकी प्रति व्यक्ति आय होती है। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या थी और आज हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है ? आज जो 3 सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे सर्विस का हो, उसमें हमारी प्रगति क्या है ? यदि आज हम देखेंगे तो भारत सरकार की एवरेज GSDP की जो ग्रोथ है, उससे ज्यादा ग्रोथ हमारे छत्तीसगढ़ की है। (मेजों की थपथपाहट) जब हम प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ देखेंगे तो आज भी पूरे देश की जो राष्ट्रीय ग्रोथ है, उससे ज्यादा ग्रोथ हमारे छत्तीसगढ़ की है। आज फायनेंस के सारे पैरामीटर हैं। कई बार जब RBI और planning commission की रिपोर्ट आती है तो उसको देखकर अच्छा लगता है कि RBI और फायनेंस की उस रिपोर्ट में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम 1 या 2 नंबर में होता है। छत्तीसगढ़वासी होने के कारण, जन प्रतिनिधि होने के कारण प्रसन्नता होती है कि एक नया राज्य, जिसको विरासत में गरीबी मिली, जिसको विरासत में विकास नहीं मिला, वह राज्य तरक्की करते हुए finance के सारे parameter में देश में अपना एक स्थान बनाये हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातों का जिक्र कल के बजट भाषण में है। हमारे पास कितने मेडिकल कालेज थे ? हमारे सड़कों की connectivity कितनी थी ? हमारे यहां कितने plane आते थे ?

हमारे यहां सब हेल्थ सेन्टर कितने थे ? हमारे यहां कितने कॉलेज थे ? हमारे यहां कितने कर्मचारी थी और आज हम कहां खड़े हैं ? उसका कुछ तुलनात्मक अध्ययन कल माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में किया। माननीय सभापति महोदय, मु झे प्रसन्नता है कि इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने चाहे finance के parameter हो, चाहे infrastructure के parameter हो, चाहे पूंजी के parameter हो, सबमें छत्तीसगढ़ ने जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन सरकारों ने अच्छा किया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के finance के parameter हैं, यह किसने ठीक किया ? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के infrastructure की प्रगति है, यह किसने बनाया ? इसकी नींव किसने डाली ? मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ के विकास की, वित्त की नींव तथा infrastructure की नींव, छत्तीसगढ़ की प्रगति की नींव अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। (मेजों की थपथपाहट) डॉ. रमन सिंह की सरकार ने की है, श्री विष्णु देव साय की सरकार ने की है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। उनको लग रहा होगा कि सारा काम भा.ज.पा. ने किया है तो हमने क्या किया ? स्वाभाविक है उन्हें लगेगा। आज कुछ पूंजीगत बातों का जिक्र उमेश पटेल जी कर रहे थे। पिछले वर्ष जो पूंजीगत व्यय था, उसमें इस बार 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है, कुछ कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह स्थिति क्यों आई ? हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था और आज हम कहां खड़े हैं, तो हमने जितना भी development किया है, वह सन् 2018 तक के पहले का है। सन् 2018 के बाद development दिखाई नहीं देता था। माननीय सभापति महोदय, उसका कारण है कि सन् 2018 के बाद पूंजीगत व्यय कम होते चला गया। आज उमेश पटेल जी लोन की बात कर रहे थे कि इस छत्तीसगढ़ के ऊपर near about 1 लाख 13 हजार करोड़ का कर्ज है, आज उसके बारे में बात कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सन् 2018 तक हमारी सरकार थी, 43 हजार करोड़ रूपये का कर्ज था। हमको 7 हजार करोड़ रूपये विरासत में मध्यप्रदेश से मिला था। केवल यदि तीन साल जोगी जी के कार्यकाल को भी मान ले तो 18 साल में 43 हजार करोड़ रूपये का कर्ज था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, माननीय भूपेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितना लोन उठाया ? सभापति महोदय, कोई भी सरकार लोन उठाये, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन लोन उठाने के बाद वह पैसा कहां जाता था, यह चर्चा का विषय है। वह पैसा जाता कहां था ? यह एक चर्चा का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि 15 साल का विकास, वास्तव में इस छत्तीसगढ़ की जो तरक्की है, finance parameters हैं, इसकी नींव बनाने का काम पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। फिर उसके बाद, अब यह तो नहीं कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राहू और केतु के बीच में फंसकर 5 साल फिर से विकास अवरूद्ध हो गया, उस सरकार ने लोन तो उठाया, लेकिन यह विचारणीय प्रश्न है कि वह लोन

का पैसा कहां गया ? वह विकास क्यों नहीं दिखाई देता है ? माननीय सभापति महोदय, वह पैसा कहां दिखाई देगा ? सवा साल से...।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी ।

श्री अमर अग्रवाल :- finance तुम्हारे बस की बात नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अतेक बड़े रोड बने हावय ते हर हमर भइया ला दिखत नई हे। छत्तीसगढ़ मा 15 साल पूरा गड्ढा करके चल देहे रहा।

सभापति महोदय :- आपका भी इसमें नाम है। आप अपने समय में बोलिएगा।

श्री रामकुमार यादव :- हमन पांच साल मा लोन नई लेहे रहे हन तेला तुमन एक साल मा ले लेहा अऊ ऊहूं लोन ला लेके अपन जेब मा भर लेहे हौं। लोन कहीं दिखत ही नई हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप अपने समय में बोलिएगा। आपका भी नाम है।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, अमर अग्रवाल जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं और हमें सुनना भी चाहिए। लेकिन मुझे केवल एक ही शब्द में आपत्ति है। उन्होंने कहा कि यह वित्त का मामला है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यहां चुनकर आए हुए सभी सदस्य विद्वान हैं। कम से कम आप जैसे शब्द का प्रयोग कर लीजिये। सेठ जी, वह मानसिकता से निकलिये। आप तुम, तुम्हारे वाली बात मत करिये।

श्री अमर अग्रवाल :- चलिये, मैं मान लेता हूं कि उनको रेस्ट हाऊस की वित्तीय समझ बहुत अच्छी है। मैंने रेस्ट हाऊस वाला वीडियो देखा था। मैं भूल गया था। उनकी वित्तीय समझ अच्छी है।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, एक मिनट। ये धरती जानत हे कि कोन माल-पानी वाला हे। आप मोला बोलवावौ झन। गुण खाय चांटा अऊ पीटान खाय चरिहा। माल ता तुमन खावओ अऊ चरिहा मोला बनाय हवओ। छत्तीसगढ़ के जनता जानत हे कि ये गरीब ला कतको बदनाम कर लेवओ, लेकिन जेन दिन तुमन माल-पानी वाला निकलिहा, तेन दिन बताहौं।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वह लोन का पैसा कहां गया? आज अगर आप इस विधान सभा में सवा साल के कार्यकाल को देखेंगे तो उधर के कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, इधर के ज्यादा प्रश्न आते हैं। धरमलाल जी का, अजय चन्द्राकर जी का, राजेश मूणत जी का प्रश्न आता है, वह प्रश्न किसके कार्यकाल के थे? जो भी प्रश्न कर लीजिये, उसका जवाब भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं। चूंकि अब हमारी सरकार बनी है। हमको जो भी व्यवस्था मिली, जैसे भी मिली, उसको हमको सजाना भी है, हमको संवारना भी है, जो पुरानी है, उनको धोलना भी है और इस छत्तीसगढ़ की प्रगति भी करनी है। हमको जो विरासत में मिला है, वह एक अलग विषय है। लेकिन वास्तव में मुझे आश्चर्य तब लगा जब अजय चन्द्राकर जी का जल जीवन मिशन के संबंध में एक प्रश्न लगा था। उसमें भ्रष्टाचार तो है ही। जिन्होंने बिना स्त्रोत के टंकी बना दिया होगा तो इन लोगों ने जो

भी किया होगा, वह मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज उसका जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। अब स्वाभावित है कि जवाब तो हमें देना पड़ता है। हम सरकार में बैठे हैं, जो सत्यता है, वह बोलना पड़ता है। लेकिन मुझे तब आश्चर्य हुआ कि भ्रष्टाचार उनके समय का है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और बहिर्गमन वह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी उन्होंने किया और जब मंत्री जी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया तो वह कह रहे हैं कि हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में इस छत्तीसगढ़ की एक तरफ जो फाइनेंस की Parameter हैं, जिसमें देश में नाम है। छत्तीसगढ़ ने जो विकास किया, उसका देश में अपना एक स्थान बना। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि जहां हमने इस छत्तीसगढ़ का सन् 2018 तक नाम रोशन किया, उस छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार की गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। यह छत्तीसगढ़ की पहचान पांच साल में बना दी गई। कल मैं देख रहा था कि इस बजट में बहुत सी नवीन योजनाएं हैं। इस छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए एक कल्पना की गई है कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाना है। इसके एक साल में देश के जितने बुद्धिजीवी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, पब्लिक हैं, उनके साथ हमारी सरकार ने जगह-जगह सेमिनार करवाया कि आगे आने वाले छत्तीसगढ़ की हम कैसे तरक्की करें? हमने उसका एक रोडमैप बनाया और उस रोडमैप के आधार पर यह जो विकसित छत्तीसगढ़ है, उसकी नींव का प्रयास हमने कल के बजट से प्रारंभ कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, "GATI", जिसके चार पैरामीटर हैं। उसके माध्यम से यह छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में कैसे परिवर्तित हो, इसके बारे में पूरी कार्ययोजना इस बजट में हमको दिखाई देती है। माननीय सभापति महोदय, मुझे कल थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री मोबाईल टॉवर एक योजना है, यह कितनी अच्छी योजना है, हम सब जानते हैं, हम मोबाईल का उपयोग करते हैं ? माननीय सभापति महोदय, कई जगह कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, गांव तो बहुत दूर की बात है, इस विधान सभा रोड में भी आयेंगे, कुछ एरिया ऐसा आता है, उसमें कनेक्टिविटी नहीं आती है । माननीय सभापति महोदय, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो दूरस्थ अंचल है, आज डिजिटल युग है, ग्लोबलाईजेशन युग है, हमें दुनिया के साथ चलना है तो एक योजना बनाई कि जो प्रायवेट कंपनी है, प्लेयर हैं, वह अपने हिसाब से कामर्शियल टॉवर लगाते हैं, उनका अपना एक पैरामीटर है । माननीय सभापति महोदय, जब सरकार की ओर से मोबाईल टॉवर योजना बनाई गई, मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करता हूँ कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पूरी कनेक्टिविटी मिले और जो दुनिया के साथ चले, यही विकसित छत्तीसगढ का सपना है और हमें उसे पूरा करना है । (मेजों की थपथपाहट)माननीय सभापति महोदय, मैंने कल पूर्व मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई और टिप्पणी करे तो समझ में आता है । सभापति महोदय, जो पांच साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, अनेक जिम्मेदारी के पद पर रहे हों, जब इस मोबाईल टॉवर के बारे में पूछा तो उनकी टिप्पणी से हतप्रभ रहा गया ? माननीय सभापति सभापति महोदय, माननीय पूर्व

मुख्यमंत्री जी संयोग से बैठे हुये हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कृपा करके यह बता दो, इस योजना में अडानी और अंबानी का फायदा कैसे होगा ? आपने जो टिप्पणी की है, मुझे कृपा करके बता दो ? माननीय सभापति महोदय, मैं भी समझना चाहता हूँ । यह गरीबों के लिये कनेक्टिविटी है...।

श्री भूपेश बघेल :-माननीय सभापति महोदय, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं...।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ । मैं तो आपकी जो वरिष्ठता है...।

श्री भूपेश बघेल :- अमर जी, यदि आप कहें तो अभी उत्तर दे दूँ या मेरी जब पारी आयेगी तो आपको उत्तर दे दूँगा । यह है कि कल बैठियेगा ?

श्री अमर अग्रवाल :- मैं कल नहीं रहूँगा, यदि उत्तर देना है तो अभी दे दो ।

श्री भूपेश बघेल :-आज भाषण देकर भागना मत ?

श्री अमर अग्रवाल :- भागना मेरी आदत नहीं है । आप और मेरे लिये कोई नया नहीं है, हम और आप पांच साल छोड़कर विधायक रहे हैं । भागना मेरा स्वभाव नहीं है । माननीय सभापति महोदय, यदि इसमें नई योजना देखें तो मुख्यमंत्री परिवहन योजना है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो राज्य परिवहन निगम को हमने समाप्त किया, जो भी कारण रहे हो, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आज पूरी यातायात व्यवस्था है, उसे निजी संस्थायें चला रही है । माननीय सभापति महोदय, निजी संस्थाओं की अपनी प्राथमिकता है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है । कुछ गांव ऐसे हैं, जो यातायात से नहीं जुड़े हैं, उसके लिये मुख्यमंत्री परिवहन योजना है, जिसमें गांवों का अंतिम व्यक्ति कम से कम जहां उसको बस मिल जाये, वहां तक आ जाये । सभापति महोदय, वास्तव में जिनके ऊपर दृष्टि नहीं गई है, वह दृष्टि दूर तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां बहुत से नेशनल हाईवे बने हैं और वास्तव में छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे हैं, मैं इसके लिये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और इस देश के परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गड़करी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज लगभग-लगभग 20 हजार करोड़ की तो इस साल की स्वीकृति है तथा 30-35 हजार करोड़ के काम आये हैं, आज सारे नेशनल हाईवे समृद्ध हो गये हैं । माननीय सभापति महोदय, इससे छत्तीसगढ़ की जो प्रगति है, यह उसका बहुत बड़ा आधार बनेगा । अभी भारतमाला जो बन रही है, यह 7 घण्टे में विशाखापटनम पहुंचायेगी, आज अगर एक्सपोर्ट करें तो इसकी भी लागत कम होगी और उससे हमारे छत्तीसगढ़ की प्रगति होगी । माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद जो सिमगा है, नांदघाट है, वहां नेशनल हाईवे रोड बन गई है, लेकिन उनकी जो मुख्य सड़क थी, जो पी.डब्लू.डी. में आती है, नगरीय निकाय में आती है, आज वह जर्जर अवस्था में है, उन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो हमारे स्टेट हाईवेज हैं, जो हमारे कस्बे हैं , उन सारी बातों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री बाई पास और रिंग रोड़ निर्माण योजना लाई गई है । अनेक योजनाएं हैं, जो नये तरीके से विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लिए

नींव डालने का काम किया । सभापति जी, मैंने यहीं से शुरूआत की थी कि किसी सरकार के सामने वर्तमान जरूरतों को पूरा करने की चुनौती होती है और भविष्य के लिए योजना बनाना, इसका बहुत अच्छा संतुलन कल के बजट में दिखाई देता है । हालांकि विपक्ष से केवल उमेश पटेल जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन मैं कल टिप्पणी देख रहा था, मैंने टिप्पणी देखने की कोशिश की कि जनता क्या सोचती है, अर्थशास्त्री इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं ? राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली पार्टियां क्या सोचती हैं, जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं ? मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रदेश के जो सारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होनें बहुत व्यापकता के साथ इस बजट की प्रशंसा की है और सबने माना है कि यह 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के बजट की एक बहुत बड़ी पहल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने की है । सभापति जी, सबने प्रशंसा की । ठीक है, बजट में कुछ कमियां होंगी, विधानसभा में चर्चा होती है, उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए । सरकार की कोई कार्यप्रणाली में अगर कहीं कोई त्रुटि दिखाई देती है तो स्वाभाविक है कि विधान सभा उसी के लिए है, लेकिन लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कल मैंने नेता प्रतिपक्ष जी की टिप्पणी देखी । उनकी टिप्पणी थी कि यह जो बजट है, यह गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ [xx] हैं । अब वे अभी सदन में नहीं हैं । कैसे [xx] है ? क्या यह सरकार 21 क्विंटल धान 3100 रूपए प्रति क्विंटल में खरीद रही है, वह [xx] है ? युवकों के लिए जो नालंदा परिसर बना रहे हैं, निफ्ट बना रहे हैं, आई.टी. पार्क बना रहे हैं, क्या वह [xx] है ? सभापति महोदय, हम महतारी वंदन का पैसा न केवल 1000 रूपए दे रहे हैं, बल्कि हमारी सरकार ने घोषणा की है कि 25 हजार का लोन बिना गारंटी के उनको रोजगार करने के लिए देंगे । यह इस सरकार की योजना है कि इस महतारी वंदन के पैसे के कारण उनको लोन की पात्रता बनती है । आगे स्व सहायता समूह के माध्यम से ढाई लाख की पात्रता बनती है । हम उनको लोन भी दिलवाएंगे, हम उनको ट्रेनिंग भी करवाएंगे, उनके मार्केट के लिए अवसर भी उपलब्ध कराएंगे, दुकान भी उपलब्ध कराएंगे और जो 1 हजार रूपए है, उससे हमारी बहिनें अपना काम करके उसको 5 हजार रूपए महीना बना सकें, उसके लिए हमने इस योजना को चालू किया। क्या यह [xx] है? माननीय सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि कौन सा [xx] है ? हां, यह जरूर है कि उनके व्यक्तिगत जीवन में उनकी पार्टी के द्वारा कोई [xx] होते रहे हों तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है ।

श्री रामकुमार यादव :- 50 रूपया बिजली बिल ल 500 रूपए करे हव, ओला पहिली मोला बतावव त । आप मन एक हाथ मा लेके दोनों हाथ मा ले लेथव ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, कुछ क्षेत्र हैं, जिसमें हम तेजी के साथ काम करना चाहते हैं । मैं मानता हूं कि हमें संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी और हम बढ़ाएंगे । अगर इस साल भी देखेंगे तो जो हमारी जो प्राप्तियां हैं, वह 12-13 प्रतिशत के ग्रोथ पर है, सारे टेक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, आगे और प्राप्तियां बढ़ाएंगे , लेकिन मैंने पहले ही कहा

है कि यह जो विकास का अवरूद्ध है, वह पिछले पॉच साल में रूका । उसको दूर करने में हमें थोड़ा समय लगेगा । एक शायर ने ठीक कहा है कि - खता लमहों ने की, सजा सदियों ने पाई। खता तो इन लोगों ने की है और सजा छत्तीसगढ़ की जनता पा रही है । उसको दूर करने का काम अगर कोई करेंगे तो विष्णु देव जी की सरकार करेगी । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति□☐ महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय वित्त मंत्री जी की बात को सुन रहा था और जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी, आपको पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि लिखावट बड़ी खूबसूरत है लेकिन काश उस लिखावट की तरह बजट भी उतना खूबसूरत होता क्योंकि उसमें मार्क्स थोड़े कम रह गए। पूरे बजट भाषण को जब हम लोगों ने पढ़ा, तो शब्दों का जाल एवं उन्होंने कई नई योजनाओं की बात की है लेकिन बाकी पूरे बजट में लगभग self praise mode में रहे। शुरुआत से ही एक self praise mode रहा, जहॉ ऐसा लग रहा था कि अमृतकाल से ही भारत का इतिहास शुरू होता है या मोदी जी जब प्रधान मंत्री बने, तभी से विकास की गाथा शुरू होती है। भाषण की शुरुआत में छत्तीसगढ़ की माटी की भी बात की गई, हम सबको छत्तीसगढ़ की माटी पर गर्व है। हमें स्वामी विवेकानंद, माता शबरी, माधवराव सप्रे इन सब पर गर्व है, हम लोग इनसे सीखते हैं लेकिन वहीं राजनैतिक होते हुए ई.वी.एम. और बैलेट की चर्चा करके पहली बार 10 सीटें जीतने का इतिहास भी हमें बताया गया। थोड़ा सा फैक्ट चेक करना चाहिए, सारी सीटें तो हमने भी जीती थीं। यह समय-समय की बात है। Anti-incumbency और pro-incumbency भी बताई गई कि आदरणीय श्री मोदी जी दूसरे प्रधान मंत्री हैं, जो कि तीसरी बार शपथ ले रहे हैं लेकिन पहले का जिक्र करना उचित नहीं समझा। बहुत सारे ऐसे प्रदेश रहे हैं, जहां पर कॉग्रेस की सरकारें लगातार रही हैं। अच्छे काम हुए हैं। कभी सरकारें नंबर में कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा होती हैं, ये तो एक democracy की प्रजातांत्रिक वैल्यू है। एक समय था, आप भी बहुत कम पर थे, देश में सिंगल डिजिट पर थे, आज आप बहुमत में हैं। ये तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि किसी को कार्य करने का मौका दिया जाता है और किसी को विपक्ष की भूमिका दी जाती है लेकिन इसमें तिरस्कृत करना कि हम लोगों ने कोई गलत काम किया और हर बार इस बात को बोलना, आपकी इस बात का मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, अगर हम आधार/नींव की बात करें, तो मैं आदरणीय नेहरू जी का उल्लेख करना चाहूंगा। नेहरू जी ने जब प्रधान मंत्री पद की शपथ ली, तो हमारे देश पर 400 करोड़ का ruled rate था। उस समय गाना आया था -

"मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिश्तानी,
सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी"

मैं एक दिन बैठकर एक विश्लेषक का देख रहा था कि हमारे पास की टेक्नालॉजी हम जापान से ला रहे थे, हमारी financial help ब्रिटेन कर रहा था, हमारी military help रूस कर रहा था और हिन्दुस्तान में जिस दिन से हमारे नेहरू जी ने शपथ ली, उस दिन से five year plane के माध्यम से काम होने चालू हुए। अब WhatsApp university पर चाहे जो फैला दें, लेकिन IIT, IIM, भाखड़ा नांगल डेम का सपना देखने वाले व्यक्ति पर अगर आप लोगों को यह लगता है कि उनने नीव नहीं डाली है, तो ये problem आपकी हो सकती है, हमारी तो नहीं है।

सभापति महोदय, मैं अगर आगे बात करूं तो आपने जी.डी.पी. की बात की कि हम लोग सन् 2000 में 21 हजार करोड़ से आज करीब 5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। हम लोग एक बात power of compounding को भी भूल जाते हैं। किसी भी ग्रोथ में हमें power of compounding एवं inflation को साथ में देखना ही होगा। हम लोग मेडिकल कालेज, AIIMS, IIT, HNLU इन सबकी बात करते हैं, तो हम उनका योगदान क्यों भूल जाते हैं? क्या हम डॉ.मनमोहन सिंह जी का योगदान भूल सकते हैं कि उन्होंने हर लोक सभा में कैसे चाहा कि यहॉ पर एक मेडिकल कॉलेज खुले? क्या हम पी.वी. नरसिंह राव जी के योगदान को भूल सकते हैं कि जब भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो उन्होंने किस तरह से देश को बाहर निकाला? हम इंदिरा गांधी जी के योगदान को कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे राजीव गांधी जी के योगदान को भूल सकते हैं?

श्री राम कुमार यादव :- महाराज, इमन कथे कि हमन एक केस में चिट्ठी भेजे रहेन, इमन घलो नई मानिन। हमन चिट्ठी दे रहेन कथे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी quote करना चाहूंगा। उन्होंने UN में कहा था कि भारत की आजादी के 70 वर्षों के दौरान कई दलों के नेतृत्व में कई सरकारें आईं, क्योंकि हम एक सतत लोकतंत्र रहे हैं। हर सरकार ने भारत के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। अब चाहे वह नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, शास्त्री जी हो, व्ही.पी. सिंह जी हो या चन्द्रशेखर जी हो, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, सभी की सरकारों ने अपना योगदान दिया है। जब छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात आयी तो आपने अटल जी की बात की। हम मानते हैं कि अटल जी ने राज्य बनाने की परिकल्पना की या राज्य बनाया लेकिन उस समय हम दिग्विजय सिंह जी के योगदान को क्यों भूल जाते हैं, हम रविन्द्र चौबे जी को क्यों भूल जाते हैं, हम खूबचंद बघेल जी और बिसाहु दास महंत जी को क्यों भूल जाते हैं, हम ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर को क्यों भूल जाते हैं ? उन्होंने भी छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना की थी। एक लंबे समय से लड़ाई लड़ी थी और छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया था। हमें इन सब को पार्टी से ऊपर उठकर याद करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। यह हम सब के पुरखे हैं।

समय:

4.00 बजे

सभापति महोदय, मैं अगर बजट के आंकड़ों पर आऊं, तो हमारे जी.एस.डी.पी. में नेशनल एवरेज करीब 10 प्रतिशत है, हम इस बार 12 प्रतिशत के आस-पास आये हैं । हम लोग यदि रिसिव्हज की बात करें और बॉरोईंग को हटा देते हैं तो हम लोगों का 2024-25 में एस्टीमेट 16 प्रतिशत का रिवाईज्ड आया था और इस बार हम लोग फिर से रेवेन्यू सर प्लस होने की बात कर रहे हैं। अगर हम पॉलिसी हाईलाईट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग वेलफेयर में पैसा दिया गया है। एजुकेशन और यूथ अफेयर्स को पैसा दिया गया है। हम लोग महतारी वंदन के माध्यम से महिलाओं को पैसा दे रहे हैं और मैं टैक्स प्रपोजल में VAT के माध्यम से कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। आदरणीय वित्त मंत्री जी, आपने जब पिछली बार नेट एक्सपेंडीचर की बात की थी तो वह 1,47,000 करोड़ के आस पास आया था, जिसको रिवाईज्ड करके 1,51,700 करोड़ के आस पास चला गया। हमारा 3 प्रतिशत का एक्सपेंडीचर बढ़ा। इस बार के बजट में चूंकि हम 1,65,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो लगभग 9 प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद है। अब यदि हम लोग अपने नेट रिसीट पर चले जाते हैं, तो जो प्राप्तियां हुई, वह कुछ कम हुई। वह 1,26,000 करोड़ की जगह 1,21,000 करोड़ के आसपास हुई और वह हमारा 4 प्रतिशत डेफीसिट गया। अगर हम देखे तो हमने खर्चे को अनुमानित 3 प्रतिशत ज्यादा किया। हमें प्राप्तियां 4 प्रतिशत कम हुई। इसके बाद जो हम रेशियो लेकर आ रहे हैं, जो 9 प्रतिशत और 16 प्रतिशत है। मैं कहीं न कहीं इस फिगर से थोड़ा बहुत चिंतित भी हूं और मुझे ऐसा लगता है कि यह अनरियलिस्टिक फिगर होगा।

सभापति महोदय, अगर हम आगे सेक्टर वाईस बात करें तो आपने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर में करीब-करीब 15 प्रतिशत का ग्रोथ दिखाया है। एक बात सोचने वाली है। यदि आप यूथ की बात कर रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, जिनकी मैं आगे बात करूंगा और जिनकी हम लोगों ने बजट में अपेक्षाएं की थीं, वह आप लोग नहीं कर पाये। मेरे पूर्ववक्ता रूरल डेव्हलपमेंट पर बोल चुके हैं इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपने रूरल डेव्हलपमेंट में करीब-करीब 100 करोड़ और एनर्जी में -25 से 1,000 करोड़ का रिडक्शन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में अभी-भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें यदि आप बजट इम्प्लीकेशन में ज्यादा पैसे देते हैं तो जो दूरस्थ अंचल है, जहां पर लाईट की समस्या आज भी है, जहां सब स्टेशनों की मांग है, हमें वहां पर कैपिटल इनवेस्ट करना ही होगा।

सभापति महोदय, मैं राजीव गांधी जी की एक बात को कोट करना चाहता हूं क्योंकि युवाओं की बात हो रही है। सभापति महोदय, मैं भी विधान सभा में पहली बार आया हूं । India is an old country but a young nation. We are impatient, I am impatient and I to have a dream

in India to say strong independent and self reliant. हमें self reliant बनना ही होगा। यह बात राजीव जी ने यू.एस. कांग्रेस में जाकर कही थी। अगर मैं टैक्स ब्रेकअप की बात करूं तो जो हमारा स्टेट का own टैक्स है, वह बजटेट और रिवाईज्ड में -7 प्रतिशत गया है और अब हम उसको 17 प्रतिशत ऊपर मान रहे हैं कि आने वाले समय में वह 17 प्रतिशत से ज्यादा आयेगा। यदि हम स्टेट के own known tax की बात करें तो -6 प्रतिशत पर है, जिसको हम लोग 26 प्रतिशत पर increase करने की बात कर रहे हैं। शेयर इन सेंट्रल और ग्रांट स्टेज तो लगभग 14 और 11 प्रतिशत पर है। मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं हमेशा स्टेट जी.एस.टी के बारे में बोलता हूं। वित्त मंत्री जी, जब पिछली बार हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे तो जनवरी तक हम लोग लगभग 9 प्रतिशत पर थे और अब जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ आ रही है, उसमें हम अभी अपने टार्गेट से करीब-करीब -3 प्रतिशत के पीछे जायेंगे। सेल्स टैक्स और वैट टैक्स में हम लोग -35 प्रतिशत और आने वाले समय में हम वह -35 प्रतिशत रिकव्हर होंगे, ऐसा बजट में अनुमान लगाया जा रहा है। मैं स्टेट एक्साईज की बात करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमें टैक्सेस के साथ अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी समझनी होगी। अभी हम लोगों ने जितना प्रोजेक्ट किया था, हम उससे -5 प्रतिशत की टैक्स की बात कर रहे हैं और स्टेट एक्साईज में फिर 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, हमारी Social responsibility भी है। हम प्रदेश के लोगों को कितनी शराब पिलायेंगे? यदि हम लोग इस तरह से शराब की दुकानें खोलते जाएंगे, उसमें इतनी ग्रोथ कराते जाएंगे तो उसका सीधा असर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति पर पड़ेगा और जो अभी असर पड़ रहा है। उस दिन बजट में एक रूपये डीजल सस्ता हुआ तो इस सदन में खूब मेज थपथपायी गयी। यहां सबको यह लगा कि एक रूपये से पता नहीं, राहत तो मिलती है, लेकिन एक रूपये डीजल सस्ता होने की कहानी कुछ और भी है। वैट को 24 प्रतिशत से 17 प्रतिशत किया गया। यहां जो उद्योगपति 12 हजार लीटर से ऊपर खरीद रहे हैं उनको साढ़े 6 रूपये प्रति लीटर का फायदा मिल रहा है और जनता को एक रूपये का लॉलीपॉप दे दिया गया है। यहां बार-बार ई.वी. में 35 प्रतिशत छूट की बात की जा रही थी कि हम 35 प्रतिशत छूट देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या देश में टेस्ला आने के बाद ही देंगे या उसके पहले माननीय वित्त मंत्री जी महिन्द्रा-वहिन्द्रा को दे देंगे। या फिर जब देश में टेसला आएगी, एलन मस्क कहेंगे तभी हमें इसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं Revenue deficit की बात करूं तो वर्ष 2023-2024 में यह ऑडिटेड आंकड़ें हैं। मेरे ख्याल से वर्ष 2023-2024 में लगभग 11233 करोड़ का Revenue deficit था। वर्ष 2015-2016 से लेकर वर्ष 2018-2019 में कोविड आया था तो हम लोग सरप्लस में रहते थे। उसके बाद कोविड आया और जिसके बाद इस प्रदेश में Revenue deficit का मामला शुरू हुआ। हम लोगों ने वर्ष 2024-2025 के बजट में एक हजार साठ करोड़ के आसपास Revenue सरप्लस की बात की थी। लेकिन जब वह रिवाईज़ होने के बाद सामने आया तो इसमें 7 हजार 206 करोड़ रूपये का Revenue

deficit है। अगर अभी हम इस साल की बात करें तो फिर से बात कर रहे हैं हम 2 हजार 804 करोड़ रूपये के Revenue सरप्लस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह का बजट आया है जो रिसिट्स और Expenditure का हिसाब आया है इसके बाद हम Revenue सरप्लस पर किसी हाल में नहीं जा सकते हैं। यह मेरी खुली चुनौती है। अगर हम लोग Fiscal deficit की बात करें । चूंकि इसके पहले माननीय सदस्य श्री उमेश पटेल जी ने इसके बारे में चर्चा की है। जो हम लोगों को लगता है कि यह 3.5 प्रतिशत होना चाहिए, जो कि केन्द्र सरकार और नीति आयोग, सब कहते हैं, उसके बाद भी आज हम लोग लगभग 5.3 प्रतिशत पर हैं। अगर हम Revenue fiscal deficit का एस.एन.जी.डी.पी.एस. से देख रहे हैं तो वह प्रतिशत हमारे स्टेट के लिए सही नहीं है। अगर हम Outstanding deaths की बात करें तो उस पर आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा कि हम क्यों 28, 29, 30 तक जा रहे हैं। आपने आदरणीय उमेश पटेल जी को यह कहा कि मैं उसका इंतजार करूंगा कि वह आंकड़ा 20 के नीचे, मेरे ख्याल से 20 के नीचे हमारा एफ.आर.बी.एन. जो है, उनकी जो गाईड लाईन्स हैं, उसके हिसाब से 20 से नीचे होना चाहिए, लेकिन वह आंकड़ा 20 के नीचे नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर हमें ऋण की बात करना बहुत जरूरी होगा, जो मैंने अनुपूरक बजट पर अपने भाषण के दौरान कहा था। यहां पर एक एक वरिष्ठ सदस्य बात कर रहे थे और उन्होंने यह कहा कि पूर्व में अपने कार्यकाल में आपने कितना ऋण ले लिया। आपने ज्यादा प्रतिशत में ऋण ले लिया। मैं उस दिन आदरणीय वित्त मंत्री जी को सुन रहा था उन्होंने यह कहा कि हमें गड्ढे पाटने थे और हमने लोन उठाकर उन गड्ढों को पाट दिया ताकि हमें कैपिटल ज्यादा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, हम कोविड के समय को क्यों भूल जाते हैं ? हमें कोविड के समय को भी याद रखना होगा कि उस समय केन्द्र सरकार ने कहा था कि आप लोग लोन ले लें क्योंकि अभी त्वरित राशि नहीं दी जा सकती। अगर उस समय पर हमारी सरकार (उच्च)Higher प्रतिशत पर लोन लिया था तो प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए वह लोन लिया था । उस समय कोई उस राशि का दुरूपयोग करने के लिए लोन नहीं लिया गया था। फिर यहां पर यह बात होती है कि वह लोन कहां गया? अभी सरकार आपकी है। आप जांच करवा लीजिए। अगर आपको कोई संदेह है। हमें तो यह पता है कि वह लोन छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए उपयोग किया गया। पहले भी यह बात कही गयी है कि कभी भी किसान या जनता के हित के लिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें उसके अनुपात के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आदरणीय वित्त मंत्री जी मैं, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। जैसा कि हमारा आर्थिक सर्वे कहता है कि हम लोग 70 प्रतिशत कृषि और Allied activities में रहते हैं। लेकिन उसका जो योगदान हैं अगर मैं वर्ष 2019-2020 से आज तक के आंकड़े दूं तो हम लोग लगभग 16 से 17 प्रतिशत पर जाते हैं और पिछले साले के मुकाबले इस साल 17.09 प्रतिशत और इस बार हम लोग 16.80 प्रतिशत के

आसपास आये हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी एक बात कहना चाहूंगा कि हमें agro based industires को बढ़ावा देना होगा, हमें उन पालिसीस को बढ़ावा देना होगा। अगर हम लोग उनको बढ़ावा नहीं देंगे तो कहीं न कहीं हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा और जी.एस.डी.पी. में हमारा जो प्रतिशत होना चाहिए, वह कहीं ज्यादा होना चाहिए। आप खुद अनुपात देखिये, यदि 70 प्रतिशत आदमी कृषि और allied activities में इनवॉल्व है तो उसका योगदान अगर कम हो रहा है तो हमें उसको बढ़ाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। आदरणीय वित्त मंत्री जी, पिछली बार आपने मुझे इसी सदन में आश्वासन दिया था कि ग्रीन जी.डी.पी. के बारे में हम कुछ करेंगे। चूंकि पिछली बहुत सारी बातें उस पर हो चुकी हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ग्रीन जी.डी.पी. को implement करना, वर्ल्ड बैंक, आर.बी.आई. सभी लोग कह रहे हैं और हमें ग्रीन जी.डी.पी. को implement करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप हमारे पहले वित्त मंत्री हों, छत्तीसगढ़ पहला राज्य हो जहां पर हम ग्रीन जी.डी.पी. को implement करके आगे जायें।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जंगल, मैदान, पहाड़, religious toursim इन सारी बातों की अपार संभावनायें हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम पालिसी लैक कर जाते हैं जब पर्यटन की बात आती है। हम लोग बार-बार एक गांव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पुरानी चीजों की बात करें तो हमारे पास मंदिर हैं, जंगल हैं जिनको नेशनल पार्क में डेव्हलप किया जा सकता है। लेकिन नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व होने के बाद भी आज वह बात नहीं है कि यहां पर टूरिस्ट बाहर से बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज हम सबको यदि कहीं जाना होता है तो हम लोग कान्हा या बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाने की बात करते हैं। क्यों नहीं हम लोग बस्तर, अचानकमार चाहते हैं? हमें इस बारे में पॉलिसी मेटर्स में बात करनी होगी। मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक मामले में लेकर जाना चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर उनको ठीक लगे तो इसी बजट में उसको शामिल करें। हम डी.एम.एफ. फंड की बात रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात कहीं कि कहीं पर एक पूरा कॉलेज उससे construct हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम जिलों में डी.एम.एफ. फंड का दुरूपयोग कभी-कभी होता दिखता है। हमें एक पॉलिसी मेटर बनाना चाहिए, पॉलिसी जिले स्तर पर हैं, सेन्ट्रल की गाईडलाईन्स भी हैं। लेकिन स्टेट से भी हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हम कॉलेज बनाने की बात कर रहे थे। मैंने अभी डी.एम.एफ. में कई जिलों की जानकारी मांगी थी। हमने वहां देखा कि वहां पर स्कूल में शेड निर्माण हुए हैं। यह बहुत छोटा सा मेटर है, लेकिन बहुत सीरियस है। स्कूल में शेड निर्माण हो रहे हैं लेकिन जब वहां पूछा गया कि क्या वहां पर क्लासरूम, बिल्डिंग उपलब्ध हैं तो पता लगा कि वहां पर अतिरिक्त कक्ष में वह स्कूल चल रहा है, लेकिन वहां पर शेड निर्माण हो रहा है। इस बात को हमको अपने पॉलिसी मेटर में ध्यान रखना होगा। मेरा आपको एक सुझाव है कि सबसे पहले बच्चियों के लिए टायलेट, बिल्डिंग और उसके बाद सेनेटरी पैड की वेडिंग

मशीन हमें हर स्कूल में इनस्टॉल करने की जरूरत है। अगर हम यह डी.एम.एफ. फंड से कर जाते हैं, कारपुस बहुत बड़ा है और काम बहुत छोटा है। इसको हम कर सकते हैं। अगर आप यह करवायें तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब हम गौण खनिज की बात करते हैं तो उसमें हम लोग अधोसरंचना में उस मद को खर्च करते हैं। मैं आपको अकलतरा का उदाहरण देता हूं, वहां से 3-4 करोड़ रुपये साल दो साल में गौण खनिज से प्राप्त होता है। कई ऐसे गांव हैं जहां साल में 2 से 3 करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है। हमें वह ह्यूमन रिसोर्स के लिए खोलना जरूरी है। वहां पर क्यों नहीं 1 लाख रुपये तनख्वाह देकर डॉक्टर बैठा सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम के गणित की और अन्य विषयों के अच्छे टीचर्स बैठा सकते हैं, ट्यूशन्स दे सकते हैं। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स गौण खनिज में खोल देते हैं तो आदरणीय वित्त मंत्री जी, यह हमारे स्टेट के लिए, हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर बार-बार मोदी की गारंटी की बात होती है। आदरणीय बहुत सीनियर सदस्य हैं, उनसे बहुत सीखने को भी मिलता है। वह छलावे की बात कर रहे थे कि हमें क्या लगता है कि कहां [xx] है ? मैं आपके माध्यम से उनको जवाब भी देना चाहूंगा कि जो 1 लाख शासकीय नौकरी देने की बात की गई थी, वह आज नहीं हो रही है, यह [xx] है। 3 हजार भर्तियां करने के बाद उनको निकाल दिया, उनके बारे में आज नहीं सोचा जा रहा है, यह [xx] है। इसी सदन में कहा गया था कि 33 हजार शिक्षक की भर्ती होगी, आज उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है, यह [xx] है। इस बार 10,000 रिक्त पदों को भरने की बात की गई है। [xx] यह भी है कि घोषणा पत्र में लिखा गया था कि संविदा कर्मचारियों को 100 दिन के अंदर नियमित किया जायेगा, जिसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है, यह [xx] है। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ 24 वर्षीय हो गया है। जी.एस.टी. के, वैट के जो केसेस थे, वैट के केसेस तो हमने 25000 रुपये से कम वाले माफ करने की बात की। सभापति महोदय, यह बात किसानों पर क्यों लागू नहीं होती ? जिनके छोटे-छोटे ऋण को-ऑपरेटिव बैंक में पड़े हुए हैं, हम उनको माफ करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कई जगह लिपिकीय त्रुटि की वजह से वह लोन खड़े हुए हैं। हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। 500 रुपये में गैस सिलेण्डर देने की बात हुई थी, यह [xx] है कि उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। महतारी वंदन योजना का पोर्टल बंद है, आज उसके बारे में बहुत कुछ बातें हो गईं तो उस बारे में न जाकर मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब हम महतारी वंदन की बात करते हैं तो इसमें दो लोगों को और इंक्लूड करना पड़ेगा जब हमारी बच्चियों की मैरिजेबल एज 18 साल है तो हम 21 साल के बाद ही महतारी वंदन क्यों दे रहे हैं ?

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इसमें जो दिव्यांग महिलायें हैं, जो अविवाहित भी हैं, जो दिव्यांग महिलायें अविवाहित हैं उनको भी हमें इस योजना का

लाभ देना चाहिए क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि बाकी लोगों के तो घर पर भी लोग हैं जो कमाकर उनको दे सकते हैं, करीब 17 प्रतिशत बिजली के बिल में बढ़ौत्तरी और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विभाग है, उर्जा । आप कृपया उसमें थोड़े से पैसे और दिलवायें ताकि खूब विकास हो सके और बिजली की समस्या से हम लोगों को छुटकारा मिल सके । राजस्व प्रकरणों की बात है, अभी अकलतरा में 3 दिन पहले हम लोगों ने यह मामला उठाया, उसका इतने दिनों से प्रकरण लंबित था कि उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश की । आपके ही दल के एक विधायक ने यह बात पूछी कि राजस्व प्रकरणों को निपटाने के लिये सुशासन शुल्क कितना लग रहा है ? यह बात केवल किसी दल की नहीं है, जिस भ्रष्टाचार को हमें नीचे तक रोकना है उसके लिये हमें शुरूआत करनी होगी और अभी की पॉलिसी में, अभी के बजट में वह बात कहीं नहीं दिख रही है । बार-बार पेपर में छपा कि आबकारी में जो प्रीमियम है उसमें आपने टैक्स कम कर दिया । हम एक-तरफ आबकारी से ज्यादा पैसे वसूलने की बात करे हैं, ऊपर से हम टैक्स भी कम करते जा रहे हैं, दुकानें खोलते जा रहे हैं, अहाता खोलते जा रहे हैं, यह एक सोशल रेस्पांसबिलिटी है जिसे हमें लेना होगा । केंद्र सरकार ने जो महंभाई भत्ता नवंबर में बढाया, उसको हमने अभी बढ़ाया । हमने कोई एरियर्स की बात नहीं की । क्यों नहीं हम भी उसको नवंबर से बढा सकते हैं ? कानून व्यवस्था की हालत चूंकि साइबर थाने और बाकी बातें बोली जा चुकी हैं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा लेकिन कहीं न कहीं हमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का भी अब सहारा लेना पडेगा क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का सहारा नहीं लेंगे तो साईबर क्राईम्स को रोकना आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के बिना संभव नहीं है । यह बात दुनिया के सारे अर्थशास्त्री, बड़े उद्योगपति और बुद्धिजीवी लोग यह बात कह चुके हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक तो चंद्राकर जी अच्छा बजट नइ बनान देवय अउ जो गोठियाथन तेला सुनन भी नइ देवय । यह सबके कसूरवार चंद्राकर जी हवय ।

श्री राघवेंद्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं जो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की बात कर रहा था । यह साईबर क्राईम से लेकर बाकी जितने बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्री हैं, वे सब आज आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की बात कर रहे हैं । हमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को अपने स्टेट की गवर्नेंस पर लाना पड़ेगा । हम उसकी बात तो कर रहे हैं लेकिन न तो कोई क्लियर पॉलिसी है, न उसके बारे में कोई प्रावधान है । हम उसको कैसे उपयोग करेंगे, न इसकी कोई बात हो रही है । आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को अपने बजट भाषण में बोल देना एक चीज है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इसको करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । हम इस बजट की यदि बात करें तो सस्टेनेबल डवलपमेंट में यह बजट एक फेलियर है । हमने गरीब-किसान, महिलाओं की तो बात की लेकिन उनके साथ-साथ इंडस्ट्रलाईजेशन और नेचुरल रिसोर्सेस को भी साथ रखने की बात हमें करनी पड़ेगी जो इस बजट में हमें कहीं नहीं दिख रही है । हमें सस्टेनेबल डवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी तभी हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में एक मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्तमंत्री जी को यह बात कहूंगा कि बहुत सारी बातें होती हैं जब हम लोग डॉयरेक्ट फंड ट्रांसफर की बात करते हैं । मैं एक किताब पढ़ रहा था, पुअर इकॉनामिक्स जिसमें अभिजीत बैनर्जी जी को नोबेल प्राईज भी मिला हुआ है । हम जो फ्री कैश देते हैं या हम कैश ट्रांसफकर करते हैं कई जगह वह बहुत सक्सेसफुल मॉडल है और कई जगह पर उसका नेगेटिव इंपेक्ट आता है । हमें एक जरूरत और है, हम छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं उसका बहुत-बहुत स्वागत है । लेकिन क्या हम उससे प्रोडक्टिविटी नहीं जोड़ सकते ? जैसे अभी एक आदरणीय सदस्य बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि चूंकि उनको 12 हजार मिल रहा है, वह ढ़ाई लाख तक का लोन लेने की पात्रता रखते हैं तो अगर वे यह पात्रता रखते हैं तो क्या हम उनको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में या किसी रोजगार में उनको क्यों नहीं ला सकते हैं जिससे वे उस पैसे का और सदुपोग कर सकें ? अभी हम वह पैसा सिस्टम में फ्लश कर रहे हैं लेकिन उस सिस्टम को हम फ्लश करने के बाद मल्टीप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं । अगर हम उसको प्रोडक्टिविटी एड कर देते हैं तो इसी 12 हजार पैसे से वह महिला कहीं ज्यादा कमा सकती है । क्यों न हम उनको और सशक्त बनाने का काम करें, यह मेरा आपको सुझाव है । आपके जो बेहतर कार्य होंगे, हम उसकी हमेशा सराहना करेंगे, लेकिन जहां पर हमें लगेगा कि बजट और पॉलिसी decisions better हो सकते हैं, हम एक विपक्ष की भूमिका में आपके सामने खड़े रहेंगे। वैसे अभी डिपार्टमेंट का तो भाषण नहीं है, लेकिन दो चीजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसके लिए हम बहुत समय से लगे हुए थे। बजट में उसका प्रावधान आ गया है। लोग लगातार मेरे यहां मर रहे थे, जिसमें अकलतरा बाईपास और एक हमारे यहां परसाही उद्वहन की 13,000 हेक्टेयर की स्वीकृति हुई है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद के साथ-साथ एक निवेदन ये करूंगा कि बजट में आने के बाद उसकी प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति में देरी न हो, क्योंकि वह लोगों से जुड़ा विषय है और इसको जल्दी प्रदान करके ऐसे सभी मुद्दों को जल्दी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करके 2 साल वाला खेल किसी के साथ न खेला जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत सादर धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री राजेश मूणत जी।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय सभापति महोदय, बजट के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सम्माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 25वें वर्ष में हम पदार्पण कर रहे हैं। एक दूरदृष्टि, एक सोच, एक कल्पना को मूर्तरूप देने का काम, एक विजन के साथ में डेवलपमेंट, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में बैठे हुए व्यक्ति को देखते हुए इस बजट की जो परिकल्पना माननीय विष्णुदेव साय सरकार के वित्त मंत्री के रूप में माननीय ओ.पी. चौधरी

जी ने किया है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ये व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने स्वयं ने अपने आलेख से लिखकर 115 पेज commitment किया। ये बजट नहीं है, ये commitment है। ये commitment की बात इसलिए कहता हूं कि जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की नींव रखी, अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं बनेगी, लेकिन अटल जी ने रायपुर की एक सभा के अंदर कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता मुझे आश्वासन देती है, छत्तीसगढ़ की जनता मुझे 11 सीट देती है, मैं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कराउंगा। इस समय उस राज्य के महान निर्माता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए, इस बात को कहता हूं कि वह commitment था और आज फिर ये commitment हमने लिख कर किया है। विष्णुदेव साय की सरकार के वित्त मंत्री ने अपने हाथ से लिखी कलम से अगर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का संकल्प का commitment किया तो इस commitment को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, सब की है। ये सोच है। ये विजन है। ये कल्पना है। (मेजों की थपथपाहट) हर व्यक्ति अपनी-अपनी बात बोल रहा है। मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी सुनता हूं। आपको भी अवसर मिला। 3 साल, एक सरकार और थी। 15 साल बेमिसाल। आपको भी 5 साल मिले। उस 5 साल में नरवा, घुरूवा, बाड़ी तीन शब्द के आगे पहुंच पाये क्या? कौन सा बस्तर के अंदर काम कर दिया, कौन सा सरगुजा में काम कर दिया, कौन सा अंबिकापुर के अंदर काम कर दिया, कौन सा दुर्ग में काम कर दिया? पूरा पी.डब्ल्यू.डी. विभाग खाली। एक जगह दुर्ग और पाटन में चलता था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम लोगों ने सरगुजा में जंगल उजाड़ने काम नहीं किया। अडानी जैसे जंगल नहीं काटे।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आपका भी समय है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जो 5 साल है, उसमें हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने का काम किया था ।

श्री राजेश मूणत :- बहुत अच्छा, बधाई हो, इसलिए आधे जेल में हैं, आधे बेल में हैं और आधे रेल में हैं। यही तो संवारने का काम हुआ।

श्री रामकुमार यादव :- मां के नाम में एक पेड़ लगाओ, पिताजी के नाम में दो पेड़ लगाओ और लाखों पेड़ ला तुमन काटौ।

श्री राजेश मूणत :- बहुत अच्छा, यादव महाराज, क्यों बीच में खड़े होते हो? उस कुर्सी में कुछ है तो सभापति जी, उसे चेक करवा लीजिए। इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि विजन है, जब हम कल्पना के साथ में बात करते हैं, विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ को 24 साल हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ 24वें या 25वें साल के अंदर हम जा रहा है, देश के अग्रणी राज्यों में जब छत्तीसगढ़ खड़ा होता है तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा होता है। पार्टी बेस से ऊपर उठकर देश के अंदर

छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है। हमारे सामने तीन राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। आज गर्व के साथ में मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों के अंदर कहीं खड़े होकर करके बातचीत करता है, अगर मैं बस्तर के वनांचल क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करता हूं, विजन के साथ में बात करता हूं और बस्तर के साथी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के भू भाग का अगर एक सर्वे करें, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे जशपुर हो, चाहे रायगढ़ हो या मैं राजनांदगांव या डोंगरगढ़ की बात करूं तो चारों तरफ डेवलपमेंट के विजन के साथ में कल्पना को साकार करने का बजट के अंदर प्रावधान करना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। अभी एक भाई कह रहे थे कि डीएलएफ में पैसे का कितना [xx] होता था । मेरे मित्र, जितना डीएलएफ के पैसे का [xx] पांच साल में हुआ है, इतिहास के पन्ने में लिखने के लिए है । अभी कई लोग उसी डीएलएफ के चक्कर में आधे लोग जेल में बैठे हैं और कई जमानत के चक्कर में घूम रहे हैं । वो बंदर बांटे रेवड़ी चुन चुन करके दे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके शासनकाल में भी नान घोटाला हुआ था । नान घोटाला हुआ था, आपके शासनकाल में ।

श्री राजेश मूणत :- अरे तो पांच साल में जांच कर लेते, किसने मना किया था? किसी ने रोका था क्या पांच साल ? एक कागज पर लिखकर देते थे कि एफआईआर दर्ज कर लो । राजनीति करते हैं शुचिता की करते हैं, राजनीति करते हैं सिद्धांत और मूल्यों की करते हैं । राजनीति द्वेष भावना की नहीं करते और न ही द्वेष भावना की राजनीति करेंगे । यह सरकार कानून से चलेगी, यह सरकार नियमों से चलेगी, यह सरकार छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का संकल्प लेकर चलेगी । आप भी कुछ फरमा लो ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि मैंने कहा था कि [xx] हुआ था । मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि [xx] हुआ था । मेरा भाषण निकलवा लीजिए । मैं कह रहा हूं कि स्टेट पॉलिसी बननी चाहिए और प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए । जब से आपकी सरकार आई है तब से जो प्रायोरिटी सेट हुई हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि गलत जगह पर काम हो रहा है ।

श्री राजेश मूणत :- मैंने न आपका उल्लेख किया, मैंने तो केवल इतना ही कहा की डीएलएफ फंड की कैसा [xx] हुआ है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- डीएमएफ ।

श्री राजेश मूणत :- डीएमएफ । फंड का कैसे [xx] हुआ है । अगर एक विज़न के साथ कल्पना को मूर्त रूप देने की बात करते हैं तो दूरसथ वनांचल क्षेत्र दंतेवाड़ा में डीएमएफ फंड से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है तो यह विजन नहीं है तो क्या है ? आप सोंचो, कल्पना करो (मेजो की थपथपाहट)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसी दंतेवाड़ा में कलेक्टर निवास में क्या बना था, वह भी बता दीजिए, स्विमिंग पूल बना था आपकी सरकार में ।

श्री राजेश मूणत :- अब आप जहां रहते हो वहां क्या हुआ था, एक एक का उत्तर दूंगा ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप ही की सरकार में स्विमिंग पूल बना, डीएमएफ से बहुत सारे काम हुए हैं । अगर डीएमएफ के बारे में बात करना होता तो मैं पूरी लिस्ट लेकर आती इनके लिए ।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, आप बालोद से आती हैं । अब मैं बालोद के बारे में कुछ गिना दूं क्या ? मैं नहीं चाहता कि उन सब चीजों की परतें उधेड़ूं । मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट का विज़न होना चाहिए, सोंच होनी चाहिए, कल्पना होनी चाहिए । अगर किसी नवजवान साथी ने एक कल्पना के साथ, एक विज़न के साथ बजट रखा है । दूरदृष्टि रखी 2047 की कल्पना को साकार करने के लिए समर्थन मांग रहा है । कुछ कमीबेशी होगी उसको सुधार करना आपका, हमारा, हम सबका कर्तव्य है । उस कर्तव्य में सहयोग देना हमारा काम है, केवल नेगेटिव खोजेंगे तो हर वयक्ति के अंदर नेगेटिव खोजने में 2 सेकेंड लगता है । मैं इस बात को कहता हूं, आपको भी अवसर मिला, आपने क्या किया ? मैं छोटे-छोटे उदाहरण देता हूं । नया रायपुर, अगर विजन की बात करें 21वीं सदी का नया रायपुर जिसकी नींव पूर्व सरकारों ने रखीं ।

समय
4.28 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में नया रायपुर खड़ा हुआ । आपने पांच साल नया रायपुर में क्या किया ? नया रायपुर में एक ईंट नहीं जोड़ पाए । नया रायपुर में स्मार्ट सिटी के पैसे का अपव्यय हुआ । नया रायपुर का कोई एक सेक्टर बता दें, जिसमें काम किया हो । आज ओ.पी.चौधरी जी आए हैं । नया रायपुर में फोटो तो अच्छा छपाते थे । दिल्ली जाकर प्रेजेंटेशन में बताते थे कि नया रायपुर हमने बनाया। अरे, भाजपा ने बनाया, हमने बनाया और हम ही संवारेंगे । यह संकल्प लेकर चल रहे हैं (मेजो की थपथपाहट) । आपने क्या किया, यह स्थिति बन गई थी कि मंत्रालय में झाड़ू नहीं लगती थी । मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं । पांच साल पूरा मंत्रिमंडल रहा और नया रायपुर में 20 बैठकें भी नहीं हो पाईं । जहां मंत्रालय बना है, जहां एचओडी बिल्डिंग बनी है, जहां पर सब लोग रहते थे । आपने क्या किया ? आप तो घर में बैठकर शासन, प्रशासन चलते थे । कभी छत्तीसगढ़ की प्रगति की बात की है । आपने उसको एक कोने में डाल दिया । मैं केवल उसकी बात नहीं करता हूं । माननीय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं । जब दिल्ली में पार्लियामेंट बन रहा था तो कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि कोविडकाल में पार्लियामेंट नहीं बनना चाहिए । छत्तीसगढ़ के अंदर भी सुरसुरी छोड़ी और कहा गया कि नया रायपुर का

डेवलपमेंट रोक दिया जाए । मुख्यमंत्री निवास रोक दीजिए, विधान सभा रोक दीजिए, सब काम रोक दीजिए, आपने काम रोककर क्या कर दिया, आज उसकी 21 प्रतिशत से ज्यादा मूल्य की वृद्धि बढ़ गई। किसके कारण बढ़ी ? आपकी क्या सोच थी, क्या कल्पना थी ? यह छत्तीसगढ़ महतारी का पैसा है, छत्तीसगढ़ ने कमाया है, गाढ़ी कमाई का पैसा है, आपने एक आदेश के अंदर लिख दिया। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, खाली पेपर में सुर्खिया बटोरना था ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- राजेश भैया, निर्माण कार्य को रोकने का कारण आप भी जानते हैं। उस समय प्रदेश और देश की जो हालत थी, केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करने के बजाय हमारी सरकार ने लोगों की जान बचाना मुनासिब समझा।

श्री राजेश मूणत :- केन्द्र की पार्लियामेंट में भी काम चल रहा था। साहब, उन्होंने काम नहीं रोका। मैं उसी बात को दस बार बोल चुका हूं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ताली बजवात रेहेव ताली। ताली बजाए ले कोरोना भागथे का, वहा रे वैज्ञानिक हो।

श्री राजेश मूणत :- अभी समय लगही मोर भाई बैठ जा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने कोरोनाकाल में थाली बजवाने का काम किया है। थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा ? (व्यवधान) यहां काम करने से होता है जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया था।

श्री मोतीलाल साहू :- अध्यक्ष महोदय, कोरोनाकाल में ऑनलाईन दारू बिक रही थी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- कोरोना थाली बजाए ले भागही। ताली बजाव, थाली बजाव। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने बेटियों को बाहर से लाने का काम किया था, किसान, मजदूरों को लाने का काम किया था।

अध्यक्ष महोदय :- आपका अवसर आएगा, मैं अवसर दूंगा, आपका पूरा समय रहेगा, आप बोल लीजिए, राजेश जी कंटीन्यू करिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, जब हम लोग देश के अंदर विजन की बातचीत करते हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि आपका विजन क्या था ? जिन्होंने उस विभाग में काम किया है, आप वहां बैठकर समझ लेना। आप चाहते तो काम अपने आप स्लो हो जाता, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। जब काम स्लो हो जाता तो धीरे-धीरे पेमेंट होता रहता लेकिन आपने क्या किया, काम रोका जाए, आदेश पारित कर दी। ठेकेदार को अवसर मिला, उसका लाभ मिल गया, आज उसकी लागत बढ़ गई। यह दूरदृष्टि नहीं थी, यह सोच नहीं थी। मैं इस बात को इंगित करते हुए बताना चाहता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर वनांचल क्षेत्र है, आपको 5 साल अवसर मिला, अभी लखेश्वर भाई यहां बैठे थे, आप कोई एक सिंगल काम ही गिना दीजिए जो बस्तर के लिए हुआ हो।

श्री विक्रम मंडावी :- राजेश भैया, बस्तर में पहली बार 62 वनोपजों का समर्थन मूल्य मिला। आज कितने लोगों को मिल रहा है बताईए ?

श्री राजेश मूणत :- मित्रवर, भा.ज.पा. सरकार में डॉ. रमन सिंह जी के समय से मिल रहा है। तेंदूपत्ता की तोड़ाई का पैसा, बोनस का पैसा, तेंदूपत्ता के संग्रहणकर्ताओं का बोनस, अगर उस समय चरणपादूका बटी है तो डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में बटी है, आपके खाते में कुछ नहीं है। आप खाली वाहवाही बटोरने का काम मत करिए। (मेजों की थपथपाहट) आपके कार्यकाल में एक स्मारक जरूर बना। मैं कांग्रेस के सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि एक बार जगदलपुर जरूर जाईए।

श्री विक्रम मंडावी :- आप शहीदों का अपमान कर रहे हैं। आप स्मारक का अपमान कर रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं। वो मेरी माताजी के बेटे हैं। मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। भ्रष्टाचार की जननी का....। (व्यवधान) जहां करोड़ों रूपए खर्च करने के बाद पूरे बस्तर के अंदर उन शहीदों के नाम पर स्मारक बनाया हुआ है...। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- यह शहीदों का अपमान है।

श्री राजेश मूणत :- मैं कहता हूं कि एक विधायक दल की कमेटी बनाईए और जाकर देखकर आईए जिन लोगों ने यह सब काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव करिए, अगर ताकत है तो करके दिखा दीजिए।

श्री विक्रम मंडावी :- कमेटी बनाईए।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मिलजुलकर धंधा करना, क्या आपने यही सीखा है ? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, वे भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं और आप भी हमारे नेता हो। विचार अलग हो सकते हैं, सिद्धांत अलग हो सकते हैं, मित्रवर यह सबके लिए सोचने का विषय है। इसलिए मैं कहता हूं, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, साहब कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। अगर एक अच्छा बजट आया और हम एक अच्छे बजट की तारीफ करें, पेपर में सुर्खियां छाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किया होता तो वहां बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। नगर निगम के अंदर भाषण दे रहे थे, मुझे भी रायपुर याद है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की 29 सीट थी, 6 निर्दलीय पार्षद थे, उसमें से 4 लोगों को मुख्यमंत्री जी दर्शन कराने ले गये और उनको ज्वाइन कराया। उनको ज्वाइन कराने के बाद रायपुर का महापौर बना दिया गया। आपके लिए खरीद-फरोख्त करना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जब उसी जनता को अवसर मिला तो उसने हमें साय-साय ऐसा बहुमत दिया कि 1 लाख, 53 हजार वोटों से रायपुर की महापौर जीतकर आती हैं और रायपुर के अंदर 60 पार्षद जीतकर आते हैं। कांग्रेस तो दहाई तक नहीं पहुंच पाई है। उस समय भी महापौर भाजपा का बन रहा था, लेकिन खरीद-फरोख्त की राजनीति पर ज्यादा शौक और विश्वास करने वालों, आज जब अवसर आया तो जनता ने निर्णय करके दे दिया। आप इसपर चिंतन और

मंथन करें। आप रायपुर शहर के विकास की बात करते हैं। आपने 5 साल में रायपुर को क्या दिया? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मैंने कई बार मीडिया से लेकर कांग्रेस के सब मित्रों से कहा कि आप एक काम गिनवाइये, जिसका मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन व लोकार्पण किया हो। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आपने रायपुर के साथ क्या किया?

श्री विक्रम मण्डावी :- राजेश भैया, स्काई वॉक पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा है ?

श्री राजेश मूणत :- बनेगा। ''हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे।'' आप काहे चिंता करते हो? (मेजों की थपथपाहट) आप लोग 5 साल तक जांच करते-करते थक गये। एस.आई.टी. गठित कर दो, यह कर दो, वह कर दो और वही एस.आई.टी. चिट देती है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। मैंने आपसे कहा न कि आप सिद्धांत और विचारों की राजनीति करिये। यदि आप शोषण की राजनीति करेंगे तो जिंदगी भर शोषण ही करते रहेंगे और आपके दिमाग में निगेटिवपन घूमता रहेगा। यदि आज रायपुर के विकास से संबंधित कोई विषय आता है तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि नालंदा परिसर जैसी चीज यदि रायपुर में खड़ी होती है और वहां से टैलेंटेड बच्चे पढ़कर निकलकर आते हैं तो किसको पता है कि वह किस समाज, किस जाति, किस वर्ग के हैं? जब वह पी.एस.सी. में सेलेक्ट होते हैं, आई.ए.एस., आई.पी.एस. बनते हैं तो हमारा सीना गर्व से उठता है कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा आई.एस.एस., आई.पी.एस. बनकर आया है। यदि कोई बच्चा पी.एस.सी. में सेलेक्ट होता है तो हम यह नहीं कहते हैं कि उसने बनाया था, बल्कि हम यह कहते हैं कि हमारे यहां से बच्चा पढ़कर निकला है और छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा यहां तक पहुंचा है। (मेजों की थपथपाहट) आज यदि 18 जगहों में इसे बनाने की बात कही गई है तो यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इस कल्पना को मूर्त रूप देना, जो व्यक्ति दर्द को जानता है, जो grass root level से आया है, जो व्यक्ति एक गरीब परिवार के अंदर रहकर आई.ए.एस. की पढ़ाई करके यहां तक पहुंचा है और एक राज्य सरकार में सचिव स्तर तक के पद पर रहने के बाद भी जनसेवक के रूप में आता है और एक वित्तमंत्री के रूप में बजट रखता है तो यह उसका commitment है। इस commitment को पूर्ण करना भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार का commitment है। इसीलिये मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे गांव-देहात से बच्चियां आती हैं और शहर में पढ़ाई करती हैं। वह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करती हैं, बल्कि नौकरी भी करती हैं। 50 साल पहले यहां पर कोई हॉस्टल नहीं था। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। 50 साल पहले महाराष्ट्र मण्डल ने एक women hostel की नींव रखी थी। चौबे कॉलोनी में वह hostel बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यदि हमारी कोई बहन यहां पर आती थी और नौकरी पेशे में जाती थी तो उसके रूकने के लिए कोई स्थान नहीं था, वह इधर-उधर सोती थी। उसकी safety का काम नहीं हो पाता था। यदि हम हमारी उस बहन के लिए पूरे प्रदेश के अंदर 8 women hostel बनाने की कल्पना करते हैं तो आप देखिये कि यह हमारी दूरदृष्टि की सोच है। (मेजों की थपथपाहट) यदि हम शहर के अंदर बायपास को

जोड़ने की बात करते हैं, यदि हम शहर के अंदर ब्लॉक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने की बात करते हैं और यदि हम हर ब्लॉक मुख्यालय के अंदर बायपास निकालने की बात करते हैं तो क्या यह हमारी दूरदृष्टि नहीं है ? आप सोचिये कि जब रोड बनती है तो कनेक्टिविटी अच्छी होती है और जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो गांव का आदमी शहर तक पहुंचता है और शहर का आदमी गांव तक पहुंचता है। उसको अपनी फसल को ले जाने में भी सुविधा प्राप्त होती है। यह हमारा विजन है और विकास की सोच है। मैं बात करता हूं कि पेट्रोल के मूल्य में 1 रूपये की छूट देना क्या कोई छोटी-मोटी बात है ? इस 1 रूपये की छूट का लाभ किसको नहीं मिलेगा ? यदि उधर वाले सदस्य कहेंगे कि हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा तो आप ही इसका लाभ लेंगे। आप लिखकर दे दीजिए कि हमें इसका लाभ नहीं चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर भैया हा बहुत अच्छा भाषण देत हे तो ओखर भाषण से मोला याद आत हे कि जब दिल्ली में यू.पी.ए. के सरकार रीहिस हे, ओ समय 35 रूपये रीहिस हे। ओ समय 35 रूपया लीटर रहिस ए तो आपे भाषण दे रहा कि ये प्रदेश में 35 रूपया लीटर पेट्रोल कैसे होगा, हमको बैठाओ, हम इसको तुरन्त कम करेंगे। एक रूपया कम हो गय हे तो कैसना हे कि हमर गांव मा हाथी आवय अउ महावत ला एक सूपा धान ला देवन अउ हमरे आघू मा एक मूठा छीच के बाकी ला धर के भाग जाय, तैसने तुमन आ।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यादव जी मैंने उस बैलगाड़ी की कहानी सुनी है। बैलगाड़ी वजन लेकर चलता है और उसके नीचे कई लोग चलते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे भरोसे बैलगाड़ी चल रही है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में हमारी सरकार थी तो पेट्रोल का रेट..।

श्री राजेश मूणत :- थी, लेकिन अभी 15 साल डॉ. रमन सिंह की सरकार थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं, मैं अभी आपको बता रही हूं, आपके संज्ञान में ला रही हूं।

श्री राजेश मूणत :- जरूरत नहीं है। हो गया, 15 साल बेमिसाल।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र में हमारी सरकार थी तो पेट्रोल का रेट 70 रूपये लीटर था। लेकिन आज 103-104 रूपया लीटर हो गया है। अगर 103-104 रूपये लीटर रेट में 1 रूपया कम करते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ? और ज्यादा कम कीजिये न।

श्री राजेश मूणत :- सही बात है। राजीव गांधी बोलकर गये कि मैं 1 रूपया भेजता हूं तो 85 पैसा गायब हो जाता है, 15 पैसा ही पहुंचता है। सही बोलते थे। कांग्रेस पार्टी ने यही काम तो किया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप रेट बढ़ा दिए हो, 70 रूपये से 100 रूपये तक ले गये हो और उसमें 1 रूपया कम कर रहे हो तो आप जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, आपका भी अवसर आयेगा, आपकी पार्टी वाले ने आपका नाम नहीं दिया है तो अब मैं क्या करू ? अगर आपकी पार्टी का नाम दे और आपका कुछ विषय हो तो मैं आग्रह करूंगा कि आपका नाम भी दे दें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नाम है। आप बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- है न, बस तो फिर आप खुलकर बोलना और दिल पर हाथ रखकर बोलना। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- कहूंगी।

श्री राजेश मूणत :- फिर आप घोषणा करना कि मेरे क्षेत्र के लिए महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- लूंगी।

श्री राजेश मूणत :- आप मत लेना, आप कांग्रेस के नवजवान मित्र घोषणा करो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप पोर्टल खुलवाईये, हम और नाम जुड़वायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप continue करिये।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि 1 रूपये की कटौती की है। वहीं बहुत से छोटे व्यापारी कई साल से परेशान हैं। छोटी-मोटी कमी होने के कारण, उनके आपस में संवाद होने के कारण ऐसे कई प्रकरण हैं, जिनके कारण व्यापारीगण हमेशा चक्कर लगाते रहते थे। उसका समाधान करने के लिए 25 हजार से कम रूपये के प्रकरण, जो 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनको माफ किया जायेगा, यह भी छोटी राहत उन व्यापारियों को दिया गया है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बस्तर शिल्प की बात करते हैं। हम बस्तर के कला और संस्कृति की बात करते हैं। पूरे देश के अंदर बस्तर के शिल्प हैं। बेल मेटल से बनने वाली कई चीजें, अगर नया रायपुर के अंदर NIPT जैसी संस्था लाकर छत्तीसगढ़ के अंदर जो कुम्हार जैसा काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर पिरामिड जैसा काम करते हैं, ऐसे कई लोगों के लिए अगर NIPT जैसी संस्था ला रहे हैं, तो मैं भी उसका स्वागत और अभिनन्दन करता हूं कि आपने बहुत दूरदृष्टि के साथ इस पर विचार किया।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के अंदर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यादव महाराज, यह आपके लिए है। छोटी-छोटी चीजों को गांव के अंदर यादव समाज, जो गांव-गांव में डेयरी का काम करते हैं, उस दूध का संग्रहण करने के काम के लिए, बड़ी डेयरी के लिए national dairy के

साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसके लिए 90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। मैं इसका स्वागत और अभिनन्दन करता हूं।(मेजों की थपथपाहट)

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आयुष्मान योजना के तहत 77 लाख 20 हजार परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसे ही वित्त मंत्री जी ने कई sectors में रायपुर शहर के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 बिस्तर अस्पताल दिया है, मैं उसका भी स्वागत और अभिनन्दन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर के विकास में पहली बार मेकाहारा के अदंर हो जितनी सुविधाएं दी हैं, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप भी बोले तो मित्र रायपुर के 5 साल का इतिहास भी निकाल लेना कि पिछले 5 साल के भीतर रायपुर के भीतर स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करने के लिए पूर्व सरकार ने कितना पैसा दिया। यह राजधानी है और इस राजधानी के अंदर पूरे प्रदेश के लोग ईलाज कराने आते हैं, वहां के लिए आपने कैसा सौतेला व्यवहार किया था, जरा उसकी स्टडी भी कर लेना। जब अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो आप और हम बैठकर बात करेंगे। वहीं मैंने नर्सिंग कालेज के बारे में बात की है। पहले कुल 8 नर्सिंग कालेज थे, इस नये बजट में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, हमें जिस प्रकार से ट्रेनिंग स्टाफ चाहिए, जिस प्रकार से हमारी बहनें नर्सिंग कोर्स करती हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए उनके लिए सरकारी कॉलेज खुल जाये, इसके लिए हम इस बजट में 12 कॉलेज का प्रावधान करके उन बहनों को ट्रेनिंग देने के साथ में नर्सिंग कॉलेज बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, मैं इसका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह बात कहना चाहूंगा कि कभी रायपुर में सिंगल फिजियोथेरेपी कॉलेज हुआ करता था। अगर 6 नये फिजियोथेरेपी कॉलेज खोल रहे हैं तो यह सोचिए स्वास्थ्य सेक्टर में सरकार कितना बड़ा छलांग लगाने जा रही है। उसके अंदर आपको, मुझको और सबको जरूरत पड़ती है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ का पट्टा चढ़ गया है या पांव मुड़ गया है तो उसको फिजियोथेरेपी सेंटर जाना पड़ता है। अगर यह फिजियोथेरेपी कॉलेज खुलने पर गांव के अंदर सुविधा मिल जाएगी, शहर में सुविधा मिल जाएगी तो इस सरकारी नेटवर्क को एक बहुत बड़ा लाभ है और इसका सबको लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से कहा। यहां वाकई में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दो चीजों के ऊपर ध्यान भी दिलाऊंगा और आपकी तारीफ करूंगा कि आपने एक साल के अंदर काम खड़ा करके दिखाया। पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश के विकास के काम की गति बढ़ी है। अगर बायपास रोड बनती है, अगर शहर के गांवों को जोड़ने की प्रगति खड़ी होती है, अगर नेशनल हाईवे के अंदर 20 हजार करोड़ के काम स्वीकृत होते हैं, रायपुर में तीन-तीन फ्लाईओव्हर स्वीकृत होते हैं, आपने बजट में रायपुर शहर के अंदर जो अन्य फ्लाईओव्हर दिया है, इसको छोड़ कर आपने ब्लॉक मुख्यालय और जिला

मुख्यालय जोड़ने की योजना लेकर आया है, यह दूरदृष्टि सोच है। मैं इसकी तारीफ करूंगा। मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूं। जब मैं वर्ष 2018 के अंदर पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री था, उस समय एस.डी.पी. का प्रोजेक्ट था, एस.डी.पी. प्रोजेक्टर के अंतर्गत लगभग 8000 किलोमीटर का काम करना था। एस.डी.पी. प्रोजेक्ट बना दिया गया। उसकी डी.पी.आर. बनती है और डी.पी.आर. स्वीकृत होकर वहीं से आती है, उसी के आधार पर काम होता है और उस काम के अंदर जो कुछ हुआ है, उसको मैं सिर्फ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 10 मीटर की रोड को 16 मीटर की रोड बना दिया। बिना Approval के, बिना डी.पी.आर. संशोधन किए कहां रोड बनी? पाटन में रोड बनी। यह काम नियमों को ताक पर रख कर किया गया। यह नियम Already एस.डी.पी. के Norms में हैं कि यदि रोड का चौड़ीकरण करना है तो उसका Traffic analysis होगा। कितनी एम.एस.ए. की रोड बनेगी, उसके लिए नियम में स्पष्ट है। उन सब नियमों को ताक पर रख कर जिस प्रकार से पैसे की [xx] और बर्बादी हुई है। अगर एस.डी.पी. की 14 जगह और रोड बनती है, पैसा खत्म कर दिया। मैंने उस समय एक निर्णय किया था, वह निर्णय में यह नियम था कि डी.पी.आर. को चेक कर लें और डी.पी.आर. को चेक करने के बाद में टेंडर डालना है और यदि ठेकेदार 10 प्रतिशत से ज्यादा violation डालेगा तो उसको उसकी Approval नहीं मिलेगी। 35 से 40 प्रतिशत violation है। अधा बांटे रेवड़ी, चुन-चुन के दे। आपके यहां भी रोड बनती है। जब आपके यहां सरकार थी तब आपके यहां भी रोड बनती थी, लेकिन सबको किनारे करके सिर्फ वहीं तक सीमित रह गये। इसलिए मैं वित्त विभाग के अंदर बजट में चर्चा कर रहा हूं तो जिन लोगों ने यह वित्तीय अनियमितता की है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और यह भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना करें, यह भी चिंता करनी चाहिए, यह मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर ऐसी कई चीजे हैं। सरकारी कर्मचारियों का फंड है। इसके पहले पेंशन फंड कभी नहीं हुआ था। यह न किसी ने कल्पना की, न कभी कोई सोचा है कि सरकारी कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण निपटाने में कितनी तकलीफें होती हैं और कई बार उनको पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए रिजर्व फंड सुरक्षित करना और इसके लिए जो काम किया गया है, उसके लिए मैं पूरे कर्मचारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मैं टॉवर की बात भी बताना चाहता हूं। आप लोग टॉवर का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आप लोगों ने कभी ऑनलाईन काम किया ही नहीं हैं। आप लोग हर चीज ऑफलाईन करना चाहते हैं। जैसे पहले हमारी सरकार के अंदर खनिज की ऑनलाईन Permission मिलती थी, वह आपको पसंद नहीं थी तो आपने कहा कि वह ऑफलाईन कर दीजिये। कलेक्टर को जाओ, नमस्ते करो, उसको बोल कर आओ, करने के बाद में वह पूछेगा कि Permission दूं या नहीं दूं, वह कहेगा ओके। उसके बाद वहां साईन करोगे, अगर वहां कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, अगर पंचायत हो या नीचे हो, कनेक्टिविटी टॉवर लगने से गांवों के अंदर कनेक्टिविटी होगी, सरकार की योजना का पूरा का पूरा लाभांश चाहे वह

किसानों के खाते में हो, चाहे वह मजदूर के खाते में हो, चाहे वह व्यापारियों का मामला हो, अगर वहां नेट अच्छा चलेगा और उसके यहां डायरेक्ट पैसा चला जायेगा तो बिचौलिये का क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न वही है और इसीलिये टॉवर का विरोध करो ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मोर एक ठन निवेदन हे कि टॉवर लगाथव त बीएसएनएल के लगाववं । आप मन पहली फ्री में सिम ला बांटथव, डाटा फ्री, सिम फ्री, बाद में तहां बिल देथव । अइसन झन करिहव । BSNL ला बढ़ाववं, सरकारी संस्था ला बढ़ाववं । आपसे अइसन निवेदन हे ।

श्री राजेश मूणत :- आप सुझाव अपने भाषण में देना । अच्छा सुझाव हे, तैं भाषण में अऊ भी सुझाव दे, स्वीकार हे । हमर वित्त मंत्री जी समझदार हे । तहुं गांव के आदमी, वहु गांव के आदमी । दूनों भाखा समझथे ।

अध्यक्ष महोदय :- कितना समय लेंगे ?

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस बात को इसलिये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करते हैं, हम लोगों ने नारे सुने हैं कि रायपुर में मेट्रो चलेगा और चलाने वाले चले गये, न ही डीपीआर बनी और न सर्वे हुआ, एक महापौर तो विदेश घूमकर आ गये ? अध्यक्ष महोदय, न उनका निमंत्रण, न मंत्रालय में निमंत्रण, बिना निमंत्रण के बोल दिये मैं गया था, वहां बातचीत हुई है, रायपुर के मेट्रो का सर्वे होगा । अध्यक्ष महोदय, सर्वे कौन करेगा, कौन सी एजेंसी करेगी, यह कहते हैं कि एम.ओ.यू. कर लेंगे ? अध्यक्ष महोदय, एम.ओ.यू. राज्य सरकार करेगा कि नगर निगम करेगी ? यह आश्चर्यजनक है, आप निजी यात्रा में गये और सुर्खियॉ बंटोरने का काम कर दिया कि हॉ हमारा कमिटमेंट है ? अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को संवारने की जिम्मेदारी हमने ली है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने जो मेंडेट दिया है, यह तीन चक्के की सरकार शानदार सॉय-सॉय काम करेगी, वह काम हम करके दिखायेंगे । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आज जितना पैसा नगरीय प्रशासन विभाग के लिये दिया गया है, एक भाई बोल रहा था तन्ख्वाह बांटने के बारे में जिक्र कर रहे थे, आप पांच साल थे तो क्या किये, आय के स्त्रोत क्यों निर्मित नहीं होने दिये ? अध्यक्ष महोदय, आपने चिंता नहीं की है, आपने शहर को संवारने का काम नहीं किया है, आपने सिर्फ जमीनों के ऊपर खेल खेलने का काम किया है और जितनी जमीन आपके कार्यकाल में बिकी है,यह इतिहास के पन्नों पर लिखा जायेगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जमीन के नाम पर जितने कॉलोनाईजर, जितने बडे नेताओं के घरों के पास की सरकारी जमीनें, उस समय जो कलेक्टर गाईड लाईन के आधार पर जो बेचे हो, यह भी एक इतिहास में लिखने वाला काम है । अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आपने नगरीय प्रशासन विभाग के नाते नगर के अंदर व्यवस्था नहीं सुधारी है, आपने उनके आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिये कोई काम

नहीं किया है, आप शहर का डेवलपमेंट कैसे करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, चाहे वह नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, सेल्फ खड़ा करना हम आप सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये जनता ने जो बहुमत दिया था, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, हमारी राजधानी का बहुत अचछा काम हुआ है, 800 करोड़ रूपये स्मार्ट सिटी के खर्च हुये हैं ? अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त मंत्री जी ने मेरे भाषण और ध्यानाकर्षण में कहा था कि उन लोगों ने जिन्होंने गलत किया, मैं उनका जरूर जांच करा दूंगा । अध्यक्ष महोदय, माननीय अरूण जी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी है, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वह दोनों है, वाकई में रायपुर का इतिहास लिखने वाला है ? अध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या में 800 करोड़ रूपये खर्च हो गये, शहर का कोई एक वार्ड नहीं है, मित्रवर यह हमारे कार्यकाल का नहीं है, यह आपके कार्यकाल का है । आप लोगों ने जिस महापौर के कार्यकाल में रायपुर को स्वर्ग बनाया, जहां आपने गुलाब की पंखुडियां बिछाकर अपने राष्ट्रीय नेता का अभिनंदन किया,वही महापौर का आपने चुनाव में फोटो लगाना उचित नहीं समझा और उसी महापौर के कार्यकाल का पानी का भी रिजल्ट है और इसी महापौर के कार्यकाल का स्मार्ट सिटी का भी रिजल्ट है । चिन्ता का विषय यह है और इसीलिए मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं । मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने दूर दृष्टि रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से गृह विभाग के अंतर्गत अलग से फोर्स बनाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा । यह बहुत अच्छा काम है, एक नई पहल हुई है । उसी प्रकार से आपने रायपुर में ही नहीं, इस प्रदेश में फायर स्टेशन बनाने का काम है । आज की स्थिति में रायपुर के अंदर कहीं पर आग लगती है तो हम भिलाई की ओर मुंह ताकते हैं । अलग-अलग सेक्टरों के लिए आपने काम किया है, यह दूर दृष्टि है, एक सोच है और आपने इसको मूर्त रूप देने का काम किया है, मैं इसका अभिनंदन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी, आपने पत्रकार साथियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बिन मांगे मुराद पूरी की । उप मुख्यमंत्री अरूण साव जी बैठे हुए हैं, अभी सदन में मुख्यमंत्री जी नहीं हैं । एक उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक फर्जी केस चल रहे हैं, वे गृह मंत्री जी भी हैं । जरा एक बार उनकी भी विवेचना करके पूर्व सरकार ने फर्जी केस बनाए थे, उनसे भी उनको मुक्ति दिला दें, ताकि इस चीज से उनको भी राहत मिल जाये । राजनीति में राग-द्वेष की भावना से जो काम करेगा, वह ज्यादा पनप नहीं सकता । ऊपर वाला सब देखता है ।

श्री रामकुमार यादव :- इही ला तो तुमन ला समझना हे, महाज्ञानी हो ।

श्री राजेश मूणत :- हम तो समझे समझाए हैं । मैं तो पूरा समझा हुआ हूं । जो नहीं समझ सके, उनको समझा । उनको समझा मेरे भाई, वे अभी भी चक्कर काट रहे हैं । मेरे को नहीं समझना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं और वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं । मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं । मैं एक चीज समझना भी चाहता हूं । हम लोगों ने छत्तीसगढ़ मेडिकल कारपोरेशन खड़ा किया है, वह आजकल सब काम कर रहा है। वह मेडिकल कॉलेज भी बनाएगा, पीएचसी भी बनाएगी, दवा खरीदी भी करेगी । दवा खरीदी में पूर्व सरकार का इतना ज्यादा कारनामा है, जब एम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट रायपुर में है और एम्स में प्रधान मंत्री जन औषधि योजना की दवाई चलती है तो क्यों न छत्तीसगढ़ के हर अस्पताल में उस दवाई का उपयोग कर लें, यह मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं । पूर्व सरकार ने जैम पोर्टल के माध्यम से दवा खरीदती थी, क्योंकि आपने भी जैम पोर्टल से खरीदी करने की घोषणा कर दी है, जैम पोर्टल में तो पूर्व सरकार ने [xx] करके रखी थी । अब मैं उस सरकार के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाना भी नहीं चाहता क्योंकि उन्हें जनता ने सांय-सांय निपटा दिया। यह जो बजट आया है, वह जनोपयोग, जनहितैषी, दूर दृष्टि, पक्का इरादा वाला, कल्पना को साकार बजट है । एक गांव, किसान, महतारी का बेटा विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में अगर यह बजट लेकर आता है, पूर्ण आशा और विश्वास के साथ जब छत्तीसगढ़ राज्य 2047 में पहुंचेगा, जब हम 25 साल बाद रजत जयंती मनाएंगे तो हमें गर्व होगा कि मेरा छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है । मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा पर अपनी बात रखना चाहता हूं । मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण पढ़ा, सुना भी । हम तो जमीनी स्तर के आदमी हैं, जो हम देखते हैं, वही यहां पर हम बोलेंगे । आपने बड़ी-बड़ी योजना की बात की जैसे उड़ान योजना, ऊर्जा से सरप्लस राज्य, अटल मानीटरिंग पोर्टल, सुगम एप्स, आदर्श कुशासन फैलोशिप, मुख्यमंत्री हेल्प लाईन, प्रधानमंत्री अन्नदाता, आय संरक्षण कृषक समग्र विकास योजना । बहुत सारी योजना सहित आपने बजट में नया आयाम देने की बात की है। हमारे क्षेत्र में और राज्य में हम विशुद्ध रूप से किसान हैं और हमारा पूरा राज्य, हमारे प्रदेश में विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति, परम्परा, रीति-रिवाज, धर्म के मानने वाले लोग हैं । हमारे प्रदेश में आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लोग निवासरत हैं, हम उनके लिए क्या सोचते हैं और धरातल पर उतारने का हमारा प्रयास क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे किसानों ने जो धान बेचा है, उसका पैसा वर्ष 2020-21 का कम से कम 19 करोड़ 97 लाख 56 हजार रुपए आप नहीं दे पा रहे हैं। वर्ष 2021-22 का आप 14 करोड़, 59 लाख 12 हजार रुपए नहीं दे पा रहे हैं। किसान जो धान बेचे हैं, आप उसकी समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी-बड़ी योजना बनाने से कुछ नहीं होता, बड़े-बड़े हेडलाईन करने से कुछ नहीं होता। आप समीक्षा कीजिए। आपने किसानों का धान भी खरीद लिया है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल):- दलेश्वर भाई, ये पिछली सरकार का है या किधर का है?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, हमने तो गलती कर ली, आप भी गलती करना चाह रहे हो? आप क्यों नहीं देते, आप सहानुभूतिपूर्वक विचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खाली बड़े-बड़े नाम करने से होगा क्या? वर्ष 2022-23 का 16 करोड़ 59 हजार रुपए आप नहीं दे पा रहे हैं और वर्ष 2024-25 का आपकी सरकार का तो 31 करोड़ 19 लाख 18 हजार अभी लंबित है। इस प्रकार 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 का लंबित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि किसान प्रकृति से जूझता है। वह प्रकृति के साथ पूरा जुँआ खेला रहता है। बिगड़े मौसम, ओला वृष्टि, बेमौसम बारिश से हानि में आपने किसानों को फसल बीमा योजना में 44 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, पर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आप पर 21 करोड़ 45 लाख 62 हजार रुपए किसानों का बकाया है, फिर इस पर समीक्षा क्यों नहीं करते? बड़ी-बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं राजनांदगांव जिले की बात कर रहा हूं, जहॉ आप भी रहते हैं। राजनांदगांव में रबी फसल के लिए 6 हजार मीट्रिक टन यूरिया की जरुरत है लेकिन आप 2558 मीट्रिक टन दे पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वित्त मंत्री जी, आप बहुत लंबा बैठ गए, चाहे तो चाय पीकर आ सकते हैं। पीकर आ जाइए।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले में 6 हजार मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड पर किसान को आप 2558 मीट्रिक टन दे पा रहे हैं और किसान भटक रहे हैं, व्यापारियों के पास जा रहे हैं। आपके पास यूरिया की समीक्षा करने के लिए समय नहीं है। डी.ए.पी. 3100 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, पर आप 1497 मीट्रिक टन ही दे पाए हैं। किसान रबी फसल के लिए भटक रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने उर्जा सरप्लस और विद्युत विभाग की बात की है। मैं कहता हूं कि आपने बजट 25 प्रतिशत घटाया है। मैं मेरे ही राजनांदगांव जिले का उदाहरण देता हूं कि एक आर.डी.एस. है, जिसमें 180 करोड़ रुपए का बजट है। यह कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने राजनांदगांव में इसकी समीक्षा भी की थी। आपने ठेकेदार को बुलवाया था। आप उसकी समीक्षा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके ठेकेदार यहां पर क्या कर रहे हैं। आपकी सरकार है। इसमें 8 घटकों में 180 करोड़ रुपए खर्च करना है, जिसमें feeder segregation 72 नग बन जाना चाहिए था और आपके पास मात्र 3 महीने बचे हैं और आप मात्र 7 ही बना पाए हैं। तीन महीने में आप क्या कर लेंगे? उसका पूरा कार्यकाल बीत गया और आप मात्र 07 बनाये हैं। feeder vibration 42 नग बनना है और आप 19 नग ही बना पाए हैं। आपको 11 KV लाईन 1500 किलोमीटर बिछाना है और आप सिर्फ 18 किलोमीटर ही बना पाए हैं। 11 KV line distribution transformers आपको 1524 नग

लगाने थे और आप सिर्फ 11 लगा पाये हैं, तो क्यों वोल्टेज प्राब्लम नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि यह सिर्फ राजनांदगांव का फिगर है, अगर आप अपने पूरे इलाके के आर.डी.एस. की समीक्षा करेंगे, तो कितने करोड़ हो जाएगा जबकि 180 करोड़ सिर्फ राजनांदगांव का है। यदि आप पूरे जिला का करेंगे, उसके लिये आपके पास पैसा भी है परंतु आप समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एल.टी. लाइन 7,093 कि.मी. बिछानी है, जिसमें से आपने अभी सिर्फ 5 कि.मी बिछायी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एकदम ऑथेंटिक बात कर रहा हूं। एल.वी. केबल का 78 किलोमीटर का कार्य करना है, जिसमें आपने केवल 14 किलोमीटर का कार्य किया है। कंडक्टर से 150 किलोमीटर का ए.सी.बी. केबल बदलना है, जिसमें आपने केवल 2 किलोमीटर का कार्य किया है। 758 नग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बदलना है, जिसमें से आपने केवल 45 नग ही बना पाया है। आप 180 करोड़ के बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप बजट में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो हमारे जैसे इंसान को समझ में नहीं आती। आपको 21,450 कि.मी. की सर्विस केबल बदलनी है, जिसमें से आपने केवल 1,500 कि.मी. की केबल ही बदल पायी है और जिसके लिए आपके पास केवल 3 महीने का समय बचा है। इसके लिये 24 माह का समय था, जो दिनांक 26.07.2025 को खत्म होने वाला है। आपने सिर्फ 7 प्रतिशत प्रोग्रेस किया है, आप कार्य को 100 प्रतिशत कैसे ले जायेंगे ? अब यदि आप ऐसे ठेकेदारों से काम करायेंगे तो वोल्टेज प्रॉब्लम, विद्युत कटौती होगी। किसान भटक रहे हैं और किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। आप न किसानों को खाद दे पा रहे हैं, न ही बिजली के पैसे का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वह भी आप नहीं कर पा रहे है। ओलावृष्टि से और बेमौसम बरसात से जो किसान परेशान हैं, उसके लिए उनका जो मुआवजा स्वीकृत है, आप उसे तक नहीं दे पा रहे हैं। आप किसानों के हित के लिये क्या सोच रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, इन्हें सिर्फ समीक्षा करने की जरूरत है। आप सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं, जो किसी किसान के समझ में नहीं आती है। ऐसी योजनाएं बनाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप धरातल पर उतरिये।

अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों के लिए पंप की बात की। हमने उसके लिए 1 लाख रूपये सब्सिडी भी दी। हमने ठेका भी दिया। परंतु आपके जो ठेकेदार हैं, आपने इन कार्यों के लिए उनको 24 माह का समय दिया था, उसके बाद भी आप किसानों के पंप नहीं लगा पाये। फिर से दूसरा साल हो गया। आपको उस पर समीक्षा करनी चाहिए। पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 12,633 पंप लगाने का लक्ष्य था, जिसमें से अभी 2,678 पंप लगाने बचे हैं। आप किसानों के हित में काम करते हैं और बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑथेंटिक बातें कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रधानमंत्री आवास के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिये यह काम कर रहे हैं, वह काम कर रहे हैं। आप 200 करोड़ 34 लाख 47 हजार रूपये का शेष भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास न केंद्रांश आया है, न ही राज्यांश आया है। जब

आप पैसा ही नहीं देंगे तो कार्य कैसे पूरा होगा ? यह फिगर 2025 के बजट सत्र का है। यदि हम जुलाई, 2024 और दिसंबर, 2024 के फिगर में जायेंगे, तो वह अलग फिगर आयेगा। यह ताजा आंकड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मनरेगा में श्रमिकों के भुगतान के बारे में बोलना चाहूंगा। आप मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिकों का 200 करोड़ 76 लाख 99 हजार रूपये की लंबित राशि नहीं दे पाये हैं। आपको 676 करोड़ 58 लाख रूपये देना बाकी है, जिसमें न आपका राज्यांश आया है और न ही केंद्रांश की राशि आयी है। आप गरीबों की बात करते हैं और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करते हैं। जो लोग काम किये हैं, उनका तो पैसा दे दीजिये, बाकी के अन्य विषय बाद में सोचियेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हें सिर्फ समीक्षा करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं वनवासी लोगों के वनाधिकार पट्टा के विषय में बोलना चाहूंगा। व्यक्तिगत अधिकार के 5,879 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। आप क्या करने जा रहे हैं ? सामुदायिक वनाधिकार के 91 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। वनवासियों के हित में निर्णय हुआ है, आप उनके अधिकार की बात करते हैं तो इतने प्रकरण क्यों प्रक्रियाधीन हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। प्रदेश में 1 हजार 114 हत्याएं हुई हैं, यहां लूट की घटना 498, अपहरण की घटना 3644, चोरी की घटना 7960, डकैती की घटना 3191, बलत्कार, 24 जुलाई से नवम्बर 2024 की स्थिति में सामग्री चोरी की घटना 3522, दुष्कर्म की घटना 1 हजार 30, महिला उत्पीड़न की घटना 627, महिलाओं की तस्करी की घटना 1, ठगी की घटना 780, नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की घटना 79, नशीले पदार्थों की तस्करी 316, अपहरण की घटना 1444, हत्या के प्रयास की घटना 324, सड़क दुर्घटनाएं 6402, प्रदेश में गोलीबारी की घटना 06 है, गैंगवार, बलवा की घटना 400 घटित हुई हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में मात्र यह घटनाएं घटित हुई हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप सदन में यह कौन से आंकड़े रख रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री दलेश्वर साहू :- आप प्रश्नोत्तरी पढ़िये। यह आपने ही जवाब दिया है। इसे मैंने नहीं दिया है।

श्री रामकुमार यादव :- आप लोगों ने जो जानकारी दी है उसी को बता रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- आप कौन से विषय में आप अपनी बात कह रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग के बारे में बात कह रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- यह मात्र है।

श्री दलेश्वर साहू :- यह आपका ही जवाब है, यह मेरा जवाब नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- भईया, यह विनियोग पर चर्चा नहीं हो रही है। अभी बजट में चर्चा हो रही है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। अगर बजट में चर्चा हो रही है।

श्री राजेश मूणत :- भईया, आप मेरी बात तो सुनिए। आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य है। अगर बजट में कोई कमी बेसी है तो यहां पर उसको बताएं। जब आप उस विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगे तो आप यह आंकड़े गिनाना कि प्रदेश में इतने काण्ड हुए और वह हुआ। यह तो विनियोग में गिनाया जाता है।

श्री रामकुमार यादव :- भाई, हम जिन्दा रहेंगे तब तो। हम बजट में क्या करेंगे?

श्री दलेश्वर साहू :- जब आप बोल रहे थे तो हम आपकी बात सुन रहे थे। जब हम प्रमाणिक बातें कह रहे हैं तो आपको पीड़ा हो रही है। पुलिस कर्मियों के पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति नहीं कर पा रहे हो। हम तो इन बातों को कहेंगे। हमें यहां सदन में बोलने का मौका मिला है। आप वर्ष 2021 में 18 लंबित अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। वर्ष 2022 में 35, वर्ष 2023 में 79 ...।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय दलेश्वर भाई, वर्ष 2020, वर्ष 2020-2021 और वर्ष 2022 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्हें पिछला कुछ है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, मैं वर्ष 2024 तक आ रहा हूँ। आप वर्ष 2024 तक का सुनिये। यह वर्ष 2023 में 79 और वर्ष 2024 में 77 है। आप उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए। उस समय हमसे चूक हो गई तो आप लोग भी चूक करेंगे क्या ? फिर यहां पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें क्यों कहते हैं? हम आपको ज्ञान देने की बात कह रहे हैं और आप समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष का संदिग्धों के संबंध में सत्यापन की कार्यवाही पर बताना चाहूंगा। रायपुर में 244 संदिग्ध व्यक्ति हैं। आपके राजनांदगांव जिले में 209 संदिग्ध व्यक्ति हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय दलेश्वर भाई, यह आंकड़े कहां के हैं ?

श्री दलेश्वर साहू :- आप ही लोग यह आंकड़ें देते हैं।

श्री राजेश मूणत :- जब आपने लिखा होगा। नहीं-नहीं, अगर आपको यह आंकड़े सरकार की तरफ से मिले हैं या आपको प्रश्नोत्तरी के उत्तर में मिले हैं या आपको किसी ने उपलब्ध करवाया है ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसे अपने मन से बना लिया है। आप इसकी जांच करवा लीजिए अगर एक भी आंकड़ा गलत होगा तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। मैं इस विधान सभा में आना बंद कर दूंगा, अगर इसमें एक भी आंकड़ा गलत होगा। हम अध्ययन करते हैं। हम तो भाषण नहीं करते हैं हम तो आंकड़ों में बात करते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मूणत जी, माननीय मंत्री जी ने यह आंकड़ा दिया है। यदि आप उसको भी नहीं मानेंगे तो जाओ, हमने इसे माननीय अजय चन्द्राकर जी की जेब से निकाला है।

श्री राजेश मूणत :- भाई, वह मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। वह मेरे बहुत अच्छे सहयोगी हैं। इस सदन के वह जागरूक विधायक हैं। कभी-कभी उनका सहयोग भी कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात जल्दी खत्म करें।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कबीरधाम तक आया था। कबीरधाम में 262, बस्तर में 181, दुर्ग में 148, मोहला मानपुर में 41, कोण्डागांव का 40 कुल योग 1131 हैं आपके पुलिस विभाग ने इनको संदिग्ध व्यक्तियों के रूप में पाया है और आपने उसका सत्यापन भी किया है कि प्रदेश में इतने संदिग्ध व्यक्ति हैं। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ। यह आपके जवाब में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा पर अपनी बात कहना चाहूंगा। इस प्रदेश में राजस्व प्रकरण लंबित हैं। इसमें भी मैं आंकड़ों से बात करूंगा। मैं कोई भी भाषणबाजी वाला काम नहीं करता हूँ। आपके राजस्व विभाग में 1 लाख 53 हजार 258 मामले लंबित हैं, जिनका आप निराकरण नहीं कर पा रहे हो। अगर यह आंकड़े भी गलत होंगे तो मैं इस विधान सभा में आना छोड़ दूंगा। आप इसे नोट कर लीजिए। मेरे आंकड़ें कार्यवाही में नोट हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग में कहना चाहूंगा कि प्रदेश में शिक्षकविहीन 337 प्राथमिक पाठशाला हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिए आपने क्या कार्ययोजना बनाई है? आप 4 स्कूल खोलकर बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। आपके 337 प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक नहीं हैं।

श्री राजेश मूणत :- डोगरगांव में कितने नहीं हैं?

श्री दलेश्वर साहू :- मैं वह भी बताऊंगा। जब विभागीय चर्चा होगी तो उस पर भी चर्चा करूंगा। मैं यह प्रदेश के फिगर की बात कर रहा हूं। एकल शिक्षकीय शाला, 4822 स्कूलों में खाली एक ही गुरूजी हैं। क्या उनके बारे में आपके पास कोई कार्ययोजना है, क्या उसके लिए आपके बजट में कुछ सम्मिलित है ? राज्य में 24,636 सहायक शिक्षकों की कमी, 13,024 प्रधान पाठकों की कमी, 2856 व्याख्याता के पद रिक्त, माध्यमिक शाला में शिक्षक के 3200 पद रिक्त हैं। अब मैं स्कूलों के जर्जर भवन में आता हूं। आपने बजट में 2-4 भवन को ला दिया और बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 2737 स्कूल भवन बैठने लायक नहीं हैं। 782 प्राथमिक स्कूलों में भवन नहीं हैं, आप दो-चार स्कूलों को शामिल कर लिये। 947 पूर्व माध्यमिक शाला में भवन नहीं हैं। 947 स्कूल भवन जर्जर हैं और 255 मिडिल स्कूल के भवन ही नहीं हैं।

श्री राजेश मूणत :- आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दलेश्वर भाई, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हैं और आपका एकत्रीकरण भी बहुत अच्छा है। क्या यह सब एक साल में ही हुआ है ? वह जो बोल रहे हैं, यह सब क्या एक साल में ही हुआ है ? थोड़ा सा पुराना भी इतिहास देख लीजिए। दलेश्वर भाई, आप इतने सीनियर विधायक हो ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- भवन मिला था, वह भी वापस हो गया है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सैकडों की संख्या में कर लेते, चलिये, 200 स्कूलों के लिए नहीं है तो 50 स्कूलों के लिए बजट में प्रावधान कर लेते। तीन-चार प्राथमिक पाठलाशा का भवन बजट में सम्मिलित करके क्या आपने तीर मार लिया ? 100 या 50 स्कूलों के भवन के लिए बजट में सम्मिलित करते तो हम कहते कि आप 05 साल में कुछ कर लेंगे। आपका 01 साल तो खत्म हो गया है और यह भी साल खत्म हो गया, आप क्या कर लेंगे ? 29 हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर हैं और 167 हाईस्कूल भवनविहीन हैं। 76 हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर हैं और 93 हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन नहीं हैं। आप कितने भवन बजट में दो, तीन या चार दिये हैं ? आप अपने बजट में पढ़ लीजियेगा। आप क्या कर लेंगे ? आपके कार्यकाल का 02 साल तो निकल गया। यह एथेंटिक फिगर है, आपके ही विभाग द्वारा दिये उत्तर से हम निकाल कर रखे हैं।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, क्या एक सुझाव दूं ? यह सबके लिए सुझाव है। उसमें मैं भी हूं और नेता जी आप भी हैं। हम सबको 4 करोड़ रुपये विधायक निधि मिलती है। हम संकल्प लें कि जब से आखिरी दम तक एक-एक करोड़ रुपये स्कूल में देंगे, एक करोड़ रुपये आंगनबाड़ी में देंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हम कहां से देंगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग 4 करोड़ रुपये भी काट लेते हैं, हमको 4 करोड़ रुपये नहीं मिलता। हमारे शासनकाल में हम लोग आपको पूरा देते थे। .. (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से जो स्वीकृति है, उसको दिला दीजिए, हम लोग दे देते हैं।

श्री राजेश मूणत :- अगर डेव्हलपमेंट की चिंता है और इतनी बात कर रहे हैं कि एक साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रही हूं कि अगर आप 4 करोड़ रुपये देते हो तो हम 100 प्रतिशत दे देंगे, लेकिन हमको 4 करोड़ रुपये मिलते ही नहीं हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- राजेश भैया, जो 1 करोड़ रुपये 33 प्रतिशत ला बचा के रखे हो, वह दिला दीजिए, हम लोग देने का वादा करते हैं।

श्री राजेश मूणत :- मैं जो सुझाव दिया हूं, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि माननीय मंत्री लोगों को वह 33 प्रतिशत का सुझाव भी इधर दे दीजिए। .. (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- 4 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने किया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी सरकार आप लोगों को 4 करोड़ रुपये विधायक निधि दे रही थी लेकिन आप लोग नहीं देते।

श्री दिलीप लहरिया :- आप अभी तक कहां बढ़ाये हैं ? क्या आप 10 करोड़ रुपये कर रहे हैं ? वह तो 4 करोड़ रुपये हमारी सरकार की देन है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमारी सरकार ने विधायक निधि 2 से 4 करोड़ रुपये दिया, आप 4 से 8 करोड़ रुपये कर दीजिए।

श्री विक्रम मंडावी :- राजेश भैया, हम आपकी बातों को मानते हैं, हमारा डेढ़ करोड़ रुपये प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से होता है, वह दीजिए, हम दे देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम तैयार हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हम तैयार हैं।

श्री राजेश मूणत :- मैंने तो माननीय अध्यक्ष जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। मैंने राजनीति से ऊपर उठकर बात की है, मैंने यह नहीं कहा कि इनके क्षेत्र में या उनके क्षेत्र में जब वह दलेश्वर भाई पूरा पढ़ रहे थे कि मेरे यहां माध्यमिक नहीं है, इसमें इतने नहीं हैं, यहां आंगनबाड़ी नहीं है, यहां यह नहीं है तो मैंने एक बात कही न कि अगर हम लोग भी सहमत हो जाएं तो अपने आप सब ठीक हो जायेगा । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ठीक-ठीक । हम तैयार हैं । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- राजेश भैया इधर भी सहमति दे दीजिये । राजेश भैया आप मंत्री जी को इधर बोलिये कि विधायक निधि दिलवा देना । हम भी सहमति देते हैं । (व्यवधान) यदि आप लोग विधायक निधि से एक-एक करोड़ की राशि काट रहे हैं वह दे दें, हम आपको 1 करोड़ रूपये देने का वायदा करते हैं ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हां, हम वायदा करते हैं ।

श्री राजेश मूणत :- दीदी, एक मिनट । यह हम नहीं काट रहे हैं । आपकी पूर्व सरकार थी वह भी यही काम करती थी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमारी सरकार ने बिल्कुल नहीं काटा है, पूरा पैसा दिया है ।

श्री राजेश मूणत :- भाई मैं कह रहा हूं न, आप सुन तो लो । यह कोई आज व्वस्था नहीं बनी है जब से राज्य बना है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप 15 साल राज्य में थे । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आप सुन लें न, 25 प्रतिशत...। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बदले की भावना मत रखिए । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप 15 साल थे, 5 साल हमारी सरकार ने नहीं काटा है । आपकी सरकार है, आपने काटना चालू किया है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप 4 करोड़ दे दीजिये फिर हम आपको देंगे । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकों का सम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बढ़ाया था, 1 करोड़ था उसको 4 करोड़ किये हैं । आपकी तरफ से कोई है, क्या आज का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय - चलिये, दलेश्वर जी । आप अपनी बात रखें ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय - हो गया । आपको बाद में समय मिलेगा । अभी नहीं । दलेश्वर जी बात करें ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा कुपोषण पर भी आ जाता हूं । हमारी महिला बाल विकास मंत्री बहन जी बैठी हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जिसमें आना है आइए लेकिन बोलिए । रुकिए मत। (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश में कुपोषण की जानकारी बताना चाहूंगा । पूरे प्रदेश में लगभग 13 प्रतिशत कुपोषण है । बहिनी आप सुनत हओ ? मंत्री जी, सुनत रह । प्रदेश में 13 प्रतिशत कुपोषण के शिकार है जिनमें हमारे मुख्यमंत्री जी के इलाका में 18 प्रतिशत है । माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव जशपुर है न । जशपुर जिला में 18 प्रतिशत, दंतेवाड़ा में 23 प्रतिशत, सुकमा में 31 प्रतिशत और बाकी जगह सब 13 परसेंट है और योजना में व्यय कतेक करोड़ होत हे ? आप ओला देखओ और कम से कम तुलनात्मक अध्ययन करो कि पिछले समय...।

श्री राजेश मूणत :- वो कौन से राजनीति कुपोषण वाले हैं का ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननी अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बात है कि इस राज्य में बच्चे कितने कुपोषित हैं उसको आप बहुत हल्के में मत लीजिए बल्कि हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एक-तरफ देश का भविष्य चूंकि आज के बच्चे कल के नागरिक होंगे । उनके ऊपर विशेष काम किया जाए, यह मैं निवेदन करता हूं ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुपोषण की बात की है जो मुख्यमंत्री के इलाका में 18 प्रतिशत है और बाकी जगह 12 प्रतिशत है तो दीदी मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि तें कम से कम मुख्यमंत्री जी के इलाका ला तो संवार ले तो कम से कम हम वहां के बात करन कि मुख्यमंत्री जी के इलाका के जिला में कुपोषण कम से कम जीरो प्रतिशत या दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत कम होना चाहिए यह कितना दुर्भाग्य जनक घटना है और बार-बार हवाला देते हैं कि हमारे सांय-सांय में भांय-भांय हो रहा है, भांय-भांय में रांय-रांय हो रहा है और रांय-रांय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ईलाका कुपोषण का शिकार हो रहा है । इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और मैं आपको बता देता हूं कि ह actual figure है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त करिए । बहुत हो गया । आपने figure बहुत दे दिए, अभी और अवसर आएगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लक्ष्मण मस्तुरिया का एक गीत गाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप गीत गाइए न । गीत गाइए कोई दिक्कत नहीं है।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं यह भी कह रहा हूं कि यह मेरा नहीं है । वह सारे figure आपके थे और यह भी लक्ष्मण मस्तुरिया का था :-

लबरा धरे ईमान के झंडा
कोलिहा बाघ के भेष मा,
कुकर्मी रखवार यहां के राम-किशन के देश मा
गधहा कतको तन-मन रंग ले
का कपिला बन जाही रे
सच बात कही दूहूं तो यह बस्ती डर जा ही रे ।

माननीय अध्क्ष महोदय, मैं बने बात बोले के कोशिश करे हंओं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याँमबिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिछली सरकार में कह नहीं पाए थे इसलिए इस गाना को व्यक्त कर रहे हैं, यह इनके मन की भावना है ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु अवसर दिया इसके लिये मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- किरण जी कल करेंगे ?

श्री किरण देव :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(सायं 5 बजकर 25 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025 (फाल्गुन-14, शक संवत् 1946) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 04 मार्च, 2025